चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 30 नवंबर–06 दिसंबर, 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

पांचवीं बार नीतीश कुमार

यह नई राजनीति की शुरुआत है

बिहार में महा-गठबंधन सरकार के गठन के साथ ही एक नई राजनीति का सूत्रपात हो गया है. पूरे देश की नज़र बिहार सरकार पर टिक गई है और बिहार सरकार की नज़र राज्य के विकास पर. इस सरकार से राज्य की जनता को बहुत आशाएं हैं और भरोसा भी. अगर यह महा-गठबंधन सरकार बिहार को विकास की पटरी पर लाकर उसे देश में एक नए मॉडल के रूप में पेश करने में सफल होती है, तो देश की राजनीतिक दशा-दिशा पूरी तरह बदल जाएगी.

संतोष भारतीय

नीतीश कुमार पांचवीं बार मुख्यमंत्री बने. सबेरे से पूरा पटना शहर झंडियों से, झंडों से, बड़े-बड़े फोटोग्राफ्स से कुछ इस तरह भरा हुआ लग रहा था, मानों लग रहा हो कि यह समारोह कांग्रेस का है. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की खुशी जितनी ज़्यादा लोगों में नहीं थी, उससे ज़्यादा खुशी कांग्रेस ने स्वयं को सालों बाद सत्ता में आने पर प्रकट की. पूरा शहर ऐसा लग रहा था, मानों कांग्रेस के सरकार बनाने की घोषणा कर रहा हो. और, शायद यही कांग्रेस का बेस्ट पार्ट है. उसे स्वयं को प्रचार की क्रीज में रखना तो कम से कम आता है और यही उसने पटना में किया. कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में आए. कांग्रेस के लगभग सारे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आए, चाहे वह कर्नाटक के रहे हों, असम के रहे हों या फिर हिमाचल के. कांग्रेस के वे सारे नेता पटना में नज़र आए, जो अब तक दुबके पड़े थे.

लालू यादव को अपने मंत्रियों को चुनने में परेशानी हुई होगी, क्योंकि दो लड़के तो उनके अपने घर में बेटों के रूप में हैं और कोई यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका कि किसी एक बेटे को मंत्री बना दीजिए, दूसरे को बाद में बना दीजिएगा अथवा दोनों बेटों को तीन या चार महीने के बाद मंत्री बना दीजिएगा. शायद घर के भीतर एक दूसरा युद्ध आरंभ हो जाता. लालू यादव के 80 विधायकों में से हर एक को आशा थी कि वह इस बार मंत्री बनेगा, लेकिन लालू यादव की मजबूरी यह थी कि उन्हें सिर्फ़ 16 पद मिलने थे. अब्दुल बारी सिद्दीकी को चौथे नंबर पर शपथ लेनी पड़ी, जबकि वह राजनीति में राजद में सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं. अगर उनके मुस्लिम होने को अनदेखा भी कर दें, तो जयप्रकाश आंदोलन से लेकर अब तक उनकी गंभीरता और साख उन्हें दूसरे नंबर पर शपथ लेने की योग्यता दर्शाती है, पर उन्हें चौथे नंबर पर शपथ लेनी पड़ी. पहले नंबर पर नीतीश कुमार, दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव और तीसरे नंबर पर लालू यादव के दूसरे पुत्र तेज प्रताप ने शपथ ली. लालू यादव की तरफ़ से 12 लोगों ने शपथ ली, जिनमें से दो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, बाकी सारे बिल्कुल नए हैं.

शायद यह लालू यादव की इच्छा न भी रही हो, मजबूरी रही हो, क्योंकि बेटों की एक अलग दुनिया बन जाती है और उस दुनिया में दोस्तों का दखल बहुत ज़्यादा हो जाता है. वैसे लालू यादव को पहले भी यह कहने में कोई संकोच नहीं था कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही होता है और उन्हें अपने दोनों बेटों को आगे बढ़ाना ही था. पहले लोगों का अंदाज़ था कि उनकी बेटी मीसा भारती उप-मुख्यमंत्री बनेंगी, पर अंततः लालू यादव ने तय किया कि उनके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव उप-मुख्यमंत्री बनें और उनकी बेटी मीसा राज्यसभा में जाएं. और, इन सारे क़दमों को लेकर राजद में किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है. ग़ौरतलब है कि राजद सत्ता में हिस्सेदारी करने लगभग दस सालों के बाद आया है.

नीतीश को अपने विधायकों में से सिर्फ़ 14 को मंत्री बनाना था. पहले नीतीश के साथ 36 मंत्री थे. इसलिए उन्हें निर्ममता से फ़ैसला लेना पड़ा कि वह किसे मंत्री बनाएंगे और किसे नहीं. इस क्रम में उनके सबसे खास लोग भी मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए. वे सारे खास लोग नाराज़ हैं. नीतीश कुमार को अपने साथियों को समझाने में दिक्कत अवश्य आई होगी.लेकिन मेरा इतना अंदाज़ ज़रूर है कि उन्होंने इस बार किसी को समझाया नहीं कि किसे मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है और किसे नहीं.

यही परेशानी नीतीश कुमार के सामने थी. नीतीश को अपने विधायकों में से सिर्फ़ 14 को मंत्री बनाना था. पहले नीतीश के साथ 36 मंत्री थे. इसलिए उन्हें निर्ममता से फ़ैसला लेना पड़ा कि वह किसे मंत्री बनाएंगे और किसे नहीं. इस क्रम में उनके सबसे खास लोग भी मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए. वे सारे खास लोग नाराज़ हैं. नीतीश कुमार को अपने साथियों को समझाने में दिक्कत अवश्य आई होगी, लेकिन मेरा इतना अंदाज़ ज़रूर है कि उन्होंने इस बार किसी को समझाया नहीं कि किसे मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है और किसे नहीं. अख़बारों में कई दिनों से ख़बरें आ रही थीं कि प्रशांत किशोर, जो नीतीश कुमार के नए सर्वोच्च अंतरंग मित्र हैं, ने मंत्रिमंडल के पुराने सदस्यों की ग्रेडिंग की है. मतलब यह कि किसने कितना काम किया और किसने नहीं किया. किसकी छवि ठीक है और किसकी छवि ठीक नहीं है. प्रशांत किशोर के सिर पर यह सेहरा है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वे के हथियार का सही फ़ैसला लेने में बखूबी इस्तेमाल किया. इसलिए जदयू से किसे मंत्री बनाना चाहिए, किसे नहीं बनाना चाहिए, इसमें उनका रोल अवश्य रहा होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले ही अख़बारों में बयान दे चुके थे कि वह एक अनोखा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

यह नई राजनीति की शुरुआत है

पृष्ठ 1 का शेष

मंत्रिमंडल बिहार को देने वाले हैं.

मंत्रिमंडल बन गया, लेकिन नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां बढ़ गईं. चुनौतियां इसलिए भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके सामने नरेंद्र मोदी का उदाहरण है. नरेंद्र मोदी ने जितने बयान प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद दिए, बिहार की जनता ने उनमें से हर एक को अपने आस–पास के विकास के साथ आंका, समस्याओं से आंका और उसने फ़ैसला लिया कि उसे नरेंद्र मोदी की बात के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए. नतीजतन, डेढ़ साल के भीतर नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री जीवन की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. नीतीश कुमार ने भी वायदे किए हैं और लोगों को स्वयं के विकास पुरुष होने का एहसास कराया है, ऐसे में अगर वह बिहार के लोगों की ज़िंदगी में अब परिवर्तन नहीं ला पाते और देश के सामने बिहार मॉडल जैसी चीज प्रस्तुत नहीं करते, जो बाज़ारवादी आर्थिक विकास से अलग जनोन्मुख विकास का मॉडल हो, तो लोगों का मन टूटना शुरू हो जाएगा. इसलिए ज़रूरी है कि वह बिहार के विकास का नक्शा बहुत धैर्य के साथ बैठकर बनाएं. विकास के नक्शे के बुनियादी क़दम सड़क, अस्पताल, शिक्षा, पेयजल और बिजली होने चाहिए. जब ये पांच चीजें बिहार के लोगों को मिल जाएं, तो उसके बाद कुछ और हो, तो काम मुश्किल नहीं रहेगा.

नीतीश कुमार के इस लक्ष्य को पूरा करने में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंत्री कितना सहयोग करते हैं, यह यक्ष प्रश्न है. राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ़ दो मंत्रियों को सरकार चलाने का अनुभव है और बाकी सारे मंत्री नए हैं. हमने देखा है कि सत्ता में आने के बाद जो नए मंत्री होते हैं, वे बहुत जल्दी उन लोगों से घिर जाते हैं, जो रास्ता भटकाने में माहिर होते हैं. उन्हें हम दलाल कह सकते हैं, पूंजीपतियों के एजेंट कह सकते हैं और दूसरे दलों द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधि कह सकते हैं. वे इतने होशियार होते हैं कि नए मंत्रियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं. कांग्रेस के भी जितने मंत्री बने हैं, उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी नए हैं. किसी को भी यह अनुभव नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे नियंत्रण में रखा जाए. मिलता–जुलता हाल जदयू का है, उसके भी आधे से ज़्यादा मंत्री नए हैं. कैसे सब एक ताल पर चलें, यही देखने की बात है. एक ताल पर अगर सब नहीं चलते हैं, तो बिहार विकास के कैसे रास्ते के ऊपर जाएगा, अभी नहीं कहा जा सकता. नीतीश कुमार के सामने चुनौती यह भी है कि वह तीनों दलों के मंत्रियों को एक सुर में और एक ताल पर कैसे चलाएंगे. अगर नीतीश कुमार चला ले गए, तो वह बिहार के विकास को एक मॉडल के रूप में देश के सामने रख पाएंगे.

प्रमुख मंत्रालयों का जिस तरह बंटवारा हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि विकास से संबंधित ज़्यादातर विभाग राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों के पास हैं. और, जब गठबंधन सरकार होती है, तो मुख्यमंत्री बहुत कम दखल देता है.

शपथ ग्रहण समारोह में मुलायम सिंह का न आना लोगों को काफी अखरा. मुलायम सिंह ने जनता परिवार को इकट्ठा किया था, सबसे मालाएं पहनी थीं और सबने उन्हें एक राय से अपना नेता माना था, लेकिन मुलायम सिंह बिहार चुनाव में एक अलग गठबंधन बनाकर कूदे. उनकी सीटें नहीं आईं, यह एक अलग सवाल है. उन्होंने नीतीश कुमार का निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अपनी समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं भेजा.

दरअसल, गठबंधन सरकारों का सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि हर मंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है. यह हमने केंद्र में यूपीए–1 और यूपीए–2 की सरकार में देखा कि जितने मंत्री थे, वे सब प्रधानमंत्री थे. अगर कहीं बिहार में भी ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंत्रियों ने यह रुख लेना शुरू कर दिया कि हम अपने विभाग में जो चाहेंगे, सो करेंगे, मुख्यमंत्री को बोलने का कोई हक़ नहीं है, तो विकास की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी.

शपथ ग्रहण समारोह में सबसे खुश अगर कोई दिखाई दिया, तो वह राबड़ी देवी थीं. उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके दोनों पुत्र सबसे महत्वपूर्ण मंत्री बनेंगे. मां की खुशी आंखों और चेहरे, दोनों पर थी. दूसरी खुशी कांग्रेस के दूसरे प्रदेशों से आए नेताओं में थी. शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार के घर पर हुई चाय पार्टी में दूसरे प्रदेशों के नेता बिहार के नेताओं को बधाई दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई, आपने देश में कांग्रेस को ज़िंदा कर दिया. बिहार कांग्रेस के नेता और मंत्री उनके इस बधाई संदेश को स्वीकार कर रहे थे. दरअसल, कांग्रेस ज़िंदा हुई है. कांग्रेस को कभी सपने में भी आशा नहीं थी कि उसे बिहार में 27 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन मिलीं और एक संदेश दे गईं कि अब अकेले कांग्रेस का चलना मुश्किल है. राहुल गांधी भी काफी गर्व से और मुस्कुरा कर कांग्रेस की जीत को अपनी जीत मानते दिख रहे थे. पर यहीं से कांग्रेस के लिए एक ख़तरा शुरू हो रहा है. कांग्रेस अगर नीतीश कुमार के साथ बिना शर्त खड़ी होती है, तो प्रदेश में कांग्रेस को प्रासंगिकता मिलती है और अगर उसने अपने केंद्रीय नेताओं के निर्देश के ऊपर बिहार में विकास का नक्शा बनाया, तो शायद यह उसके लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में बहुत मददगार साबित नहीं होगा.

लालू यादव बिहार और महा–गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. इसी सवाल को लेकर देश का मीडिया या बिहार का मीडिया नीतीश के साथ खेलेगा, जैसे कि नीतीश और लालू क्या कहते हैं, उसका दूसरा व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया देता है, दोनों में कौन महत्वपूर्ण है. लालू यादव के एक बयान के सौ अर्थ निकाले जाएंगे और नीतीश के एक बयान के दो सौ अर्थ निकाले जाएंगे. अगर ये दोनों लोग मीडिया के जाल में फंस गए, तो बिहार सरकार डगमगाने लगेगी.

यद्यपि संख्या का बंटवारा इतना जादुई है कि यदि कोई डगमगाता है, तो उसे फिर मध्यावधि चुनाव का ख़तरा उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी अन्य के साथ मिलकर कोई सरकार बिहार में बनाई ही नहीं जा सकती. लालू यादव एवं नीतीश कुमार के साथ मीडिया एक और सवाल पर खेलेगा. वह उनके बेटों के मंत्रालयों में लिए गए फ़ैसलों को चर्चा का विषय बनाएगा. देश में पूरा सोशल मीडिया लालू यादव के दोनों बेटों की शिक्षा और उनकी बातचीत के तरीके को लेकर चर्चाओं से भरा पड़ा है. अब मंत्रिमंडल में होने वाली चर्चा या मंत्रालयों में होने वाले फ़ैसले मीडिया के लिए एक अचूक औजार बन जाएंगे और वह चाहेगा कि इन्हें लेकर बिहार की सरकार में कुछ अस्थिरता आए और जो समीक्षा नहीं होनी चाहिए, वैसी समीक्षा भी बिहार के मंत्रिमंडल के फ़ैसलों की होगी. इसलिए कोई मंत्री सावधान रहे या न रहे, लेकिन लालू यादव के दोनों बेटों को अपने फ़ैसलों, अपनी भाषा और अपने व्यवहार को लेकर ज़्यादा सावधान रहना चाहिए. अन्यथा लोगों के बीच साख के ऊपर सवाल खड़े होने लगेंगे. बिहार की क़ानून व्यवस्था भी नीतीश कुमार के लिए परीक्षा की कसौटी होगी. क़ानून व्यवस्था जितनी सुधरी है, उससे और ज़्यादा उसे सुधारना होगा. अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के जंगलराज वाले प्रचार अभियान को लोग फिर माइक्रोस्कोपिक ग्लास से देखने लगेंगे. लेकिन, जिस तरह का तालमेल अभी लालू यादव और नीतीश कुमार में दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि नीतीश कुमार को कोई परेशानी निकट भविष्य में होने वाली नहीं है.

शपथ ग्रहण समारोह में मुलायम सिंह का न आना लोगों को काफी अखरा. मुलायम सिंह ने जनता परिवार को इकट्ठा किया था, सबसे मालाएं पहनी थीं और सबने उन्हें एक राय से अपना नेता माना था, लेकिन मुलायम सिंह बिहार चुनाव में एक अलग गठबंधन बनाकर कूदे. उनकी सीटें नहीं आईं, यह एक अलग सवाल है. उन्होंने नीतीश कुमार का निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अपनी समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं भेजा. जानकारी के अनुसार, मुलायम सिंह से लालू यादव ने भी बात की और नीतीश कुमार ने भी बात की. मुलायम सिंह ने पहले कहा कि वह आएंगे, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने अपने न आने की ख़बर अख़बारों में लीक करा दी और शपथ ग्रहण के दिन अखिलेश यादव को भी आने से मना कर दिया. इसलिए उत्तर प्रदेश में भविष्य में क्या नक्शा बनेगा, यह एक दिलचस्प प्रश्नचिन्ह के रूप में सामने खड़ा हो गया है. असम में होने वाले चुनाव के लिए एक नई आधारशिला नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दी. असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ–साथ यूडीएफ के प्रेसिडेंट बदरुद्दीन अजमल भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे और यह माना जा रहा कि अगर नीतीश कुमार बीच में पड़ें, तो असम में कांग्रेस, जदयू और यूडीएफ के बीच एक वैकल्पिक गठबंधन बन सकता है. आने वाले दिनों में पंजाब में भी चुनाव हैं, असम में भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी. इस शपथ ग्रहण समारोह में एक नए तरह के दिलचस्प समीकरण बने. पश्चिम बंगाल के धुर–परस्पर विरोधी ममता बनर्जी और सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी पहली कतार में बैठे थे. असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और यूडीएफ के प्रेसिडेंट बदरुद्दीन अजमल इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जो अब तक आमने–सामने चुनाव लड़ते थे. तमिलनाडु से स्टालिन, जो करुणानिधि के बाद डीएमके के सबसे सशक्त नेता हैं और अन्ना डीएमके के टीआर बालू शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर थे. पंजाब से सुखबीर सिंह बादल और उनके मुक़ाबले चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस शपथ ग्रहण समारोह में थे. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी उनके साथ थीं और वे आपस में बातचीत करते दिखाई दिए. तमिलनाडु से सीपीआई सांसद एवं पार्टी सचिव डी राजा इस शपथ ग्रहण समारोह में थे और वह कम्युनिस्टों से लड़ने वाली ममता बनर्जी से लगातार बातचीत करते दिखाई दिए. इसी तरह कर्नाटक से भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और उनके पुराने शिष्य, जो अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, इस समारोह में आए. जम्मू–कश्मीर से फारुख अब्दुल्ला एवं उमर अब्दुल्ला आए. इसी तरह झारखंड में एक–दूसरे के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ने और राजनीति करने वाले हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी एवं सरयू राय भी समारोह में मौजूद थे. यह दृश्य बता रहा था कि शायद देश में एक नए तरीके की राजनीतिक समझदारी विकसित हो रही है. यह समझदारी अगर बिहार में विकसित होती है, तो यह नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की स्वीकार्यता का संदेश देती है.

देश से लगभग दो लाख लोग अपने पैसों से इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने आए. कांग्रेस को जदयू और राजद का पूरा वोट मिला तथा उन्हें भी कांग्रेस का वोट मिला. भाजपा यह मानकर बैठी थी कि लालू का वोट नीतीश को ट्रांसफर नहीं होगा, नीतीश का वोट लालू को ट्रांसफर नहीं होगा और कांग्रेस का वोट किसी को ट्रांसफर नहीं होगा. पर भारतीय जनता पार्टी की आशा उस समय निराशा में बदल गई, जब तीनों पार्टियों का वोट एक–दूसरे को ट्रांसफर हो गया. अगर हम ट्रेडिशनल वोट ट्रांसफर की भाषा में चीजों को जानना चाहें, तो हमें पता लग जाएगा. वैसे मोटे तौर पर नीतीश कुमार बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान पर जहां खड़े थे, वहीं पर अभी भी खड़े हैं और अभी भी कोई ऐसा नहीं दिखाई देता, जो नीतीश कुमार की इस छवि को धूमिल कर सके.

इसलिए एक चुनौती नीतीश कुमार के सामने भी है, लालू यादव के सामने भी है, कांग्रेस के सामने भी है और पूरे बिहार के सामने भी है कि अगर किसी भी तरह इस गठबंधन में मरमरी शुरू होती है या किन्हीं फ़ैसलों को लेकर या किन्हीं क़दमों को लेकर कोई भटकाव नज़र आता है, तो मीडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो इस कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहेंगे. और, अगर उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, तो जिस अद्भुत प्रयोग की शुरुआत बिहार में हुई है, वह फिर कहीं और हो पाएगा, हाल–फिलहाल तो नहीं दिखाई देता. अगला चुनाव उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में है और उत्तराखंड में भी. देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा विरोध की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है और श्रेय लेने की होड़ में कहीं ऐसा न हो चले कि भाजपा विरोध की राजनीति की भ्रूण हत्या हो जाए. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 39
दिल्ली, 30 नवंबर–06 दिसंबर, 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060
+91–8451050786
+91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

आम राय के साथ ही साथ आंकड़े भी बताते हैं कि भूमिहारों ने खुलकर महागठबंधन का साथ नहीं दिया. इसी बात पर जब सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई तो यह बात उठी कि आखिर जिसने वोट ही नहीं दिया उसे ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में दिया जाए? इसलिए यह तय हुआ कि केवल एक मंत्री को रखा जाए और इसमें ललन सिंह पी के शाही पर काफी भारी पड़े. सभी जानते हैं कि पी के शाही नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं. इसी तरह अटकलों का बाजार इस बात को लेकर गर्म था कि विधान पार्षद संजय सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है. पूरे चुनाव अभियान में संजय सिंह ने जिस तरह से बढ़–चढ़ कर काम किया था उससे इस संभावना को काफी बल मिला.

आग के दरिया में भाजपा

भाजपा की एक बड़ी ज़िम्मेदारी एनडीए को अटूट बनाए रखने की है, क्योंकि उसमें किसी भी विघटन से बिहार के राजनीतिक हलके में उसकी नेतृत्व क्षमता पर बट्टा लग सकता है, ऐसा भाजपा नेताओं का भी मानना है. नई विधानसभा में एनडीए के कुल 58 सदस्य हैं, जिनमें सहयोगी दलों के सदस्यों की संख्या पांच है. इन सभी विधायकों को किसी भी सूरत में एनडीए के दायरे में बांधे रखना ज़रूरी है. भाजपा इसे अपनी राजनीतिक साख से जोड़कर देख रही है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार में महा–गठबंधन के घटक दलों यानी राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू) और कांग्रेस में चुनावी सफलता को लेकर उत्साह चरम पर है. कांग्रेस और राजद का मनोबल तो सहज ही काफी ऊंचा है. अर्से बाद सूबे की सत्ता–राजनीति में राजद अहम किरदार निभा रहा है, तो कई चुनावों के बाद पहली बार कांग्रेस इस हैसियत में पहुंची है. मौजूदा सरकार की नकेल काफी हद तक राजद प्रमुख लालू प्रसाद के हाथों में आई है और उनकी हैसियत किंगमेकर से अधिक सत्ता संचालक की बन गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं के निर्धारण और उन्हें लागू करने में लालू प्रसाद की भूमिका महा–गठबंधन में सबसे अहम हो जाएगी. कांग्रेस की तो बात ही अलग है, वह राज्य विधानसभा में चार से 27 की ताकत पर पहुंच कर नीतीश सरकार की साझीदार बन गई है, यही उसके लिए बड़ी बात है. इसके बरक्स, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में सन्नाटा छाया हुआ है. भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित पराजय ने स्तब्ध कर दिया है. पटना से लेकर दिल्ली तक के नेतृत्व में पराजय को लेकर खामोशी है. यदि कहीं से कोई आवाज़ आती है, तो वह आरोप की होती है या फिर उसके जवाब की. जवाब भी क्या, बल्कि सफाई की. हालांकि, प्रदेश भाजपा के सबसे कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी राज्य की क़ानून व्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं और कभी–कभी नंद किशोर यादव भी बोलते हैं, पर पार्टी नेतृत्व की खामोशी टूट नहीं रही है. चुनाव के बाद एक मौक़ा छठ के रूप में सामने आया, जब भाजपा नेताओं के सार्वजनिक दर्शन हो सके. एनडीए के अन्य घटक दलों की स्थिति भी कमोबेश भाजपा जैसी है. छठ के मौक़े पर ही लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख राम विलास पासवान एवं उनके पुत्र चिराग पासवान के सार्वजनिक दर्शन हुए. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा इस मौक़े पर भी नहीं दिखे. अलबत्ता, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) प्रमुख एवं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार मीडिया से मुलाकात की और उन्होंने एनडीए की पराजय के लिए काफी हद तक संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान को ज़िम्मेदार ठहराया. लेकिन, हम के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी ने धमाका किया. उन्होंने स्वयं और पुत्र रोहित कुमार की हार के बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की ज़िम्मेदारी ली. यही नहीं, उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी. बिहार की सोलहवीं विधानसभा के चुनाव पश्चात यह पहली बड़ी आहुति रही.

एनडीए में इतना सन्नाटा क्यों है, हार से पस्त हिम्मत या पराजय के कारणों के मंथन से पूर्व की खामोशी या फिर भावी रणनीति की तैयारी? इस प्रश्न का उत्तर सहज नहीं है. इसका उत्तर एनडीए नहीं, भाजपा के नेता दे सकते हैं. अन्य दलों की बात जाने दें, भाजपा में भी अब तक चुनाव की औपचारिक समीक्षा नहीं हुई, कम से कम प्रादेशिक संगठन में तो नहीं. प्रदेश में चुनाव प्रबंधन के ज़िम्मेदार भाजपा के बिहारी या ग़ैर बिहारी नेताओं की भी ऐसी कोई बैठक अब तक नहीं हुई, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा हुई हो. केंद्रीय नेतृत्व की एक बैठक ज़रूर हुई है, जिसमें हार की सामूहिक ज़िम्मेदारी की बात कही गई. उस बैठक में यह भी राय जाहिर की गई कि महा–गठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवारों के बीच परस्पर वोट ट्रांसफर एनडीए के घटक दलों की अपेक्षा बेहतर हुआ और ऐसा होना भाजपा (एनडीए) की हार का प्रमुख कारण बना.

एनडीए के अन्य घटक दलों की स्थिति भी कमोबेश भाजपा जैसी है. छठ के मौक़े पर ही लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख राम विलास पासवान एवं उनके पुत्र चिराग पासवान के सार्वजनिक दर्शन हुए. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा इस मौक़े पर भी नहीं दिखे. अलबत्ता, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) प्रमुख एवं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार मीडिया से मुलाकात की और उन्होंने एनडीए की पराजय के लिए काफी हद तक संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान को ज़िम्मेदार ठहराया.

क्या मामला इतना भर है? जो भी हो, हार की समीक्षा अभी होनी है, लेकिन यह कब होगी, इस बारे में कोई कुछ बताने की स्थिति में नहीं है. इतना तो तय है कि अब भाजपा (एनडीए) को दोतरफ़ा सोचना है. उसे अपनी ताकत समेट कर आगे की रणनीति तैयार करनी है. इस शताब्दी में भाजपा की यह सबसे बड़ी हार है. विधानसभा में उसके इतने कम सदस्य कई चुनावों के बाद हैं. भाजपा नए सहयोगियों की मदद से न सिर्फ़ अपेक्षित विस्तार पाने में विफल रही, बल्कि वह अपना पुराना जनाधार (वोट बैंक) भी सुरक्षित नहीं रख सकी. हाल के चुनावों में भाजपा के सबसे बड़े समर्थक अगड़े सामाजिक समूह रहे. इन समूहों ने भाजपा को बिहार की राजनीति में मजबूत ज़मीन दी. इस सामाजिक आधार के हितों का पोषण उसने कितना किया, यह तो विचार का विषय है, पर उसका यह आधार इस बार दरकता हुआ दिखा. हालांकि, पूरे राज्य में आम तौर पर अगड़े सामाजिक समूहों का सबसे बड़ा राजनीतिक ध्रुव भाजपा ही रही, पर राज्य के अनेक हिस्सों में अगड़े सामाजिक समूहों के मतदाताओं ने ग़ैर भाजपाई विकल्प के चयन का भी जोखिम लिया. अगड़े मतदाता बाहुल्य क्षेत्रों में भाजपा के अगड़े उम्मीदवारों की बड़ी–बड़ी हार इसी ओर संकेत करती है. साथ ही यह राजनीतिक स्थिति पार्टी की रणनीति को लेकर पुनर्विचार की अपेक्षा रखती है. पुनर्विचार की अपेक्षा तो भाजपा की आरक्षण नीति भी रखती है, ऐसी राय भाजपा के अनेक दिग्गज निजी बातचीत में ज़ाहिर करते हैं. उनके अनुसार, संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान को हार का ज़िम्मेदार बताया जा रहा है, पर तथ्य तो यह भी है कि उस बयान को निष्प्रभावी बनाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही दिन से हरसंभव कोशिश की. यहां तक कि महा–गठबंधन के नेताओं की धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पुरानी मांग भी उछाली गई. प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जातियों की चर्चा हुई, बिहार के दलित एवं अति पिछड़े नेतृत्व को एनडीए की छतरी के नीचे इकट्ठा किया गया, लेकिन आरक्षण के बारे में लालू–नीतीश की जोड़ी ने जो व्यूह तैयार किया, उसे भेदा नहीं जा सका. यानी पिछड़ों एवं अति पिछड़ों में भरोसा नहीं पैदा किया जा सका. इसलिए पार्टी की आरक्षण नीति को अति पिछड़ा और महादलित–मुखी सकारात्मक दिशा देने पर क्यों न विचार किया जाए, अनौपचारिक बातचीत में ऐसे सवाल किए जा रहे हैं.

भाजपा को इन सारे सवालों को लेकर दीर्घकालीन रणनीति तैयार करनी है, जो गंभीर विचार–विमर्श की अपेक्षा रखते हैं. फिलहाल पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व को दो मोर्चों पर जूझना है. पाठकों तक इन पंक्तियों के पहुंचने तक नई विधानसभा आहूत हो चुकी होगी. नई विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता का मसला चुनाव नतीजों की घोषणा होते ही चर्चा में आ गया. चूंकि विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लिहाजा उसके नेता को ही नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल होगा. नेता प्रतिपक्ष को उसकी संवैधानिक हैसियत के कारण कई सरकारी सुविधाएं हासिल हैं. राज्य में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के निर्णय में वह साझीदार होता है. बतौर नेता विधायक दल वह पार्टी की नीति निर्धारक समितियों में भी शामिल होता है. इस लिहाज से पार्टी के कामकाज में उसकी बड़ी भूमिका हो जाती है. चुनाव के दौरान जब भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की चर्चा चलती थी, तो पार्टी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार सार्वजनिक तौर पर स्वयं को पेश करते थे. भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पर भी उन्होंने अपना नाम आगे कर दिया है. नंद किशोर यादव पहले से मैदान में हैं. अभी तक तीसरा कोई नाम सामने नहीं आया, पर कुछ अन्य नामों का सामने आना तय है. प्रेम कुमार अति पिछड़ी जाति के हैं और वह इस बात को आगे कर भी रहे हैं. अब देखना यह है कि भाजपा नेतृत्व क्या करता है, किसे इस पद का दावेदार घोषित करता है, पिछड़े या अति पिछड़े को!

भाजपा की एक बड़ी ज़िम्मेदारी एनडीए को अटूट बनाए रखने की है, क्योंकि उसमें किसी भी विघटन से बिहार के राजनीतिक हलके में उसकी नेतृत्व क्षमता पर बट्टा लग सकता है, ऐसा भाजपा नेताओं का भी मानना है. नई विधानसभा में एनडीए के कुल 58 सदस्य हैं, जिनमें सहयोगी दलों के सदस्यों की संख्या पांच है. इन सभी विधायकों को किसी भी सूरत में एनडीए के दायरे में बांधे रखना ज़रूरी है. भाजपा इसे अपनी राजनीतिक साख से जोड़कर देख रही है. भाजपा नेताओं को आशंका है कि सहयोगी दलों के विधायकों पर देर–सवेर नीतीश कुमार डोरे डालने का प्रयास करेंगे. लोजपा का तो ऐसा इतिहास भी रहा है. पिछली दो विधानसभाओं की शुरुआत में उसके चार–चार विधायक रहे हैं, मगर सभी नीतीश कुमार के साथ होते चले गए और जद (यू) में शामिल होते रहे. अंत में लोजपा के पाले में सिर्फ़ शून्य बचा. रालोसपा तो विधानसभा में पहली बार दो सदस्यों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है. हम का गठन इसी चुनाव में हुआ है और उसके प्रमुख जीतन राम मांझी अपने दल के एकमात्र विधायक हैं. हालांकि, भाजपा को किसी पर कोई शक नहीं है, पर राजनीति और राजनेता का क्या भरोसा? कभी इधर, तो कभी उधर! सो, भाजपा अनेक मोर्चों पर जूझते हुए भी चौकस है.■

feedback@chauthiduniya.com

मंत्रिमंडल

चाहकर भी कई नेता छूटे

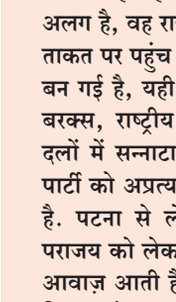

सरोज सिंह

नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने जिस सामाजिक ताने–बाने का खाका खींचकर प्रदेश के चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी को चारो खाने चित्त कर दिया ठीक उसी तरह अपने मंत्रिमंडल के बनाने में भी इसका पूरा ख्याल रखा गया कि वह ताना–बाना बरकरार है. नई सरकार में जो चेहरे शामिल किए गए उन्हें देखकर तो यही लगता है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अपने इस प्रयास में सफल रहे. लेकिन इस काम का एक साइड इफेक्ट यह हुआ कि ये दोनों नेता चाहकर भी अपने कुछ ऐसे पसंदीदा सेनानायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाए जिन्हें वे दिलोजान से चाहते हैं. यही हाल कांग्रेस का भी रहा इसके भी कुछ नेता तालमेल की राजनीति और सामाजिक ताने–बाने को बनाए रखने के चक्कर में मंत्री नहीं बन पाए. बात अगर जदयू से शुरू की जाए तो सबसे पहला नाम श्याम रजक का आता है. जदयू के कुछ मंत्रियों को हटना था यह तय था कि क्योंकि जदयू कोटे से 14 लोगों को ही शामिल किया जाना है. लेकिन छंटने वालों में श्याम रजक होंगे इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. यह तब हुआ जबकि श्याम रजक लालू और नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं. दोनों नेताओं को नजदीक लाने में श्याम रजक की अहम भूमिका रही है. जब बिहार में जीतन राम मांझी की सरकार बनी तो उस समय भी श्याम रजक के बारे में यह कहा जाता था कि वह केवल नीतीश कुमार का ही कहना मानते हैं. कहा जा रहा है कि पांच दलितों को शामिल करने के बाद श्याम रजक के लिए जगह बनाना लालू और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो गया. लेकिन सूत्र बताते हैं कि देर सवेर श्याम रजक को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. यही हाल पी के शाही का भी हुआ. आम राय के साथ ही साथ आंकड़े भी बताते हैं कि भूमिहारों ने खुलकर महागठबंधन का साथ नहीं दिया. इसी बात पर जब सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई तो यह बात उठी कि आखिर जिसने वोट ही नहीं दिया उसे ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में दिया जाए? इसलिए यह तय हुआ कि केवल एक मंत्री को रखा जाए और इसमें ललन सिंह पी के शाही पर काफी भारी पड़े. सभी जानते हैं कि पी के शाही नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं. इसी तरह अटकलों का बाजार इस बात को लेकर गर्म था कि विधान पार्षद संजय सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है. पूरे चुनाव अभियान में संजय सिंह ने जिस तरह से बढ़–चढ़ कर काम किया था उससे इस संभावना को काफी बल मिला. लेकिन बात फिर वहीं आकर अटक गई कि राजपूत बिरादरी ने भी महागठबंधन के लिए अपना दिल पूरी तरह नहीं खोला. इसलिए केवल इस समाज से दो लोगों को यानि की जयकुमार सिंह को जदयू कोटे से और अवधेश सिंह को कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया. राजद की तरफ से न तो किसी राजपूत को और न ही किसी भूमिहार को मंत्री बनाया गया. गौरतलब है कि राजद ने तो किसी भूमिहार को टिकट भी नहीं दिया था. बात अगर यादवों की करें तो सरकार में इनका बंपर प्रतिनिधित्व रखा गया क्योंकि यादवों ने दिल खोलकर महागठबंधन को अपना वोट दिया. नीतीश की नई सरकार में सात यादवों को शामिल किया गया है. लेकिन इसके बावजूद भाई वीरेंद्र, रामानंद यादव, राजवल्लभ यादव और ललित यादव जैसे लालू के करीबी मंत्री बनने से रह गए. इसी तरह जदयू से नरेंद्र नारायण यादव को उनकी बेदाग छवि के बावजूद जगह नहीं मिल पाई. किसी तरह विजेंद्र यादव जगह बनाने में सफल रहे. कांग्रेस कोटे से किसी यादव को मंत्री नहीं बनाया गया है. कुशवाहा कोटे से तीन मंत्री बनाए गए हैं. बेजोड़ काम करने वाले की छवि रखने वाले विभूतिपुर के जदयू विधायक रामबालक सिंह सरकार में अपनी जगह नहीं बना पाए जबकि नीतीश कुमार रामबालक सिंह को काफी पसंद करते हैं. जानकार बताते हैं कि अगले विस्तार में रामबालक सिंह को नीतीश सरकार में जगह मिल सकती है लेकिन फिलहाल तो वह खाली हाथ ही रह गए. अतिपिछड़ा समाज से चार लोगों को मंत्री बनाया गया है और कुर्मी से दो को. मुसलमानों को नीतीश सरकार में पूरी तवज्जो दी गई है और इससे चार विधायकों को मंत्री बनाया गया है. हालांकि मुसलमानों को इस बात का मलाल है कि अब्दुल बारी सिद्दकी उपमुख्यमंत्री नहीं बन पाए. बताया जा रहा है अगले विस्तार से किसी एक और मुस्लिम विधायक को मंत्री पद दिया जा सकता है. नीतीश ने अपनी नई सरकार में दलितों का पूरा ख्याल रखा और पांच विधायकों को इस समाज से मंत्री बनाया गया है. जीतनराम मांझी और रामविलास पासवान की चुनौती को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए दलितों पर यह सरकार मेहरवान दिखती है. गौरतलब है दलितों ने महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोट किया और जीतनराम मांझी और रामविलास पासवान हाथ मलते ही रह गए. लेकिन इसके बावजूद रत्नेश सदा और मनीष कुमार जैसे जदयू के विधायक सरकार में अपनी जगह नहीं बना पाए. ये दोनों विधायक नीतीश के काफी करीबी रहे हैं. ■

जदयू के कुछ मंत्रियों को हटना था, यह तय था, क्योंकि जदयू कोटे से 14 लोगों को ही शामिल किया जाना है. लेकिन छंटने वालों में श्याम रजक होंगे इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. यह तब हुआ जबकि श्याम रजक लालू और नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं. दोनों नेताओं को नजदीक लाने में श्याम रजक की अहम भूमिका रही है.

feedback@chauthiduniya.com

जिस तरह से कश्मीर में कुछ नौजवानों को आईएसआईएस का झंडा लहराते कई बार देखा जा चुका है और देश के कई अन्य हिस्सों में आईएसआईएस का साथ देने के संदेह में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है यह खतरे की घंटी है, आईएसआईएस के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनाने की आवश्यकता है. भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लगभग 23 भारतीय आईएसआईएस में शामिल हैं. सितंबर में यूएई से आईएसआईएस के साथ संबंध रखने के संदेह में चार भारतीयों को भारत वापस भेजा गया था, सितंबर में ही एक 37 वर्षीय महिला जोसेफ को भारत वापस भेजा गया था, उसपर आईएसआईएस के लिए नौजवानों की भर्ती करने का आरोप था.

भारतीय मुसलमान आईएसआईएस के साथ नहीं

वसीम अहमद

फ्रांस के आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. फ्रांस की सरजमीं पर हुए अबतक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले में तकरीबन 150 लोगों की जान गई. पेरिस में हुए इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली. गौरतलब है कि इसी साल जनवरी के महीने में विवादित कार्टून पत्रिका शार्ली हेब्दो के मुख्यालय और एक मॉल में हुए आतंकवादी हमले में 17 लोग मारे गए थे. बहरहाल फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पेरिस में हुए आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वार बताकर आईएसआईएस के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है.

आईएसआईएस एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिससे भारत सहित पूरी दुनिया को खतरा है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक ईराक और सीरिया के बाद यह संगठन भारत में अपनी पैठ जमाने की कोशिश में अपरिपक्व नव-युवकों का ब्रेनवॉश कर सकता है. केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में पांच राज्यों जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम को खासतौर पर चौकस रहने की सलाह दी है. दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने भी अपने आला-अधिकारियों को चौकस रहने के निर्देश दिए हैं.

आतंकवादी हमले चाहे पेरिस में हों या दुनिया में कहीं और, इन्हें किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता. दरअसल आतंकी इस्लाम का लबादा ओढ़कर सिर्फ अपना मक़सद पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए वे किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहते हैं. लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि कुछ मौकापरस्त लोग इस तरह के कायरतापूर्ण हमलों को क्रिया-प्रतिक्रिया की भूल-भुलैया में उलझाकर इसे जायज ठहराने की कोशिश करते हैं. आईएसआईएस सहित दुनिया भर के विभिन्न आतंकवादी संगठन अपने इस तरह के हमलों को किसी न किसी आधार पर जायज ठहराने की पुरजोर कोशिश करते हैं जबकि उनकी इस तरह की कार्रवाई में बेगुनाह लोग मौत का शिकार हो जाते हैं. लेकिन हमारे देश के कुछ राजनेता भी इस तरह के हमलों को सही ठहराते हैं. हालिया पेरिस हमले के बारे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान ने कहा कि ये हमला फ्रांस में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ है. इसके जवाब में एक नेता ने यह कह दिया कि ऐसा कहने वाला आईएसआईएस के लिए काम कर रहा है. एक और मशहूर राष्ट्रीय स्तर के नेता ने मुसलमानों को यह सलाह दे दी कि वे आतंकवाद के ख़िलाफ शपथ लें. कहने का तात्पर्य यह कि ऐसे हमलों के बाद राजनेताओं की ओर से गैरजरूरी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है और मीडिया भी इस बयानों को खूब कवरेज देता है.

दरअसल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवियों और उलेमाओं ने पेरिस या इस जैसे दूसरे आतंकी हमलों को मानवता विरोधी और इस्लाम विरोधी करार दिया है और क्रिया-प्रतिक्रिया की चल रही बहस को सिरे से खारिज कर दिया है. इस बात पर तकरीबन सभी उलेमा सहमत हैं कि आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है और इसके सिद्धांत और विचारधारा इस्लामिक उसूलों के ख़िलाफ़ है. मिस्र की जानी-मानी इस्लामिक शैक्षणिक संस्था जामिया अजहर से पहले ही एक फतवा जारी हो चुका है जिसमें आईएसआईएस को गैरइस्लामी विचारधारा का प्रवर्तक संगठन बताया जा गया है.

जहां तक भारत का सवाल है तो यहां के अधिकतर मुस्लिम संगठन अपने-अपने तरीके और स्तर से आईएसआईएस और उस जैसे दूसरे संगठनों के गैर-इस्लामी होने की अपनी राय ज़ाहिर कर चुके हैं. इसके अलावा अलग-अलग पंथ और विचारधारा वाले तकरीबन एक हजार उलेमाओं ने साझा फतवा जारी करके इस

संगठन को गैर इस्लामी करार दिया है. पेरिस में हुए हमले के बाद जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दिल्ली के जंतरमंतर और देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें इसके महसचिव महमूद मदनी ने कहा कि इस तरह के इस्लामिक संगठन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और हम अपने खून की आखिरी बूंद तक उनके खिलाफ जंग जारी रखेंगे. इस मौके पर दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हमें यह पता लगाना चाहिए कि आईएसआईएस को हथियार और पैसा कौन पहुंचा रहा है? ये कौन सी ताकतें हैं?

जाहिर है पेरिस और इस जैसे दूसरे आतंकी हमलों की वजह से दुनियाभर में इस्लाम की छवि खराब हो रही है और लोगों के मन में इस्लाम विरोधी भावनायें प्रबल हो रही हैं. तो क्या आईएसआईएस वाकई मुसलमानों को बदनाम करने वाला संगठन है. चौथी दुनिया ने देश की कई मशहूर मुस्लिम शख्सियतों और संगठनों के प्रमुखों से बात की. जिसके जवाब में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख मौलाना उमैर इलियासी ने कहा कि आईएसआईएस ने पेरिस पर हमला करके अमानवीय काम किया है जिसकी मैं निंदा करता हूं और हमारे संगठन से जुड़े इमामों से अपील करता हूं कि वे शुक्रवार को अफसोस जाहिर करें और इस नापाक कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाएं. उनका मानना है आतंकवादी सोशल मीडिया का सहारा लेकर नौजवानों को अपने संगठन में शामिल करने का लालच देते हैं और ये नौजवान इनके जाल में फंस जाते हैं, अगर इन नौजवानों को सही मार्गदर्शन मिले तो इनका ब्रेनवॉश करना आतंकवादी संगठनों के लिए आसान नहीं होगा. आतंकवादी हमले को राजनीतिक रंग देने के सवाल पर मौलाना इलयासी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जिस नेता ने पेरिस हमले को प्रतिक्रिया का नाम दिया है, वह गलत है. प्रतिक्रिया का कानूनी रास्ता भी हो सकता है

आतंकवादी हमले चाहे पेरिस में हों या दुनिया में कहीं और, इन्हें किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता. दरअसल आतंकी इस्लाम का लबादा ओढ़कर सिर्फ अपना मक़सद पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए वे किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहते हैं. लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि कुछ मौकापरस्त लोग इस तरह के कायरतापूर्ण हमलों को क्रिया-प्रतिक्रिया की भूल -भुलैया में उलझाकर इसे जायज ठहराने की कोशिश करते हैं.

लेकिन जो तरीका अपनाया गया है वह बिल्कुल गलत है. दिल्ली स्थित फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि आईएसआईएस अपने हर क्रियाकलाप के पीछे मुसलमानों के लिए तबाही और बर्बादी का सामान छोड़ जाता है, इससे यह साबित होता है कि ये इस्लाम के दुश्मन हैं दोस्त नहीं, जो मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए जेहाद के नाम पर खून-खराबा कर रहे हैं, इसी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है.

जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि आतंकवादी हमला किसी भी तरफ से हो उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन पेरिस पर जो हमला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए कि हमलावर कौन हैं, जहां तक आईएसआईएस के इस हमले की जिम्मेदारी लेने की बात है तो ये हो सकता है कि उसने क्रेडिट लेने के लिए ऐसा किया हो. इसलिए फ्रांस को चाहिए कि सबसे पहले वह पुख्ता सुबूत इकट्ठा करे और गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाए. इस सिलसिले में एक खास बात यह है कि प्रतिक्रिया स्वरूप फ्रांस ने सीरिया और ईराक पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस कार्रवाई में वहां के आम नागरिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है. चूंकि अबतक यह देखा गया है कि जब भी कहीं हवाई हमले होते हैं वहां बड़ी संख्या में बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं. उन्होंने भी आज़म खान की टिप्पणी को गलत करार दिया. उन्होंने पहली बात तो यह कही कि इस्लाम में इस तरह की प्रतिक्रिया की कोई गुंजाइश ही नहीं है.

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक ने कहा कि पेरिस का हमला अमानवीय और गैरइस्लामिक है. किसी भी व्यक्ति या संस्था को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह किसी बेगुनाह का कत्ल करे. इस्लाम में इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए कोई जगह नहीं है. जहां तक कुछ नेताओं द्वारा मुसलमानों के दहशतगर्दी के खिलाफ शपथ लेने की मांग का सवाल है तो उसपर मौलाना सादिक ने कहा कि ये एक गैरजरूरी राजनीतिक बयान है, इस तरह के बयान देने से राजनेताओं को बचना चाहिए.

मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के मौलाना असगर अली सल्फी ने कहा कि पेरिस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं. इस्लाम में इस तरह की नापाक घटना की कोई जगह नहीं है, जहां तक हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के लेने की बात है तो पहली बात यह कि मुझे यह नहीं मालूम की कि आईएसआईएस का असली ठिकाना कहां है? हो सकता है इंडियन मुजाहिदीन की तरह यह भी एक अज्ञात संगठन है. इसके पीछे कोई इस्लाम का दुश्मन हो, और आईएसआईएस की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रच रहा हो, लेकिन जो भी हो लेकिन वैश्विक स्तर पर इस संगठन और आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाकर कार्रवाई करनी चाहिए.

खानकाह-ए-रहमानी मुंगेर के मौलाना वली रहमावनी ने कहा कि वह इस हमले की सख्त निंदा करते हैं और कोई यदि कोई प्रतिक्रिया के तौर पर इसे सही ठहराता है तो वह भी गलत है. बेकसूर इंसानों की जान लेना किसी भी स्थिति में सही नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि कुछ नेता मुसलमानों को आतंकवाद के खिलाफ शपथ लेने का मशविरा दे रहे हैं तो इसपर उन्होंने कहा कि इस्लाम नाम है दूसरों पर जुल्म न करने का. लिहाजा इस तरह की बातें गैरजरूरी हैं. मुमकिन है कि कोई न कोई राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया. गौरतलब है कि भारत में आईएसआईएस की दिलचस्पी बढ़ रही है. हालांकि वह अभी तक यहां अपना प्रभाव छोड़ने और वजूद बनाने में कामयाब नहीं हुआ है. लेकिन जिस तरह से कश्मीर में कुछ नौजवानों को आईएसआईएस का झंडा लहराते कई बार देखा जा चुका है और देश के कई अन्य हिस्सों में आईएसआईएस का साथ देने के संदेह में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है यह खतरे की घंटी है, आईएसआईएस के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनाने की आवश्यकता है. भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लगभग 23 भारतीय आईएसआईएस में शामिल हैं. सितंबर में यूएई से आईएसआईएस के साथ संबंध रखने के संदेह में चार भारतीयों को भारत वापस भेजा गया था, सितंबर में ही एक 37 वर्षीय महिला जोसेफ को भारत वापस भेजा गया था, उसपर आईएसआईएस के लिए नौजवानों की भर्ती करने का आरोप था. उसी तरह अलग-अलग समय में भारत से सीरिया जाने वाले 17 नौजवानों को शक की बिनाह पर रोका जा चुका है. हालांकि निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये नौजवान वाकई आईएसआईएस के लिए ही काम कर रहे थे. लेकिन आईएसआईएस के झंडे लेकर घूमना और उसकी चिन्ह वाली टीशर्ट पहनना इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि भारत में आईएसआईएस अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत के मुसलमान आईएसआईएस का साथ नहीं देंगे. लेकिन हालिया एडवाइजरी यह इशारा कर रही है कि भारतीय सरजमीं पर आईएसआईएस के लिए कुछ नौजवानों में हमदर्दी देखी जा रही है. वो कभी भी उनके हाथों का खिलौना बन सकते हैं. बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस हमले के बाद जो बयान दिया है वह बेहद अहम है. उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. जिस तरह आईएसआईएस के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक जुट हो रहा है उससे लगता है कि उसने पेरिस में हमला करके अपने लिए कब्र खोद ली है. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

आजम ने कहा था, अमेरिका और रूस की ओर से अरब देशों पर हमला कर वहां निर्दोष लोगों का मारा जाना उचित नहीं है. ये हरकतें भी पेरिस हमले जितनी ग़लत हैं. हमें यह देखने की आवश्यकता है कि किसने पहले किसे मारा. उसके बाद किसने जवाबी कार्रवाई की. यह बहस का मुद्दा है. आप ड्रोन से बम बरसाते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं. इतिहास फ़ैसला करेगा कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं. यह हमला एक प्रतिक्रिया (रिएक्शन) है. विश्व शक्तियों को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए. किस कार्रवाई से यह प्रतिक्रिया हुई और क्या उनकी कार्रवाई उचित थी? उन्हें सोचने की आवश्यकता है, अन्यथा आशंका है कि स्थिति और बिगड़ेगी. मेरा मानना है कि दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है. रिएक्शन कहां से हो रहा है और क्यों हो रहा है, यह सुपर पावर देशों को सोचना चाहिए.

सियासी फ़लक पर ज़ोर-शोर से चल रही महा-गठबंधन की पतंगबाज़ी

फिर बैठेगा बैतलवा उसी डाल पर!

फोटो–प्रभात पाण्डेय

बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में यह सवाल मुखर रूप से उठने लगा कि सपा नेतृत्व ने महा-गठबंधन से अलग होने का फ़ैसला किन स्थितियों में लिया और फिर से उसमें शामिल होने की क्या संभावनाएं हैं. इस सवाल को राज्य सरकार के मंत्री फरीद महफूज ने यह कहकर हवा दे दी कि सपा और बसपा को गठबंधन कर लेना चाहिए. उन्होंने दोनों दलों को उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन का सुझाव देकर राजनीतिक ताप बढ़ा दिया. किदवई ने कहा, बिहार की तरह यूपी में भी भाजपा के ख़िलाफ़ महा-गठबंधन बने, तो अच्छा है. मैं दुआ करूंगा कि महा-गठबंधन में बसपा भी शरीक हो.

प्रभात रंजन दीन

बिहार चुनाव में महा-गठबंधन की भारी जीत और महा-गठबंधन से अलग होने की भारी चूक से मुक़ाबिल समाजवादी पार्टी ने फिर से महा-गठबंधन में शामिल होने का मन बना लिया है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव संगठन की कई सभाओं में इसका संकेत दे रहे हैं. मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव साफ़-साफ़ बोल चुके हैं कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी महा-गठबंधन हो सकता है. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उत्तर प्रदेश में महा-गठबंधन किन पार्टियों के साथ मिलकर किया जाएगा. अखिलेश यादव ने कहा कि इस बारे में कोई भी फ़ैसला नेताजी (मुलायम सिंह) और पार्टी का संसदीय दल द्वारा लिया जा सकता है. अखिलेश के इस बयान के बाद प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने यह कहकर भ्रम का माहौल भी बनाया कि यूपी में सपा अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी और महा-गठबंधन की कोई संभावना नहीं है. शिवपाल ने कहा कि यदि भविष्य में महा-गठबंधन की कोई संभावना बनती भी है, तो उसका फ़ैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा.

बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में यह सवाल मुखर रूप से उठने लगा कि सपा नेतृत्व ने महा-गठबंधन से अलग होने का फ़ैसला किन स्थितियों में लिया और फिर से उसमें शामिल होने की क्या संभावनाएं हैं. इस सवाल को राज्य सरकार के मंत्री फरीद महफूज ने यह कहकर हवा दे दी कि सपा और बसपा को गठबंधन कर लेना चाहिए. उन्होंने दोनों दलों को उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन का सुझाव देकर राजनीतिक ताप बढ़ा दिया. किदवई ने कहा, बिहार की तरह यूपी में भी भाजपा के ख़िलाफ़ महा-गठबंधन बने, तो अच्छा है. मैं दुआ करूंगा कि महा-गठबंधन में बसपा भी शरीक हो. किदवई के बयान के परिपेक्ष्य में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि लालू-नीतीश के गठबंधन को लेकर कुछ लोग पहले आशंका में थे और कुछ इसे असंभव भी बताते थे. उसी तरह सपा-बसपा का महा-गठबंधन होना अभी बेमेल लगता है और मुश्किल भी दिखता है, लेकिन यह असंभव नहीं है. 1993 में सपा और बसपा ने गठबंधन करके न सिर्फ़ चुनाव लड़ा था, बल्कि सरकार भी बनाई थी. राजनीति के जानकार मानते हैं कि बिहार की तरह पिछड़ों, दलितों एवं मुसलमानों की एकजुटता के लिए सपा-बसपा का गठबंधन सबसे प्रभावी हो सकता है.

बहरहाल, बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद से पछतावे में पड़ी समाजवादी पार्टी को फरीद महफूज किदवई के बयान से मौक़ा मिल गया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महा-गठबंधन की संभावनाओं की बात करके शीर्ष नेतृत्व के लिए एक पेशबंदी भी कर दी. अखिलेश का यह बयान उन नेताओं के लिए भी करारा जवाब साबित हुआ, जिन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह को इस बात के लिए राजी किया था कि वह बिहार के महा-गठबंधन से अलग हो जाएं. यह भी साफ़ हुआ कि अब पार्टी के नए नीति-निर्माण में उन नेताओं को अलग रखा जाएगा. उल्लेखनीय है कि महा-गठबंधन से अलग होने के पक्षधर नेताओं में सबसे आगे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव थे. बिहार में महा-गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव को खास तौर पर आमंत्रित करके लालू-नीतीश ने अपनी मंशा रेखांकित कर दी. अखिलेश यादव को शपथ ग्रहण में शरीक होने का न्यौता मिला और मुलायम सिंह के जन्मदिन समारोह में शामिल होने का न्यौता लालू को गया, इसके निहितार्थ स्पष्ट हैं.

समाजवादी पार्टी में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक यह बात साल रही है कि महा-गठबंधन से अलग होने के फ़ैसले ने सपा के राष्ट्रीय फलक पर उभर कर आने का मौक़ा छीन लिया. सपाई मानते हैं कि महा-गठबंधन से समाजवादी पार्टी अलग न हुई होती, तो वह बिहार में कई सीटें जीत लेती, उसके एक-दो मंत्री भी बन जाते और राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश के बजाय मुलायम राजनीति के केंद्र में रहते. भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ देश भर के समाजवादियों को एक करने की पहल मुलायम सिंह ने ही की थी. एक बार फिर से महा-गठबंधन में वापसी का सपा का रास्ता साफ़ होता दिख रहा है. हालांकि, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजित सिंह ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई महा-गठबंधन संभव नहीं है. उन्होंने कहा, यूपी में सपा और बसपा एक साथ आने से रहे. बिहार में महा-गठबंधन की जीत की एक बड़ी वजह नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ सत्ता विरोधी रुझान न होना था. यूपी में सपा सरकार के ख़िलाफ़ हर तबके में नाराज़गी है. चौधरी बोले कि रालोद का सपा से कोई गठबंधन नहीं होगा.

सपा, कांग्रेस एवं रालोद को मिलाकर भी एक गठबंधन तैयार करने की समानांतर कोशिश हो रही है, जिसमें लालू और नीतीश समेत दूसरे सेकुलर नेता भी शामिल रहें, ताकि भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव रोका जा सके. उक्त दल गठबंधन करके पहले भी चुनाव में उतरते रहे हैं. राजनीतिक कयासों में एक अटकल यह भी है कि बसपा, कांग्रेस और रालोद मिलकर चुनाव लड़ें. बसपा उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनाव अकेले लड़ चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार और बदले राजनीतिक हालात में महा-गठबंधन की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता. ताजा राजनीतिक स्थितियों में बसपा अपने दम पर भाजपा को चुनौती देने में पूरी तरह सक्षम नहीं है. गठबंधन बनने पर सपा और भाजपा के ख़िलाफ़ सत्ता विरोधी रुझान, क़ानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर जंग जीती जा सकती है. एक राजनीतिक संभावना यह भी तलाशी जा रही है कि भाजपा और रालोद मिलकर चुनाव लड़ें. भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पुराने सहयोगी अपना दल के साथ विधानसभा चुनाव में उतर सकती है. भाजपा और रालोद पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं. दूसरी संभावना भाजपा और बसपा के तालमेल को फिर से दोहराने में तलाशी जा रही है, लेकिन उस तालमेल के तीखे अनुभव इस मिलाप में आड़े आ रहे हैं.

बसपा से गठबंधन के कयासों को सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव सिरे से नकार देते हैं. वह कहते हैं, बसपा से गठबंधन कभी नहीं होगा. सपा की नीति है, कांग्रेस और भाजपा से बराबर राजनीतिक दूरी बनाकर रखी जाए. यह सपा नेतृत्व को तय करना है कि किन समाजवादी विचारधारा वाले दलों से गठबंधन किया जाए और किनसे नहीं. जदयू-राजद की तरह सपा-बसपा गठबंधन की संभावनाओं के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा-बसपा के रिश्ते जदयू-राजद से अलग हैं. बाकी लोगों के लिए मायावती बहनजी हैं, लेकिन हमारे लिए वह बुआ हैं. हम हर राजनीतिक गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं. नज़र इस पर भी है कि कहीं बसपा और भाजपा का राजनीतिक गठबंधन तो नहीं हो रहा? उन्होंने कहा, हम राज्य के विकास के लिए काफी काम कर रहे हैं. ऐसे में जिन्हें यूपी में गठबंधन की ज़रूरत होगी, वे खुद संभावनाएं देखेंगे. बड़बोलेपन के विशेषज्ञ सपा नेता आजम खान ने अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के बयानों के विपरीत बयान पेश किया कि उत्तर प्रदेश में महा-गठबंधन आसान नहीं है. बिहार में महा-गठबंधन से अलग होने के सवाल पर आजम ने कहा कि ऐसे फ़ैसलों में उनकी कोई भूमिका नहीं होती.■

सपा को मदनी की सलाह

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने समाजवादी पार्टी को बसपा के साथ महा-गठबंधन बनाकर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी है, ताकि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को शिकस्त दी जा सके. मदनी का कहना है, देशहित में भाजपा को कमज़ोर करना ज़रूरी है. सिर्फ़ यूपी में नहीं, बल्कि पूरे देश में भाजपा विरोधियों को एकजुट हो जाना चाहिए. यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में अगर सभी पार्टियां अपने निजी फ़ायदे और भाजपा की साज़िश में फंस कर अलग-अलग लड़ेंगी, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा.

feedback@chauthiduniya.com

पेरिस हमले पर अमानवीय बयान से हतप्रभ लोग पूछ रहे सवाल

आजम समाजवादी हैं या अलगाववादी!

राष्ट्र विरोधी बयान देने में एक तरफ़ जम्मू-कश्मीर सुर्खियों में रहता है, तो दूसरी तरफ़ उत्तर प्रदेश. जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेता राष्ट्र विरोधी बयान देते रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी नेता आजम खान. जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता बार-बार संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाते हैं और आजम खान भी संयुक्त राष्ट्र में अर्जी देने की उसी बीमारी से ग्रस्त हैं. फ्रांस की राजधानी पेरिस में पिछले दिनों हुई सिलसिलेवार आतंकी वारदात में सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बाद आजम खान ने जो अमानवीय बयान दिया, उसने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादियों को भी पीछे छोड़ दिया. आजम ने कहा कि यह क्रिया की प्रतिक्रिया है. आजम के इस बयान से समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी सकते में है और वह इसे उनका व्यक्तिगत बयान बताकर पल्ला झाड़ रहा है. चारों तरफ़ से यह मांग उठने लगी है कि आतंकवाद के पक्ष में दिए गए इस बयान पर समाजवादी पार्टी अपना नीतिगत स्टैंड स्पष्ट करे और आजम खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा समझा जाएगा कि वह आतंकवाद का समर्थन करती है. आजम खान के बयान पर फ्रांस के भारत स्थित राजदूत ने भी गहरा क्षोभ जताया है. फ्रांस के शीर्ष राजनयिक की प्रतिक्रिया से आजम का बयान भारत सरकार की विदेश नीति और कूटनीति, दोनों पर एक सवाल की तरह चिपक गया है.

मर्यादा की सीमा लांघती ज़ुबान

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने बयान में मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखते. इंग्लैंड की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आजम ने कहा, मोदी इन दिनों काफी बेचैन लग रहे हैं. उन्हें अपनी पत्नी को साथ रखना चाहिए, इससे उनका तन-मन दोनों शांत रहेगा. मोदी को भाजपा के सभी कुंवारे नेताओं की शादी का भी इंतजाम कर देना चाहिए, ताकि अक्सर गरम हो जाने वाले उक्त नेता थोड़ा ठंडे दिमाग़ से काम करें. मोदी ने बापू और बुद्ध का नाम लंदन में लिया, जबकि वह बापू के कातिल हैं, उन्हें बापू का नाम लेने का हक़ नहीं है.

दरअसल, आजम ने कहा था, अमेरिका और रूस की ओर से अरब देशों पर हमला कर वहां निर्दोष लोगों का मारा जाना उचित नहीं है. ये हरकतें भी पेरिस हमले जितनी ग़लत हैं. हमें यह देखने की आवश्यकता है कि किसने पहले किसे मारा. उसके बाद किसने जवाबी कार्रवाई की. यह बहस का मुद्दा है. आप ड्रोन से बम बरसाते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं. इतिहास फ़ैसला करेगा कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं. यह हमला एक प्रतिक्रिया (रिएक्शन) है. विश्व शक्तियों को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए. किस कार्रवाई से यह प्रतिक्रिया हुई और क्या उनकी कार्रवाई उचित थी? उन्हें सोचने की आवश्यकता है, अन्यथा आशंका है कि स्थिति और बिगड़ेगी. मेरा मानना है कि दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है. रिएक्शन कहां से हो रहा है और क्यों हो रहा है, यह सुपर पावर देशों को सोचना चाहिए. अगर ऐसे ही रिएक्शन होते रहे, तो हालात और बिगड़ सकते हैं. तेल के लिए अमेरिका और रूस ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया है. तबाह हुए देशों के कुओं के तेल से अमेरिका और यूरोप रोशन हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इतिहास तय करेगा कि बड़ा आतंकवादी कौन है और कौन नहीं. तेल की भूख़ की वजह से पश्चिमी देशों ने इराक़, लीबिया, सीरिया एवं अफगानिस्तान को पहले ही बर्बाद कर दिया है. पेरिस हमले की समीक्षा करने से पहले यह भी देखा जाना चाहिए कि माचिस की पहली तीली किसने जलाई थी. आजम ने विवाद में एक और पंक्ति जोड़ते हुए विचित्र किस्म की मानवीयता का परिचय दिया. उन्होंने कहा, पेरिस तो नाच-गाने का शहर है, शराबबाजी का शहर है.

भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रांसवा रिचियर ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के बयान से बेहद दु:खी हैं. आजम खान के बयान से उत्तर प्रदेश के लोग भी हतप्रभ हैं कि पेरिस में आतंकियों ने थियेटर, स्टेडियम एवं रेस्तरां समेत आधा दर्जन स्थानों पर वहशियाना हमले कर तक़रीबन डेढ़ सौ लोगों को मार डाला और तीन सौ लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, ऐसी बर्बर घटना पर कोई वरिष्ठ राजनेता इस तरह का अमानवीय बयान कैसे दे सकता है! कांग्रेस ने आजम खान के बयान को निंदनीय करार दिया. हालांकि, कांग्रेस भी मणिशंकर अय्यर एवं सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं से पीड़ित है. अय्यर ने कहा कि पेरिस हमला वहां महिलाओं के हिजाब पहनने पर लगी रोक के कारण हुआ. जबकि सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान जाकर भारत सरकार की खुली निंदा की. अय्यर और खुर्शीद के बयानों की भी कांग्रेस ने निंदा की. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ऐसे बयानों से देश-समाज में ग़लत संदेश जाता है. नेताओं को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए. कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि पेरिस में हुए हमले को किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता. ऐसे बयान देने वाले नेताओं के ख़िलाफ़ पार्टी नेतृत्व को कार्रवाई करनी चाहिए.

भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि लगता है, आजम खान आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं. कहीं उनकी उक्त आतंकी संगठन से साठगांठ तो नहीं है? उन्होंने कहा कि जब भारत में आतंकी हमला हुआ था, तो समूचे विश्व समुदाय ने उसे सांप्रदायिक बताया था. भाजपा सांसद कौशल किशोर ने कहा कि आजम खान जैसे अलगाववादियों को समाजवादी पार्टी ने पनाह दे रखी है. यह समाजवादी पार्टी का हिडेन एजेंडा है. विवादास्पद बयान जारी कराना और फिर उससे पल्ला झाड़ लेना समाजवादी पार्टी की सोची-समझी रणनीति है. उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि जिस तरह दिग्विजय सिंह के बयानों से कांग्रेस की लुटिया डूबी, ठीक उसी तरह आजम खान समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबोएंगे. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह चुके हैं कि आजम का बयान उनका निजी विचार हो सकता है और समाजवादी पार्टी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करती. पेरिस में हुई आतंकी घटना पर अखिलेश अपनी संवेदना और आतंकियों के ख़िलाफ़ अपना आक्रोश पहले ही जता चुके हैं. ■

प्रभात रंजन दीन
feedback@chauthiduniya.com

अमरावती

किसके सपनों की राजधानी

चौथी दुनिया ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की गत 22 अक्टूबर को आधारशिला रखी थी. आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विजयवाड़ा से करीब 30 किलोमीटर और मौजूदा राजधानी हैदराबाद तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सत्ता में आने के बाद ऐलान किया था कि अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी. अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उनकी सरकार ने 28 गांवों की तकरीबन 32 हज़ार एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है. आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय यह तय किया गया था की हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अगले 10 साल तक राजधानी रहेगी. लेकिन 10 वर्ष बाद हैदराबाद पूर्ण रूप से तेलंगाना की राजधानी बन जाएगी, इसी वजह से आंध्र सरकार ने अपनी नई राजधानी को बसाने की योजना पर जल्दी काम शुरू कर दिया. सरकार उम्मीद कर रही है की राज्य की नई राजधानी साल 2024 तक तैयार हो जायेगी. सरकार की 7,317 वर्ग किलोमीटर का राजधानी क्षेत्र बसाये जाने की योजना है, जिसमें से 217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कोर राजधानी क्षेत्र होगा. आंध्र सरकार ने एक जनवरी, 2015 को इसके लिए नोटीफिकेशन जारी कर दिया था. फरवरी के अंत तक सरकार ने 20,150 किसानों से 32,469 एकड़ जमीन हासिल कर ली थी.

अमरावती विजयवाड़ा और गुंटुर जैसे शहरों के बीच में आता है. ये शहर नई राजधानी के डेवलपमेंट में कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं. अमरावती से सटे चार नेशनल हाईवे, एक नेशनल वाटर हाईवे, रेलवे का ग्रैंड ट्रंक रूट, तेजी से बढ़ रहा एयरपोर्ट और एक सीपोर्ट है. ये दोनों शहर को फायदा पहुंचाएंगे. इसका विकास उद्योग और कारोबार के बड़े केंद्र के रूप में भी किया जाएगा. राज्य सरकार का लक्ष्य 2050 तक यहां 50 लाख रोजगार पैदा करना है. 450 साल तक अमरावती का इलाका आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैला हुआ था. नई योजना के तहत इस शहर को ईस्ट कोस्ट पर इसे गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित किया जाएगा.

लेकिन नई राजधानी को बसाने की इस प्रक्रिया में विवाद शिलान्यास के बाद भी आड़े आ रहे हैं, सबसे बड़ा विवाद भूमि अधिग्रहण को लेकर है. इस क्षेत्र में दो तरह की जमीन है एक फसली और बहुफसली. इलाके की दो तिहाई जमीन एक फसली है जबकि एक तिहाई जमीन बहुफसली है. राजधानी बनाए जाने से पहले यहां की एक फसली जमीन की कीमत 10 से 20 लाख रुपये प्रति एकड़ थी, लेकिन नई राजधानी की घोषणा के बाद इनकी कीमत एक करोड़ रुपये हो गई. लेकिन इस इलाके की बहुफसली जमीन की कीमत पहले से ही एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ के आसपास थी, राजधानी बनने की घोषणा के बाद इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया. इस वजह से बहुफसली फसलों वाले किसान अपनी जमीन देने से कतरा रहे हैं. अमरावती का इलाका देश के सबसे उपजाऊ इलाके में से एक है. यहां महज 10–15 फीट नीचे ही भू–जल उपलब्ध है. राजधानी के लिए जिस तीस हज़ार एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है. उसमें से दो तिहाई जमीन एक फसली है जबकि एक तिहाई बहुफसली है. राजधानी के निर्माण के लिए जिस जगह का चयन किया गया है उस दायरे में 28 गांव आते हैं. सरकार ने किसानों से लैंड पूलिंग के जरिए ज़मीन हासिल की है. भारत में यह पहला मौका है जब कोई राजधानी इस तरह लैंड–पूलिंग योजना के तहत बसाई जा रही है. इस योजना के मुताबिक जमीन के मालिकों को जमीन के विकास और उसकी कीमत बढ़ जाने के बाद उसमें हिस्सा मिलेगा. लेकिन इस योजना में सरकार की विस्थापित हो रहे लोगों के पुनर्स्थापना की कोई जिम्मेदारी नहीं है. यह विस्थापित होने वाले लोगों के साथ धोखा है. किसानों ने पूल में अपनी जो कृषि योग्य भूमि दी है उसका लगभग 30 फीसदी हिस्सा उन्हें शहर की महंगी जमीन के तौर पर वापस मिल सकेगा. जिन किसानों ने राजधानी के लिए अपनी ज़मीन देने से इंकार किया उसके लिए आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट की धारा–100 के अंतर्गत प्रावधान किया कि ऐसी परिस्थिति में अथॉरिटी आंध्र प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा के अधिकार और पारदर्शिता अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान है. लेकिन सरकार ने जिस सामाजिक संगठनों का आरोप है कि ऐसे में किसानों पर सरकार ने दबाव बनाकर लैंड पूलिंग के लिए उनसे जगह ली है. उन्डावल्ली, पेनूमक्का, निदामारू, रयापुदी गांव के लोग राजधानी का शिलान्यास हो जाने के बाद भी अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं. नेशनल एलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट के राष्ट्रीय संयोजक भूपति राजू ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी ही चालाकी से राजधानी के लिए ज़मीन अधिग्रहित कर ली है. राजधानी बनाने के लिए जिस क्षेत्र का चुनाव किया गया है उस क्षेत्र में अधिकांश लोग मुख्यमंत्री की जाति के हैं.

चंद्रबाबू ने चालाकी दिखाते हुए नई राजधानी के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में जगह नहीं दी थी. लेकिन सरकार के गठन के बाद उन्होंने किसी दूसरे शहर का चुनाव राजधानी के रूप में करने के बजाय अमरावती में नई राजधानी के निर्माण का निर्णय लिया. उन्होंने नई राधजानी की निर्माण प्रक्रिया स्थानीय लोगों से चर्चा और विचार विमर्श किए बगैर शुरू कर दिया. साथ ही चंद्रबाबू सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजधानी के चयन के लिए पूर्व केंद्रीय शहरी विकास सचिव सी शिवराम कृष्णन की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसाओं को भी दरकिनार कर दिया. इस कमेटी ने राज्य सरकार से कहा था कि वह सावधानी के साथ राजधानी के रूप में उस जगह का चुनाव करे जहां इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध हो. कमेटी ने इतनी उपजाऊ भूमि पर नई राजधानी बनाने के ख़िलाफ सरकार को आगाह किया था. कमेटी ने सलाह दी थी कि पूरी तरह नई राजधानी गढ़ने की बजाय राज्य के मौजूदा शहरों में से ही किसी एक को इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए.

इसके अलावा नेशनल एलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एम जी देवसहायम की अध्यक्षता में अमरावती के इलाके के गांवों का दौरा किया था और पाया था कि इस इलाके में राजधानी के बनने से एक लाख लोग अपनी स्थाई आजीविका के साधन खो देंगे. इसका असर फूड–सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस तरह इतने बड़े पैमाने पर उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण होने से केवल कंक्रीट के जंगल खड़े हो जाएंगे. कमेटी का कहना था कि सरकार के वो दावे भी खोखले हैं, जिस तरह चंडीगढ़ में पिछले साठ सालों में 12 लाख आबादी बढ़ी है. इसलिए सरकार का यह कहना कि जल्दी से यहां का विकास हो जायेगा यह दावा खोखला, इस क्षेत्र का विकास होने में 20 साल से ज्यादा समय लग जायेगा. ऐसे में लैंड पूलिंग के आधार पर किसानों को जितनी विकसित जमीन दी जायेगी, उससे उनका विकास होगा, यह कह पाना अभी मुश्किल है. फिलहाल किसान को 30 हज़ार से 50 हजार रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे पर ही जीवन यापन करना होगा. नेशनल एलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट के संयोजक बी राजू बताते हैं कि किसानों को लैंडपूलिंग के बारे में आज भी सही जानकारी नहीं है उन्हें केवल सरकार ने सुनहरे सब्जबाग दिखाए हैं, लेकिन ऐसे में उनके हाथ कुछ नहीं लगा है. बी राजू का कहना है कि एक व्यक्ति के सपनों की भेंट यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था चढ़ गई है. चंद्रबाबू नायडू सिंगापुर की तर्ज पर नई राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं. जबकि यहां की अपनी अलग जरूरतें और आवश्यकताएं हैं.

चंद्रबाबू नायडू की छवि एक ऐसे नेता की है, जिन्होंने अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में हैदराबाद को विश्वस्तरीय आईटी हब में तब्दील कर दिया. उन्हें उस दौरान सीईओ ऑफ आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता था. इसलिए लोगों को आज भी उनपर पूरा विश्वास है कि वह अमरावती को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में से एक बना पाएंगे. लेकिन आलोचक यह भी कह रहे हैं कि उनके इस सपने को पूरा करने में पूरे प्रदेश का नुकसान भी होगा, प्रदेश के सभी हिस्सों का एकीकृत तरीके से विकास नहीं होगा, प्रदेश सरकार का अधिकांश फंड राजधानी के निर्माण कार्यों की ओर मूड़ जाएगा. ऐसे में चंद्रबाबू को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अपनी विकास योजनाओं को हैदराबाद के इर्दगिर्द सीमित कर लिया था, इसी वजह से उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा था. दस साल बाद वह सत्ता में वापस लौटे हैं यदि वह पुरानी गलतियों को फिर से दोहराते हैं तो उनके लिए उसी तरह की समस्याएं फिर से उठ खड़ी होंगी. इस बार चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लग रहे हैं कि वह रियल इस्टेट कारोबारियों के एजेंट बन गए हैं. इसके लिए वे तर्क देते हैं कि यदि नए भूमि अधिग्रहण क़ानून के अंतर्गत वह भूमि अधिग्रहित करते तो इतनी मात्रा में भूमि अधिग्रहित नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें केवल सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रावधान है.

इस क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को सरकार ने 2500 रुपये प्रतिमाह दे रही है. साथ ही उसने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पूरे साल रोजगार उपलब्ध कराने और क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखने की बात कह रही है. इसके साथ उसकी यहां के लोगों के कौशल विकास की भी योजना है, ताकि भविष्य में उन्हें राजधानी निर्माण के कार्य में बेहतर कार्य मिल सके. लेकिन बी राजू कहते हैं कि इस क्षेत्र का किसान पहले संपन्न था सरकार ने उनसे जमीन छीनकर उन्हें भूमिहीन मजदूर में तब्दील कर दिया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

तस्वीरों में यह सप्ताह

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय / सुनील मल्होत्रा*

पतंजलि नूडल्स की लॉन्चिंग के मौक़े पर बाबा रामदेव.

छठ पर्व के दौरान इंडिया गेट पर पूजा–आराधना करतीं महिलाएं.

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की 125वीं जयंती के मौक़े पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी.

टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के विरोध में जंतर–मंतर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हिंदू सेना के कार्यकर्ता.

पेरिस हमले में मारे गए लोगों को इंडिया गेट पर दी गई श्रद्धांजलि.

आईएस के ख़िलाफ़ नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते मुस्लिम संगठन.

18 महीने के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह 30वां विदेश दौरा था. मोदी ने 26 मई, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी. 14 नवंबर, 2015 तक के इन 537 दिनों में से अब तक वे कुल 30 विदेश यात्राएं कर चुके हैं. वह 12 से 14 नवंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर थे. यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार और महागठबंधन की जीत और भाजपा के अन्तर्कलह, कुलबुर्गी और अखलाक की हत्या के बाद असहिष्णुता के बहस और लेखकों एवं कलाकारों के पुरस्कार लौटाने की पृष्ठभूमि में हुआ था.

पीएम का ब्रिटेन दौरा

समझौतों पर अमल कब

चौथी दुनिया ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय बहुप्रचारित ब्रिटेन यात्रा के दौरान कई रंग देखने को मिले. ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने मोदी का भरपूर स्वागत किया. वेम्बली स्टेडियम में मोदी को देखने उपस्थित भारी भीड़ से एक बार फिर लोगों के दिलोदिमाग में अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर की याद ताज़ा हो गई. दूसरी तरफ कैमरन के साथ पीएम मोदी के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश मीडिया ने गुजरात दंगों से चुभते सवाल भी किए. मोदी के ब्रिटेन दौरे के दौरान कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी इस तरह के प्रदर्शन हुए थे, लेकिन वहां उसे उतनी कवरेज नहीं मिली. यह पहला मौक़ा था, जब उनकी किसी विदेश यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शनों की इतनी चर्चा हुई. वेस्टमिन्स्टर बिल्डिंग पर आवाज़ डॉट कॉम की तरफ से मोदी नॉट वेलकम (मोदी का स्वागत नहीं है) को प्रोजेक्टर से दिखाया गया. इसके अलावा मोदी के खिलाफ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सिख, कश्मीरी, दलित, महिलाएं और छात्रों के साथ-साथ नेपाली और श्रीलंकाई मूल के लोग भी शामिल हुए. सही मायने में देखा जाए तो ब्रिटेन का भारतीय समुदाय मोदी के स्वागत और विरोध अर्थात दोनों ओर बंटा दिखा. बहरहाल, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते भी हुए. प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश संसद के रॉयल गैलरी में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित किया. ब्रिटेन की रानी ने बकिंघम पैलेस में उन्हें भोज भी दिया. वेम्बले स्टेडियम में खूब धूमधाम भी रही. लेकिन सवाल यह है कि इस दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ?

बहरहाल, 18 महीने के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह 30वां विदेश दौरा था. मोदी ने 26 मई, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी. 14 नवंबर, 2015 तक के इन 537 दिनों में से अब तक वे कुल 30 विदेश यात्राएं कर चुके हैं. वह 12 से 14 नवंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर थे. यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार और महागठबंधन की जीत और भाजपा के अन्तर्कलह, कुलबुर्गी और अखलाक की हत्या के बाद असहिष्णुता के बहस और लेखकों एवं कलाकारों के पुरस्कार लौटाने की पृष्ठभूमि में हुआ था. पहले से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि ब्रिटेन में बसे प्रवासी भारतीय मोदी से इस बार असहिष्णुता पर सवाल करेंगे और ऐसा हुआ भी. ब्रिटिश मीडिया ने भी असहिष्णुता के मसले पर तीखे सवाल किए. वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असहिष्णुता पर अपनी सरकार का रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि भारत में हो रही हर घटना मायने रखती है, चाहे वह छोटी से छोटी ही घटना क्यों न हो. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुद्ध और गांधी की धरती है, जहां हर व्यक्ति और उसके विचारों की सुरक्षा काफी अहमियत रखती है. सभी तरह के विचारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है. हमारे देश के यही मूल्य हैं, इसलिए ऐसे मूल्यों के खिलाफ कोई भी बात स्वीकार नहीं की जा सकती है.

भारत-ब्रिटेन में समझौते

विरोध प्रदर्शन से अलग, भारत और ब्रिटेन के बीच कई समझौते भी हुए. ब्रिटेन और भारत के प्रधानमंत्रियों ने असैनिक परमाणु सहयोग जैसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए. ब्रिटेन ने भारत में तीन स्मार्ट शहरों के निर्माण का सौदा भी किया और दोनों देशों के बीच 9 अरब पाउंड के व्यापार पर रज़ामंदी हुई. ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिटेन के साथ हमारे गहरे रिश्ते रहे हैं. मोदी ने कैमरन सरकार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर ब्रिटेन के समर्थन देने पर आभार भी जताया. ब्रिटेन के साथ क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौता हुआ. पीएम ने रक्षा व्यापार पर कहा कि रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया के तहत ब्रिटेन इसमें प्रमुख भागीदार होगा. ब्रिटेन में भारत तीसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है.

9 अरब पाउंड के व्यापार के समझौते में वोडाफोन भारत में अपने नेटवर्क के फैलाव और सुधार के लिए 1.3 अरब पाउंड खर्च करेगा, जिसके तहत पुणे और हैदराबाद में टेक-सेंटर बनाना शामिल है. लाइट सोर्स अगले पांच वर्षों में 3जीडब्लू सौर्य ऊर्जा के उत्पादन के लिए 2 अरब पाउंड का निवेश करेगा, जिसमें भारत और ब्रिटेन में 300 नौकरियों का सृजन होगा. इंटेलीजेंट एनर्जी ने 27,400 टेलीकॉम टावरों के लिए क्लीन एनर्जी आपूर्ति के लिए 1.2 अरब पाउंड का निवेश करेगा. किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल फाउंडेशन ट्रस्ट और इंडो-यूके हेल्थकेयर चंडीगढ़ में एक अस्पताल स्थापित करेंगे. यह भारत-यूके के बीच 11 अस्पतालों में से पहला अस्पताल होगा, जिस पर 1 अरब पाउंड की लगत आएगी. इंडिया बुल्स ब्रिटिश स्टार्ट-अप बैंक ओकनार्थ में 6 करोड़ 60 लाख पाउंड का निवेश करेगा. एस बैंक और लन्दन स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के बांड और शेयर जारी करने के समझौते किये हैं. भविष्य में 30 करोड़ रुपये के ग्रीन बांड जारी करने पर भी सहमती बनी है.

जहां तक ब्रिटेन द्वारा भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता की मांग के समर्थन का सवाल है तो यह एक अच्छी खबर है, लेकिन भारत की यह मांग उस वक़्त तक नहीं पूरी हो सकती, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सारे स्थाई सदस्य इसके लिए सहमत नहीं हो जाते, लेकिन फिर ब्रिटेन का भारत के समर्थन में आना दोनों देशों के बीच के संबंधों की गर्माहट की तरफ इशारा करता है.

विरोध प्रदर्शन भी कम नहीं

प्रधानमंत्री की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन की शुरुआत लंदन से हुई. लंदन में विरोध प्रदर्शनों की कवरेज भी वहां के मीडिया ने प्रमुखता से की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभवतः यह पहली विदेश यात्रा रही, जिसमें उनके आधिकारिक कार्यक्रम, स्वागत कार्य़क्रम के साथ-साथ उनके विरोध के कार्यक्रमों की इतना चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में भी

अच्छी-खासी संख्या में लोग सड़क पर उतरे. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को 200 जाने-माने लेखकों ने पत्र लिखकर मांग की कि वह भारतीय प्रधानमंत्री से भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करने की बात करें. अपील करने वालों में सलमान रुश्दी, नील मुखर्जी, मेगी गिब्सन, इयान मक्विन जैसे प्रसिद्ध लेखक भी शामिल थे. पेन इंटरनेशनल संस्था के लेटरपैड पर दिए गए इस पत्र को ब्रिटेन के बुद्धिजीवी तबके में भारत में राजनीतिक हिंसा और नफरत के खिलाफ बयान के तौर पर देखा गया. इसके अलावा 12 नवंबर को आवाज नेटवर्क, साउथ एशिया सॉलिडेरिटी, फ्रीडम विदाउट फीयर, कास्ट वॉच यूके, न्यू हैम एशियन वूमेन प्रोजेक्ट सहित सिख फेडरेशन यूके, साउथहॉल ब्लैक सिस्टर्स, दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क यूके, इंडियन मुस्लिम फेडरेशन, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, मुस्लिम पार्लियामेंट और वॉइस ऑफ़ दलित इंटरनेशनल जैसे कई संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. 8 नवम्बर को वेस्टमिन्स्टर बिल्डिंग पर आवाज़ डॉट ऑर्ग की तरफ से मोदी नॉट वेलकम (मोदी का स्वागत नहीं है) का सन्देश प्रोजेक्टर से दिखाया गया. इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वास्तिक की पृष्टभूमि में एक तलवार लिए हुए दिखाया गया था. इस सम्बन्ध में ब्रिटिश संसद बॉब ब्लैकमैन का कहना था कि आवाज़ ने इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली थी. उस सांसद ने इस मामले को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में उठाया और कहा कि दोषियों को पकड़ा जायेगा. इसे पहले ब्रिटेन के 40 सांसदों ने अर्ली डे मोशन पर हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री कैमरन से मांग की थी कि वह मानवाधिकार के मसले को मोदी के साथ उठायें. गौरतलब है कि हस्ताक्षर करने वालों में लेबर नेता जेरेमी कोर्बिन भी शामिल थे.

द गार्जियन अख़बार में छपे अपने पत्र में शिक्षाविदों के एक गठबंधन ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे असहिष्णुता और हमलों की तरफ इशारा किया. उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि मोदी के मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री शामिल हैं, जिनके विरुद्ध बलात्कार और अपराधिक मामले दर्ज हैं. इन शिक्षाविदों ने आरएसएस के महिला विरोध और अल्पसंख्यक विरोध का भी ज़िक्र किया है. जैसा कि पहले ज़िक्र किया जा चुका है कि मोदी के पिछले दौरों में भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ कि इन प्रदर्शनों को इतनी कवरेज मिली. जहां इन प्रदर्शनों में असहिष्णुता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा शामिल था, वहीं पहली बार नेपाल के लोगों ने नए संविधान के लागू होने के बाद नेपाल के प्रति भारत के रवैये के विरोध में मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया.

ज़बरदस्त स्वागत

इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस दौरे पर जहां उनके खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन हुए, अख़बारों में आलोचनाएं हुईं, वहीं उनका ज़बरदस्त स्वागत भी किया गया. ब्रिटेन पार्लियामेंट के रॉयल गैलरी में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करने वाले और ब्रिटेन की महारानी के बकिंघम पैलेस में दावत खाने वाले वह भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं. उन्होंने अपने पार्लियामेंट के संबोधन में भारत और ब्रिटेन के पुराने रिश्तों की बात की. वहीं दोनों देशों के बीच कई समानताएं भी गिनवाईं. जहां एक तरफ क्रिकेट का हवाला दिया, वहीं भारत के अंग्रेजी उपन्यासकारों का भी हवाला दिया. अपने भाषण में उन्होंने कई बातें मजाकिया अंदाज़ में भी कहीं. जैसे बेंड इट लाइक बेकहम और भांगड़ा फ्रॉम लन्दन. उनके भाषण से गैलरी में मौजूद लोग भी लुत्फ़ ले रहे थे. ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी भारतीय प्रधानमंत्री के आवाभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी. मोदी के स्वागत में रॉयल एयरफोर्स के रेड एरो विमानों के धुएं से आसमान में भारतीय तिरंगा बनाया गया.

दूसरी तरफ लन्दन स्थित वेम्बली स्टेडियम में भारतीय समुदाय ने एक बार फिर उनके स्वागत में अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर का नज़ारा पेश किया और विदेशों में जहां भारतीय समुदय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, वहां उनकी रॉक स्टार की छवि बरक़रार रही. भले ही उनके कार्यक्रम के दिन कुछ सीटें खली हों, लेकिन उनके कार्यक्रम के लिए कुल 60,000 टिकटें बुक हो चुकी थीं. यहां भी डेविड कैमरन ने मोदी को खुश करने का मौक़ा नहीं छोड़ा और मोदी विरोधियों पर हमला करने से भी नहीं चुके. उन्होंने कहा कि वे (मोदी विरोधी) कहते थे कि कोई चायवाला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नहीं चला सकता, लेकिन ऐसा हो गया. कैमरन यहीं नहीं रुके, उन्होंने भाजपा के चुनावी नारे अच्छे आने वाले हैं, को भी यहां दोहराया. उन्होंने हिंदी में कहा कि अच्छे दिन ज़रूर आयेंगे. स्टेडियम में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत एक रॉक स्टार की तरह ही किया.

अब सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह दौरा कैसा रहा? यह तो आसानी से कहा जा सकता है कि यह दौरा भी उनके दूसरे देशों के दौरे की तरह ही था. यहां भी उनका पुरजोर स्वागत किया गया. भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनके लिए अपनी आंखें बिछाईं, विदेशी निवेश और व्यपार के ढेरों समझौते हुए. सिविल न्यूक्लियर डील हुए. आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर बातें हुईं. इस दौरे में एक और अहम बात यह हुई कि ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता की मांग का खुलकर समर्थन किया. इस दौरे में भी मोदी दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब हुए, लेकिन जबतक ज़मीनी सतह पर इन समझौतों पर कार्यान्वयन नहीं होता, तब तक इन दौरों की सफलता का दावा करना शायद जल्दबाज़ी होगी.

बहरहाल, मौजूदा दौरे का एक और दिलचस्प और अहम पहलू देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है. बिहार में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई थी. ये चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े गए थे. लिहाज़ा, चुनाव में पराजय के बाद उनकी पार्टी के अन्दर उनका विरोधी खेमा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है. पार्टी में हाशिये पर पड़े नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पहली बार खुल कर बोलना शुरू किया है. ऐसे नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम शामिल हैं. ज़ाहिर है, ऐसे में अपनी ही पार्टी में आलोचनाओं से घिरे प्रधानमंत्री के लिए यह दौरा एक राहत की सांस की तरह था, लेकिन अभी पार्टी के अंदर की अन्तःकलह धीमी ज़रूर हुई है, लेकिन शांत नहीं हुई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोराका

बिहार की भलाई के लिए काम करे नई सरकार

दूसरी महत्वपूर्ण बात है नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की. उनके पांच वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत हो गई है. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था. उसके साथ ही सभी बड़े कल-कारखाने झारखंड में चले गए थे, जैसे बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट एवं कोल इंडिया लिमिटेड आदि. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने चुनावी भाषण में कहा था कि झारखंड में ऊर्जा की खपत अधिक है, जबकि बिहार में कम है. बिहार में ऊर्जा की खपत झारखंड से अधिक कैसे हो सकती है, जो कि बुनियादी तौर पर कृषि पर निर्भर है?

बीते दिनों की सबसे बड़ी ख़बर पेरिस की भयानक घटना रही, जिसे लेकर विभिन्न समीक्षकों ने अलग-अलग अटकलें लगाईं कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था? असल दोषियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. असल तथ्य, जो आसानी से समझ में आता है, वह यह है कि ऐसी घटनाएं अमेरिका द्वारा अफ़ग़ानिस्तान एवं इराक में अंजाम दी गई कार्रवाई की उपज हैं. यहां इतिहास पर एक नज़र डाल लेना अनुचित नहीं होगा. वर्ष 1956 में मिस्र के साहसी राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने एक लोकप्रिय नायक की तरह स्वेज़ नहर का दौरा किया और वहीं पर स्वेज़ नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी. इस बात को लेकर ब्रिटेन और फ़्रांस काफी क्रोधित हुए, क्योंकि स्वेज़ नहर का संचालन ब्रिटेन के हाथों में था. ब्रिटेन, फ़्रांस एवं इजराइल ने अपने फौजें वहां भेज दीं और उन्होंने अमेरिका के समर्थन को हलके में लिया. हालांकि, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जनरल डोवाईट आइजनेहावर थे, जिन्होंने विश्व युद्ध को वर्ष 1945 में समाप्त होते हुए देखा था. उन्होंने बिल्कुल सही मशविरा दिया. उनका कहना था कि नासिर ने जो किया, वह बिल्कुल ग़लत है, लेकिन फौजी कार्रवाई करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पूरी अरब दुनिया पश्चिम की दुश्मन बन जाएगी और यह बुद्धिमत्ता वाला फ़ैसला नहीं होगा. अनेक अमेरिकी राष्ट्रपतियों की प्रशंसा उनके कामों के लिए की जाती है, लेकिन मेरे विचार में डोवाईट आइजेनहावर के वर्ष 1956 के बुद्धिमत्ता भरे फ़ैसले को उतना महत्व नहीं दिया गया, जितना उसे मिलना चाहिए था.

आइजेनहावर वर्ष 1956 में जो स्थिति टालने में कामयाब रहे थे, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाई करके उसी जाल में फंस गए, पहले अफ़ग़ानिस्तान और उसके बाद इराक में, जिसकी वजह से निश्चित रूप से मुस्लिम दुनिया या अरब दुनिया में गुस्सा पैदा हुआ. मैं पेरिस हमले में शामिल लोगों का पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर हम सभी इस बात पर सहमत होंगे कि शांति या शत्रुता का एक ऐसा वातावरण तैयार करने की ज़रूरत है, जिसमें हम सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे. भारत के पास ऐसे विकल्प या अवसर नहीं हैं कि हम शांति या शत्रुता में से किसी एक का चुनाव कर सकें. अगर हम दुनिया पर एक नज़र डालें, तो पाएंगे कि भारत सबसे शांत देशों में से एक है. भारतीय मुसलमान स्वयं को निश्चित रूप से मध्य पूर्व के मुसलमानों से अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे. बदक़िस्मती से भारत में सत्ताधारी दल को इतिहास का कम ज्ञान है और उसे हमारी हालत की गंभीरता का एहसास नहीं है. हम बीफ़ खाने या न खाने, यूनिफार्म सिविल कोड और ऐसी ही दूसरी ग़ैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं. अब समय आ गया है कि देश की शांति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए हमारे वश में जो भी हो, उसे किया जाए. इस सिलसिले में जो सबसे पहली अपेक्षा है, वह है सामाजिक सामंजस्य. मैं दलाई लामा के उस बयान से सहमत हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव ने साबित किया है कि भारत के लोग भाईचारा चाहते हैं. बेशक, भाजपा और उसके समर्थकों ने दलाई लामा की आलोचना की, लेकिन मेरे ख़्याल से यह हालत का सही आकलन है.

चुनाव आते हैं, कुछ लोग जीतते हैं और कुछ हारते हैं, लेकिन

> विडंबना यह भी है कि हम अपनी तुलना इस्लामी सभ्यता से करने लगते हैं, जिसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई थी. इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, की सूची है. हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है. वेदों, श्रीमद् भगवद् गीता या दूसरी किताबों में खाने-पीने का आकलन सिर्फ़ इतना है कि कुछ भोजन सात्विक होते हैं, कुछ तामसी और कुछ राजसी. लेकिन, कोई यह नहीं कहता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अपने व्यवसाय के लिहाज से अगर आप मेहनती हैं, तो तामसी भोजन लीजिए और अगर आप बहुत काम नहीं करते, तो सात्विक रहिए. लेकिन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, का कोई प्रावधान नहीं है. यह हिंदू धर्म की बुनियादी पहचान है. अब हमारा पाला एक नए तरह के हिंदुत्व से पड़ रहा है, जो आपको अधिक आक्रामक बनना चाहता है. हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे नाराज़ बंधुओं में, चाहे वे पेरिस में हों या अमेरिका, इराक एवं अफ़ग़ानिस्तान में हों, बेहतर भावना व्याप्त होगी. जितनी जल्दी सभी लोग अपनी ऊर्जा मानवता की भलाई के लिए मेहनत करने में लगाएंगे, उतना ही बेहतर होगा.

दूसरी महत्वपूर्ण बात है नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की. उनके पांच वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत हो गई है. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था. उसके साथ ही सभी बड़े कल-कारखाने झारखंड में चले गए थे, जैसे बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट एवं कोल इंडिया लिमिटेड आदि. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने चुनावी भाषण में कहा था कि झारखंड में ऊर्जा की खपत अधिक है, जबकि बिहार में कम है. बिहार में ऊर्जा की खपत झारखंड से अधिक कैसे हो सकती है, जो कि बुनियादी तौर पर कृषि पर निर्भर है? बहरहाल, नीतीश कुमार को अपने इस कार्यकाल में सभी तथ्यों को सामने रखते हुए सोचना चाहिए कि बिहार की भलाई के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में आप स्टील प्लांट नहीं लगा सकते, लेकिन चीनी उद्योग लगा सकते हैं, जो वहां पहले से मौजूद है. दूसरे उद्योग-धंधों, जिनके लिए कच्चा माल मौजूद है, बाज़ार मौजूद है, उनके बारे में सोचा जा सकता है. कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना बिहार के लिए लाभदायक साबित होगा. मनमोहन सिंह के दस वर्षों के शासनकाल में कृषि की उपेक्षा हुई है. मौजूदा सरकार भी कृषि की बात नहीं कर रही है. मेक इन इंडिया और एफडीआई की बहस के बीच अगर कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया, तो दस वर्षों के बाद एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. बहरहाल, बिहार की नई सरकार को शुभकामनाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

बिहार देश के लिए नई राह खोलेगा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी शान के साथ शपथ ली, लेकिन उतनी ही शान के साथ उनके सामने चुनौतियां का पहाड़ खड़ा है. नीतीश कुमार को उनमें से कुछ चुनौतियों का एहसास भी है, पर शायद जब वह अपना एजेंडा तय करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों का महत्व क्या है, उनकी गंभीरता क्या है और उनकी आवश्यकता क्या है? पिछले दिनों नीतीश कुमार जी के साथ कई दौर की बातचीत हुई. उस बातचीत में नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के कुछ दूसरे पहलू सामने आए, लेकिन उन सारे आयामों का परीक्षण अभी बाकी है.

नीतीश कुमार के बारे में कुछ सालों तक माना जाता रहा कि वह अहंकारी हैं, वह अपने सांसदों एवं विधायकों से मिलते नहीं हैं और जब मिलते हैं, तो इस तरह बात करते हैं, जैसे उन्हें बातचीत समाप्त करने की जल्दी है. शायद इसी छवि ने उन्हें बिहार में उनके अपने दल के भीतर अलोकप्रिय साबित कर दिया. लेकिन, अब लगता है कि शायद नीतीश कुमार के लिए उस रुख़ का अपनाना आवश्यक था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते, तो बिहार के विकास की रूपरेखा बन ही नहीं पाती. बिहार में यह माना जा रहा था कि राज्य को विकास के दरें पर लाना लगभग नामुमकिन है और उस नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का काम नीतीश कुमार ने किया. शायद इसीलिए किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव को, चाहे वह पार्टी के अंदर का रहा हो या फिर बाहर का, उन्होंने अपने रास्ते में आने नहीं दिया और इसी का परिणाम है कि इस बार उनके नेतृत्व में बिहार में महा-गठबंधन की दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत से जीत हुई है और उनके सहारे कांग्रेस का पुनर्जन्म भी हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को साथ लेने का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं का था.

अभी नीतीश कुमार के सामने पहली राजनीतिक चुनौती राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ समरसता बैठाने की है. नीतीश कुमार को इस बात का अंदाज़ा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का मनोविज्ञान और उनके अपने दल का मनोविज्ञान लगभग एक लय में है. चुनौतियों का एहसास लालू यादव को भी है और नीतीश कुमार को भी. पर यह समरसता बनाए रखने की जितनी ज़िम्मेदारी लालू यादव की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदारी नीतीश कुमार की है. बहुमत अपार मिला, लेकिन अगर दोनों दलों के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलने के बाद उसका सार्थक परिणाम सामने न आया और नीतीश कुमार ने उन्हें साथ चलने के लिए प्रेरित या मजबूर न किया, तो यह सार्थक पहल बहुत जल्दी निरर्थक प्रयास में बदल जाएगी. कांग्रेस का मनोविज्ञान नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं पता. कांग्रेस के लोग बिहार में कैसा रुख अपनाते हैं और उसका असर दिल्ली में राहुल गांधी के ऊपर क्या होता है, यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है.

बिहार के विकास की नई नीति बनाना नीतीश कुमार के लिए आवश्यक है और उस नई नीति में स्पष्ट प्राथमिकता बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को मिलनी चाहिए. अगर नीतीश कुमार इन चारों को बुनियाद बनाकर योजना बनाते हैं, तो वह बिहार के लोगों के उस जनादेश का सम्मान करेंगे, जिसने उन्हें इतना बड़ा अवसर दिया है. रोज़गार के अवसर दूसरा चरण दे सकता है, बशर्ते पहले चरण को नीतीश कुमार सफलतापूर्वक अमल में ले आएं. रोज़गार के अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम यह हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के प्रत्येक ब्लॉक को, प्रखंड को केंद्र बनाकर छोटे-छोटे उद्योगों की शृंखला डाल सकें, तो वह देश के लिए आर्थिक योजना का भी एक नया खाका पेश कर सकते हैं. देश की अर्थनीति बाज़ार आधारित है और 70 प्रतिशत लोगों के ख़िलाफ़ है. अगर बिहार में नीतीश कुमार जन-आधारित विकास या रोज़गार की योजना बनाते हैं, तो इसे नीतीश कुमार से ज़्यादा और कोई नहीं जानता कि वह उन्हें इतिहास पुरुष के रूप में परिवर्तित कर सकती है.

लेकिन, इन सबके बावजूद नीतीश कुमार के सामने धन की कमी आने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से विकास के लिए पैसा नहीं निकाल पा रही है. वह बेहिसाब टैक्स बहाने-बहाने से लगा रही है और देश के लोगों के सामने अपना योजना विहीन चेहरा रख रही है. जिन चीज़ों के लिए वह टैक्स लगा रही है, उनके संबंध में उसकी घोषणाएं ऐसी नहीं थीं कि उन्हें पूरा करने के लिए लोगों के ऊपर करों का बोझ बढ़ेगा. नतीजतन, डेढ़ साल के भीतर किसी भी योजना में दांवागत परिवर्तन होना नहीं दिखाई दिया. हो सकता है कि परिवर्तन 10 सालों के बाद दिखाई दे, लेकिन तब तक एक पीढ़ी जवानी से बुढ़ापे की ओर चली जाएगी और एक पीढ़ी दुनिया से चली जाएगी.

> नीतीश कुमार के बारे में कुछ सालों तक माना जाता रहा कि वह अहंकारी हैं, वह अपने सांसदों एवं विधायकों से मिलते नहीं हैं और जब मिलते हैं, तो इस तरह बात करते हैं, जैसे उन्हें बातचीत समाप्त करने की जल्दी है. शायद इसी छवि ने उन्हें बिहार में उनके अपने दल के भीतर अलोकप्रिय साबित कर दिया. लेकिन, अब लगता है कि शायद नीतीश कुमार के लिए उस रुख़ का अपनाना आवश्यक था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते, तो बिहार के विकास की रूपरेखा बन ही नहीं पाती.

इसलिए नीतीश कुमार के सामने बिहार में चुनौती सिर्फ़ बिहार की नहीं है. देश के सामने बिहार के विकास का मॉडल रखना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है. मैं यह आशा कर सकता हूं कि नीतीश कुमार इस चुनौती को न सिर्फ़ समझेंगे, बल्कि स्वीकार करेंगे और इसका सामना करने के लिए एक सर्वांगीण रणनीति बनाएंगे तथा अपने मंत्रियों को उस पर चलने के लिए मजबूर भी करेंगे. नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि वह बिहार में विकास के लिए पैसा कहां से लाते हैं. मुझे बिहार का सर्वांगीण आर्थिक विकास हो और वहां के लोगों को रोज़गार मिले. यह असंभव काम नहीं है, लेकिन यह असंभव तब हो जाएगा, जब वह नौकरशाहों को ढीला छोड़ देंगे.

श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनाव में अपने मुक़ाबले नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया और देश के लोगों को बता दिया कि बिहार में अगर नीतीश कुमार हारते हैं, तो उनके (नरेंद्र मोदी) विचारों की विजय होगी और देश उस पर चलेगा. लेकिन, अगर नीतीश कुमार जीतते हैं, तो यह उनकी (नरेंद्र मोदी) पराजय होगी. उनके सारे वक्तव्यों का सार यही निकलता है, उनकी सारी भाषा का निष्कर्ष यही निकलता है. अब बिहार में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के मुक़ाबले जीते हैं, लेकिन इस जीत के भीतर छिपी चुनौतियां विजय का समारोह मनाने की धुंध में नज़रअंदाज़ नहीं होनी चाहिए. इस विजय से मिली ज़िम्मेदारियों एवं चुनौतियों के माध्यम से नीतीश कुमार को सारे देश में ऐसे जननेता के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, जो देश की चुनौतियों का हल बिहार की प्रयोगशाला में तलाश कर उसका लोक कल्याणकारी स्वरूप विकसित करे.

इनमें से नीतीश कुमार को कई सारी चीज़ों का एहसास होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें हमेशा यह याद दिलाएं कि सिर्फ़ एहसास होने से रास्ते नहीं मिला करते, रास्ते चलने पर मिला करते हैं. अब जबकि वह अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ले चुके हैं, तो उन्हें अपना एक भी मिनट देश के लोगों के कल्याणार्थ किए जाने वाले फ़ैसलों का मूर्त स्वरूप बिहार में निर्मित करने के अलावा इधर-उधर नहीं लगाना चाहिए. राजनीतिक लड़ाई का फ़ैसला हो चुका, पर उस राजनीतिक लड़ाई को लोगों की जीत में बदलने का काम अभी बाकी है. यह काम नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के नेता साथ मिलकर करेंगे. ऐसी आशा तब तक करनी चाहिए, जब तक यह न लगने लगे कि राजनेताओं से ज़्यादा आशाएं करना स्वयं को छलावे में डालना है. इस बार बिहार में लोगों को छलावा न मिले, बिहार सारे देश के लिए विकास का एक अद्भुत मॉडल बनकर उभरे, ऐसी कामना हम देश के लोगों के हित में अवश्य करते हैं और नीतीश कुमार से यह कामना पूरी करने की ज़िम्मेदारी निभाने की अपेक्षा भी करते हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

खादी अब ग़रीबों को लूटने के लिए है-अंतिम

गांधी के नाम पर काला कारोबार

पिछले ढाई साल में मज़दूरों ने सारे दरवाजे खटखटा लिए हैं. 26 जनवरी को उन्होंने परतंत्र दिवस मनाया. पर उनके तमाम आवेदनों-प्रतिवेदनों की कोई सुनवाई नहीं हुई. उल्टे मीटिंग करने जा रहे मज़दूरों को गुंडों ने एसडीएम तथा कोतवाल के सामने ही पीटा, उनकी चौकी उठाकर फेंक दी. एक फरवरी, 1983 को गोरखपुर में गोलघर गांधी आश्रम पर मज़दूरों ने प्रदर्शन किया, तो उन पर पत्थरों और खाली बोतलों की वर्षा हुई. गांधी आश्रम की छत से गोलियां भी चलीं. 12 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए. मज़दूरों पर इस हमले के एक घंटे के बाद पुलिस पहुंची, जबकि गोलघर गोरखपुर का केंद्रीय बाज़ार है. आश्रम से अनेक बंदूकें, रिवॉल्वर और कट्टे बरामद हुए. धारा 307 के तहत आश्रम में उपस्थित 110 लोगों की गिरफ्तारी की गई. घायल श्रमिकों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 395 के तहत मुकदमा कायम किया.

फिलहाल स्थिति यह है कि लगभग 40 श्रमिकों ने माफी मांग ली है और उन्हें काम पर ले लिया गया है. उनमें से कुछ का स्थानांतरण कर दिया गया है तथा शेष

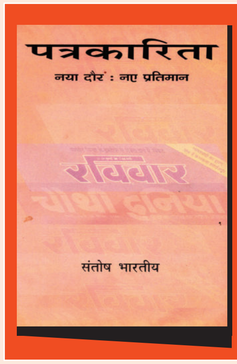

> आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

> आश्रम में चार लाख के लगभग सालाना मुनाफ़ा होता है तथा चार करोड़ से ज़्यादा की सालाना बिक्री. बाहर से चीजें मंगाकर उनकी क़ीमत बढ़ा दी जाती है और इस तरह भी मुनाफ़ा कमाया जाता है. अब तक व्यवस्थापकों एवं अधिकारियों के वेतन की सीमा एक हज़ार रुपये थी, पर दो वर्षों से यह सीमा समाप्त कर दी गई है. ट्रस्टी मंडल जो भी तय करेगा, वही उनका वेतन होगा. बहुत पूछने पर भी व्यवस्थापकों एवं अधिकारियों का वेतन नहीं बताया गया. शोषण और दमन की यह कहानी केवल एक खादी केंद्र, मगहर की है, पर मगहर जैसे केंद्र बहुत-से हैं. हज़ारों श्रमिक बंधुआ स्थिति में, अमानवीय स्थिति में काम करने को बाध्य हैं.

के साथ बहुत निर्दयतापूर्ण व्यवहार हो रहा है. फंड का सारा पैसा, 400 मज़दूरों की एक महीने की तनख्वाह, पहरे का पैसा वगैरह आश्रम पर बाकी है. खाली जगहों पर व्यवस्थापकों ने अपने रिश्तेदारों की भर्ती कर ली है. हड़तालियों में अब तक चार हरिजन श्रमिक-माले, राम आसरे, हरिद्वार केवट एवं कृपाल गरीबी व भूख के कारण मर चुके हैं. एक अन्य कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है. मज़दूर जब भी शिव कुमार पांडे के पास जाते हैं, उनका एक ही जवाब होता है, इंदिरा गांधी से काम मांगो.

व्यवस्थापकों का पक्ष क्या है? गांधी आश्रम में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आश्रम के सहायक स्टोर इंचार्ज राम मूर्ति चौधरी से मुलाकात हुई. उन्होंने पूरा आश्रम घुमाकर दिखाया. आश्रम की तमाम स्थितियां मज़दूरों के आरोपों की पुष्टि कर रही थीं. अंदर छह तेलघानी थे, जिन्हें केवल दो आदमी चला रहे थे. घास छीलने जाते व चारा काटते मज़दूर भी मिले. साबुन भट्ठी, रंगाई-धुलाई सभी जगहों पर मज़दूर अमानवीय स्थितियों में काम कर रहे थे. आश्रम में मंत्री शिव कुमार पांडे तो नहीं मिले, लेकिन व्यवस्थापक पुरुषोत्तम तिवारी और जय नारायण तिवारी से ज़रूर भेंट हो गई. उनके अनुसार, मगहर पांच ज़िलों के खादी भंडारों का क्षेत्रीय कार्यालय है. पांचों ज़िलों में कुल 700 कार्यकर्ता हैं. ये पांच ज़िले हैं, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच एवं लखनऊ. इन लोगों के अनुसार, कार्यकर्ताओं की कोई श्रेणी नहीं है तथा किसी भी कर्मचारी को कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है. जब मैंने पूछा कि वेतन इतना कम क्यों है, तो उनका उत्तर था कि यहां वेतन आमदनी से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि बेरोज़गारी की समस्या का हल हो. आश्रम में सारा काम ठेके पर होता है, ऐसा क्यों? जय नारायण तिवारी का कहना था, इससे काम ज़्यादा होता है.

आश्रम में चार लाख के लगभग सालाना मुनाफ़ा होता है तथा चार करोड़ से ज़्यादा की सालाना बिक्री. बाहर से चीजें मंगाकर उनकी क़ीमत बढ़ा दी जाती है और इस तरह भी मुनाफ़ा कमाया जाता है. अब तक व्यवस्थापकों एवं अधिकारियों के वेतन की सीमा एक हज़ार रुपये थी, पर दो वर्षों से यह सीमा समाप्त कर दी गई है. ट्रस्टी मंडल जो भी तय करेगा, वही उनका वेतन होगा. बहुत पूछने पर भी व्यवस्थापकों एवं अधिकारियों का वेतन नहीं बताया गया. शोषण और दमन की यह कहानी केवल एक खादी केंद्र, मगहर की है, पर मगहर जैसे केंद्र बहुत-से हैं. हज़ारों श्रमिक बंधुआ स्थिति में, अमानवीय स्थिति में काम करने को बाध्य हैं. यह सब गांधी के नाम की आड़ में चल रहा है, जिनके लिए खादी एक नई, मानवीय अर्थव्यवस्था का प्रतीक थी. क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा सचमुच नपुंसक हो चुकी है, जो ऐसे गंभीर मामलों की तरफ़ भी ध्यान देने का साहस नहीं कर रही है? ज़रूरत इस बात की है कि राज्य विधान मंडल एक समिति नियुक्त कर मगहर सहित तमाम खादी केंद्रों की अमानवीय स्थितियों की जांच कराए और सरकार से कहे कि गांधी के नाम पर यह काला धंधा बंद किया जाए. ■

11 सितंबर, 1983

feedback@chauthiduniya.com

सबका साथ-सबका विकास

मोदी के पास वक्त बहुत कम है

मेघनाद देसाई

> वर्ष 2005 एवं 2010 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू की कनिष्ठ सहयोगी थी और वह उस दौरान बिहार में हुए विकास का श्रेय लेने में नाकाम रही. राज्य के विकास का सारा श्रेय नीतीश की झोली में चला गया. वहीं भाजपा के तेजतर्रार नेताओं में से एक सुशील मोदी को उनका जायज हक़ नहीं दिया गया. भाजपा को मजबूरन यह दलील देनी पड़ी कि वर्ष 2013 में एनडीए के टूटने के बाद बिहार में कोई विकास नहीं हुआ और लालू प्रसाद का मतलब है, जंगलराज. इन हमलों से बेपरवाह लालू ने बिहार की जातीय संरचना की अपनी जानकारी का लाभ उठाना शुरू किया. पिछले कुछ चुनावों से पिछड़े, मुस्लिम एवं दलित वोट जदयू और राजद के बीच विभाजित हो जाते थे.

किसी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव की सही भविष्यवाणी नहीं की. दूसरों की तरह मेरी भी पहली भविष्यवाणी ग़लत साबित हुई, लेकिन कम संभावना वाली मेरी दूसरी भविष्यवाणी सही साबित हुई, जिसमें मैंने नीतीश को भारी जीत दर्ज करते हुए दिखाया था. दरअसल, वास्तविक विजेता न तो नीतीश कुमार हैं और न लालू प्रसाद यादव, वास्तविक विजेता कांग्रेस है. कांग्रेस द्वारा 41 सीटों में से 27 पर जीत हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं है. ऐसा सोनिया गांधी के कारण संभव हो सका, जिन्होंने महा-गठबंधन में कनिष्ठ सहयोगी बनने की इच्छा दिखाई. उन्हें मालूम था कि 2014 की हार के बाद कांग्रेस को बदलना पड़ेगा. हालांकि, कांग्रेस एक बार फिर से एक विकल्प बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से 2019 के बारे में कोई भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी.

वर्ष 2005 एवं 2010 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू की कनिष्ठ सहयोगी थी और वह उस दौरान बिहार में हुए विकास का श्रेय लेने में नाकाम रही. राज्य के विकास का सारा श्रेय नीतीश की झोली में चला गया. वहीं भाजपा के तेजतर्रार नेताओं में से एक सुशील मोदी को उनका जायज हक़ नहीं दिया गया. भाजपा को मजबूरन यह दलील देनी पड़ी कि वर्ष 2013 में एनडीए के टूटने के बाद बिहार में कोई विकास नहीं हुआ और लालू प्रसाद का मतलब है, जंगलराज. इन हमलों से बेपरवाह लालू ने बिहार की जातीय संरचना की अपनी जानकारी का लाभ उठाना शुरू किया. पिछले कुछ चुनावों से पिछड़े, मुस्लिम एवं दलित वोट जदयू और राजद के बीच विभाजित हो जाते थे. लेकिन, इस बार ऐसा नहीं हुआ और वे महा-गठबंधन के साथ एकजुट रहे. भाजपा के पास सवर्ण जातियों के वोट थे, लेकिन वे काफी नहीं थे, क्योंकि दलितों एवं पिछड़ों के अधिक वोट उसे नहीं मिले. इसके बावजूद वह सबसे अधिक वोट हासिल करने में सफल रही. भाजपा को 24.5 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन सीटें केवल 20 प्रतिशत मिलीं. राजद को 18

प्रतिशत वोट मिले, लेकिन सीटें 32 प्रतिशत मिलीं.

राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाति का कार्ड खेला, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की जीत हुई. इससे ज़ाहिर होता है कि भारत में हर जगह राष्ट्रीय पार्टियों की पकड़ मज़बूत नहीं है. तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में हैं. परंपरागत रूप से भाजपा उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में मज़बूत है. ये वे राज्य हैं, जहां पहले देशी रियासतों की सामंतवादी सत्ता थी. आपातकाल के दमन के बाद सामंतों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा को अपना लिया. वर्ष 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर की वजह से भाजपा उत्तर प्रदेश और बिहार में जीती थी. लेकिन, अब यह साफ़ हो गया है कि लोकसभा के चुनाव दूसरे क्षेत्रीय चुनावों से अलग होते हैं. भाजपा की ग़लतियों के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है. उसकी ग़लतियां भी बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद यह साफ़ नहीं हो सका कि जातीय गणित में बदलाव लाया जा सकता है या नहीं. बहरहाल, भाजपा को बेहतर आंतरिक अनुशासन बनाए रखना चाहिए था. ब्रिटेन में सभी पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों के मन से नस्लवाद और लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. भाजपा अगर सत्ता में बने रहना चाहती है, तो उसे भी अपने सभी सदस्यों को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि उनके मन से मुसलमानों एवं दलितों के प्रति भेदभाव समाप्त हो जाए.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी 21वीं सदी में दाखिल होने की ज़रूरत है. उसे अब महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करके महिला प्रचारकों या नेताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए. संघ द्वारा भाजपा को बाहर से सलाह देने में कोई बुराई नहीं है. कम्युनिस्ट पार्टियां अक्सर सोवियत संघ और चीन के आदेशों का पालन करती थीं. फिर भी संघ को सावधानीपूर्वक और बिना शोरगुल किए अपनी राय रखनी चाहिए. उसे जितनी ज़रूरत अपनी ज़ुबान पर क़ाबू रखने की है, उतनी ज़रूरत अपने मुख-पत्र पर नियंत्रण रखने की भी है. सत्ता ज़िम्मेदारी का तकाज़ा करती है. नरेंद्र मोदी भाजपा के शीर्ष पर वोट हासिल करने के वादे और संभावनाओं के साथ पहुंचे थे. उन्होंने वर्ष 2014 में यह कारनामा कर दिखाया, लेकिन राज्यों के चुनाव स्थानीय नेताओं पर छोड़ देने चाहिए. मोदी को अपने कार्यकाल के बाक़ी दिनों में सबका साथ-सबका विकास का वादा निभाने के लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके लिए अब अधिक समय नहीं बचा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

[यदि सब अगों में सूजन हो, मूत्र कम मात्रा में होता हो, मूत्र में एल्ब्युमिन जाता हो, यकृत वृद्धि हो, अग्निमांद्य तथा नेत्रों के नीचे सूजन हो तो 15-20 दिन इच्छानुसार अनानास के रस का सेवन करने से लाभ होता है तथा 15-20 दिन में पूरा लाभ होता है. पथ्य में केवल दूध का सेवन करें.]

अनानास

अनानास ब्राजील का आदिवासी पौधा है. भारत में पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, पश्चिमी घाट , महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के समुद्रतटों पर तथा अण्डमान द्वीपसमूह में प्रचुर मात्रा में इसकी खेती की जाती है.

बाह्य स्वरूप

इसका 1.5 मी ऊंचा, बहुवर्षायु, छोटे, काण्ड तथा पत्रयुक्त क्षुप होता है, जो देखने में केवड़े या घृतकुमारी जैसा होता है. इसके पत्र 30-90 सेमी लंबे, 5-7 सेमी चौड़े, चक्राकार, क्रम में व्यवस्थित, ऊपरी सतह पर चमकीले तथा निचली सतह पर पाण्डुर वर्णी होते हैं.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

1. अनानास वातपित्त शामक, रुचिकारक, दीपन, अनुलोमन, रेचन, हृद्य, रक्त-पित्त, अश्मरी-भेदन, मूत्रल, बलकारक तथा ज्वरघ्न होता है.

2. कच्चे फल का स्वरस तीव्र गर्भाशय उत्तेजक, आर्तवजनन तथा अधिक मात्रा में गर्भपातक होता है.

3. अनानास पत्र-स्वरस तीव्र रेचक एवं कृमिघ्न होता है.

4. अनानास के पत्र विरेचक, कृमिरोधी, आर्तवजनन तथा कृमिनिस्सारक होते हैं.

5. इसके पक्व फल शीतादरोधी, मूत्रल, स्वेदजनन, मृदुविरेचक तथा शैत्यकारक होते हैं.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

वक्ष रोग :

1. कास एवं श्वास रोग-अनानास फल के 50-100 मिली रस में 1 ग्राम छोटी कटेरी मूल चूर्ण, 2 ग्राम आंवला चूर्ण और 500 मिग्रा जीरा चूर्ण तथा मधु मिलाकर सेवन करें.

2. पके फल के 50-100 मिली रस में पिप्पली मूल, सोंठ और बहेड़े का चूर्ण 2-2 ग्राम तथा भुना हुआ सुहागा व मधु मिलाकर सेवन करने से कास एवं श्वास रोग में लाभ होता है.

3. अनानास फल रस में मुलेठी बहेड़ा और मिश्री मिलाकर सेवन करने से श्वास-कास में लाभ होता है.

उदर रोग :

1. अजीर्ण-अनानास के पके फल के बारीक टुकड़े में सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर खाने से अजीर्ण दूर होता है.

2. 100 मिली पक्व फल रस में 1-2 नग दाख और 125 मिग्रा सेंधा नमक मिलाकर खाने से अजीर्ण दूर होता है.

3. भोजन के बाद यदि पेट फुल जाए, बैचेनी हो तो अनानास के 50-100 मिली रस के सेवन से लाभ होता है.

4. पके हुए अनानास के 10 मिली रस में भुनी हुई हींग 125 मिग्रा तथा सेंधा नमक 250 मिग्रा और अदरक का रस 250 मिली मिलाकर प्रात: सायं सेवन करने से उदर शूल और गुल्म रोग में भी लाभ होता है.

5. 100 मिली पक्व फल रस में 65 मिग्रा यवक्षार, 250-250 मिग्रा पीपल और हल्दी का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से प्लीहा, उदर रोग तथा गुल्म दिन में नष्ट होते हैं.

6. अनानास रस में, रस से आधी मात्रा में गुड़ मिलाकर सेवन करने से उदर एवं वस्तिप्रदेश में स्थित वात नष्ट होता है. उदर यदि बाल चला गया हो तो अनानास के खाने से वह गल जाता है.

7. जलोदर- अनानास के पत्रों के क्वाथ में बहेड़ा और छोटी हरड़ का चूर्ण मिलाकर देने से अतिसार और मूत्र साफ होकर जलोदर में लाभ होता है.

8. कृमि रोग- अपक्व फल स्वरस का सेवन से कृमि रोगों में लाभ होता है.

9. उदर विकार- फल स्वरस का सेवन से पाचन-तंत्र संबंधी विकारों में लाभ होता है.

10. पके फल के रस में छुहारा, खुरासानी अज़वायन और वियविडंग का चूर्ण समभाग मिलाकर, थोड़े से शहद के साथ 5-10 ग्राम की मात्रा में चटाने से बालकों के कृमि रोग नष्ट होते हैं.

11. अनानास के पत्तों के रस में थोड़ा शहद मिलाकर रोज 2 से 10 मिली तक सेवन करने उदरकृमियों का शमन होता है.

यकृतप्लीहा रोग:

1. कामला- अनानास के पके फलों के 10-50 मिली रस में 2 ग्राम हल्दी चूर्ण और 3 ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन करने से कामला रोग में लाभ मिलता है.

वृक्कवस्ति रोग:

1. मधुमेह- अनानास मधुमेह में बहुत लाभकारी है. अनानास के 100 मिली रस में, तिल, हरड, बहेड़ा, आंवला, गोखरू और जामुन के बीज 10-10 ग्राम मिला दें. सूखने पर चूर्ण बनाकर रखें. इस चूर्ण को प्रात: सायं 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से बहुमूत्ररोग तथा मधुमेह में अत्यन्त गुणकारी है. (पथ्य-दूध व चावल, परहेज-लाल मिर्च, खटाई और नमक)

2. अनानास और खजूर के टुकड़े बराबर-बराबर लेकर उसमें घी और शहद (विषम मात्रा में) मिलाकर कांच के बर्तन में भरकर रखें. इसे नित्य 6 या 12 ग्राम की मात्रा में खाने से बहुमूत्र रोग दूर होता है और शक्ति बढ़ती है.

प्रजनन संस्थान रोग:

1. मासिक-विकार- अनानास के कच्चे फलों के 10-50 मिली रस में, पीपल की छाल का चूर्ण और गुड़ 1-1 ग्राम मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है.

2. 40-60 मिली अनानास पत्र क्वाथ को पीने से भी मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है.

3. रतिक रोग- अनानास के अपक्व फलों को उबालकर सेवन करने से रतिज रोगों में लाभ होता है.

त्वचा रोग:

1. अभिघातजन्य शोथ- अनानास फल स्वरस का लेप करने से अभिघात एवं शल्यकर्म के पश्चात उत्पन्न शोथ में लाभ होता है.

2. कुष्ठ- ताजे फल स्वरस का लेप करने से श्लीपद तथा कुष्ठजन्य त्वक विकारों में लाभ होता है.

सर्वशरीर रोग:

1. सर्वांग शोथ- यदि सब अगों में सूजन हो, मूत्र कम मात्रा में होता हो, मूत्र में एल्ब्युमिन जाता हो, यकृत वृद्धि हो, अग्निमांद्य तथा नेत्रों के नीचे सूजन हो तो, 15-20 दिन इच्छानुसार अनानास रस का सेवन करने से लाभ होता है तथा 15-20 दिन में पूरा लाभ होता है. पथ्य में केवल दूध का सेवन करें.

2. एकांग शोथ- अनानास के पत्तों पर एरंड तेल चुपड़कर कुछ गर्म करें और सूजन पर बांध दें. विशेषत: पांव की सूजन तुरन्त दूर होती है.

3. ज्वर- इसके फलों का रस देने से अथवा 20 मिली रस में शहद मिलाकर पिलाने से पसीना आता है, मूत्र खुलकर आता है और ज्वर का वेग कम हो जाता है.

मुरब्बा और शर्बत:

1. अनानास के पके फलों के टुकड़े करके एक दिन चूने के पानी में रखकर, सुखाकर, शक्कर की चासनी में डालकर मुरब्बा बना लें. इस मुरब्बे का सेवन करने से यह पित्त का शमन और चित्त को प्रसन्न करता है.

2. अनानास का शर्बत (रस 1 भाग, चाशनी 2 भाग)
भी पित्त को शान्त करने वाला और हृदय को बल देने वाला होता है.

अहितकर: अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कंठ के लिए अहितकर होता है.

दुष्प्रभाव निवारण: नींबू का रस, शर्करा, अदरक का रस इसके उपद्रवों को शान्त करता है.

प्रयोज्यांग: फल, पत्र तथा काण्ड.

मात्रा: फल स्वरस 25-50 मिली या चिकित्सक के परामर्शानुसार

आचार्य बालकृष्ण

विद्यालय में वज़ीफा नहीं मिलता है तो क्या करें

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

अगर आपको आपके विद्यालय में वजीफा नहीं मिलता है, आप अपने वजीफे से संबंधित सूचना चाहते हैं, वजीफा में हेरफेर या भ्रष्टाचार का पता लगाना चाहते हैं, अगर आपको किसी सूचना की दरकार हो, तो आप आरटीआई आवेदन के माध्यम से अपने वजीफे से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस अंक में हम एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के जरिये संपर्क कर सकते हैं.

विद्यालय में वजीफा कैसे प्राप्त करें

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

कृपया.....विद्यालय मे वजीफा के वितरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:

1. उपरोक्त विद्यालय के कक्षा ..... में मेरा पुत्र/पुत्री ..... पढ़ता/पढ़ती है. आपके रिकॉर्ड के मुताबिक क्या वह इस वर्ष वजीफा पाने का हकदार है? यदि हां तो उसे कितनी राशि मिलनी चाहिए?

2. क्या आपके विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उसे इस वर्ष का वजीफा दिया जा चुका है? यदि हां, तो सम्बंधित दस्तावेजों/रजिस्टरों के उस भाग की प्रमाणित प्रति दें, जहां उसे वजीफा दिए जाने को विवरण दर्ज है.

3. यदि उसे वजीफा नहीं दिया गया है तो इसका क्या कारण है? सम्बंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति दें.

4. उपरोक्त विद्यालय में कुल कितने छात्र/छात्राओं को वजीफा प्रदान किया जाता है? प्रत्येक छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम एवं कक्षा का विवरण दें.

5. वर्ष.....में कुल कितने छात्र/छात्राओं को वजीफा दिया गया? प्राप्ति रजिस्टर, जिस पर छात्र-छात्राओं का या उनके अभिभावकों का हस्ताक्षर हो, उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.

6. छात्र/छात्राओं के वजीफे का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? वजीफा प्रदान करने के लिए क्या नियम एवं कानून है? इस सम्बंध में समस्त शासनादेशों/निर्देशों एवं कानूनों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.

7. सरकार ने विभिन्न कक्षाओं के छात्रों/छात्राओं को वजीफा देने के लिए कितनी राशि निर्धारित की है?

8. अगर किसी छात्र के वजीफे का भुगतान अब तक नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है? ऐसे सभी छात्रों कि सूची दें, जिन्हें अब तक वजीफा नहीं दिया गया है. इस सूची में निम्नलिखित विवरण अवश्य शामिल हों:

क. छात्रा का नाम
ख. पिता का नाम

ग. वजीफा नहीं दिये जाने का कारण

10. वजीफे का भुगतान समय से न किये जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का नाम एवं पद बताएं? अपना काम विभाग के नियम कानूनों के अनुसार न करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा /रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है-

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल: rti@chauthiduniya.com

आईएस को फंडिंग करने की लिस्ट में कुल 40 देशों का नाम है. यही नहीं, जिन देशों से पैसा पहुंच रहा है, उस पर पुतिन ने खुफिया जानकारियां भी साझा कीं. दूसरी तरफ पेरिस हमले के बाद अमेरिका सवालों के घेरे में है. उस पर आरोप लग रहे हैं कि वह आईएसआईएस से निपटने के लिए असरदार कदम नहीं उठा रहा. कुछ आलोचकों का मानना है कि अमेरिका सीरिया में बशर सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों को लगातार मदद करता रहा है. इसी वजह से वह आईएस के खिलाफ जमीनी कार्रवाई न कर सेलेक्टिव अप्रोच अपना रहा है.

पेरिस हमला

आईएसआईएस के अंत का आरंभ

पिछले 1400 वर्षों के इतिहास में ऐसी कोई सदी नहीं गुजरी है, जब दुनिया के किसी न किसी हिस्से में इस्लाम के नाम पर गैर मुसलमानों और मुसलमानों का खून न बहाया गया हो. वर्षों से भारत आतंकवाद पर अपनी पीड़ा को गला फाड़-फाड़ कर बताना चाहता है, लेकिन पश्चिमी देशों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी. हिंसा का यह लावा हाल में भले ही यूरोप और अमेरिका पहुंचा है, लेकिन एशियाई देशों के सीने में बहुत पहले से ही धधक रहा है. पश्चिमी देश हथियारों के दम पर अगर आईएसआईएस को हरा भी दें तो यह समझ से परे है कि उन्हीं देशों द्वारा पाला-पोसा गया आईएसआईएस और उसके विचार को कुछ और लोग कहीं और आगे नहीं बढ़ायेंगे. और अगर ऐसा होगा, तो क्या वह आईएसआईएस के अंत का आरंभ होगा या आईएसआईएस के विचार को कुछ लोग एक नये कलेवर में प्रस्तुत करेंगे, यह देखने वाली बात होगी.

राजीव रंजन

पिछले दिनों पेरिस में हुए चरमपंथी हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की स्थिति नाज़ुक बताई जा रही है. आज जब फ्रांस में आईएसआईएस का हमला हुआ है तो सारी पश्चिमी ताकतें सीरिया पर दिन-रात बमबारी कर सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक सीरिया जैसे देश को खंडहरों में तब्दील कर चुकी हैं. यहां तक कि ये ताकतें हमलों में न्यूक्लियर सपोर्ट से भी नहीं हिचकिचा रही हैं. इन ताकतों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनके हमले में दोषी कम और निर्दोष नागरिक ज्यादा मारे जा रहे हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी हैं. पेरिस पर आईएसआईएस ने हमला उस समय किया था, जब स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच दोस्ताना मैच खेला जा रहा था. इस मैच को देखने के लिए राष्ट्रपति ओलांदे खुद वहां मौजूद थे. आईएस द्वारा फ्रांस पर हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांस्वा ओलांद ने पार्लियामेंट में दी स्पीच में कहा कि फ्रांस आईएस के खिलाफ जंग शुरू कर चुका है. पेरिस हमलों के प्रतिक्रिया स्वरूप फ्रांस का आईएस आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमला जारी है. फ्रांस की ओर से ये हमले आईएसआईएस का गढ़ सीरिया के रक्का शहर पर किए जा रहे हैं. फ्रांस ने यह साफ कर दिया है कि आईएस आतंकियों पर जारी उसकी कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा और ये भविष्य में भी जारी रहेगी. पेरिस पर हमले के बाद अमेरिका ने भी सीरिया पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने स्पष्ट किया है कि उनका देश सीरिया में जमीनी फौज का प्रयोग नहीं करेगा. दूसरी ओर अमेरिका के 44 प्रतिशत लोगों का मानना है कि आईएस से बदला लेने के लिए उसके घर में घुसकर मारा जाना चाहिए. रूस ने तो पिछले दिनों एक ही दिन में क्रूज मिसाइल से हमला कर 600 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया. करीब महीना भर पहले 224 लोगों सहित एक रूसी विमान को आईएसआईएस द्वारा मार गिराने के कारण रूस आईएसआईएस पर पहले से ही बौखलाया हुआ है, इसलिए फ्रांस पर हमले के बाद उसको आईएस पर हमला करने के लिए और बल मिल गया. लेकिन इन सब से हटकर एक सवाल यह है कि आखिर आईएसआईएस इतना शक्तिशाली कैसे हुआ कि लगभग सारे नाटो देशों को मिलकर उससे लोहा लेना पड़ रहा है. क्या आईएसआईएस को पीछे से किसी शक्तिशाली देश का सपोर्ट मिल रहा है? कम से कम जी-20 सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा, उससे तो यही पता चलता है. पुतिन ने कहा कि आईएस को कुछ देशों से पैसा पहुंच रहा है, जिसमें जी-20 से जुड़े देश भी शामिल हैं. आईएस को फंडिंग करने की इस लिस्ट में कुल 40 देशों का नाम है. यही नहीं, जिन देशों से पैसा पहुंच रहा है, उस पर पुतिन ने खुफिया जानकारियां भी साझा कीं. दूसरी तरफ पेरिस हमले के बाद अमेरिका सवालों के घेरे में है. उस पर आरोप लग रहे हैं कि वह आईएसआईएस से निपटने के लिए असरदार कदम नहीं उठा रहा. कुछ आलोचकों का मानना है कि अमेरिका सीरिया में बशर सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों को लगातार मदद करता रहा है. इसी वजह से वह आईएस के खिलाफ जमीनी कार्रवाई न कर सेलेक्टिव अप्रोच अपना रहा है. आलोचकों का मानना है कि अमेरिका के लचर रवैए की वजह से ही सिविल वॉर झेल रहे सीरिया में आईएसआईएस को सिर उठाने का मौका मिला.

सवाल यह भी है कि खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस को हथियार कहां से मिलते हैं? वैसे तो पहले से ही अमेरिका व यूरोपीय देशों पर लोगों को शक था. हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो गया है कि आईएसआईएस जिन हथियारों का प्रयोग करता है, उनका निर्माण 21 हथियार निर्माता देशों में होता है, जिनमें दुनिया के प्रमुख हथियार निर्माता सुपरपावर देश चीन, अमेरिका और रूस के नाम शामिल हैं. हाल ही में पेरिस में हुए आईएसआईएस के हमले और उसमें सैंकड़ों लोगों के मारे जाने के बाद कई सुपरपावर देशों ने ऐसे खूंखार आंतकी संगठनों से एक सुर में सख्ती से निपटने की बात कही थी, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सबकी पोल खुल गयी है और आंतक से निपटने की उनकी यह बातें एक झूठा आश्वासन ही दिखाई देती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, हथियार खरीदने के लिए आईएस जैसे आतंकी संगठनों के पास पैसा पेट्रोलियम व तेल की बिक्री से आता है. इसके अतिरिक्त बेशकीमती और ऐतिहासिक मूर्तियों को तोड़कर बेचने, निवासियों द्वारा मकानों को खाली कर भाग जाने और उन मकानों को किराये पर देने या नीलामी करने, दूसरे देशों के लड़ाकों द्वारा पैसा लाने, लड़कियों को बेचने, जिस्मफरोशी, अपहरण से उगाही और जनता पर विभिन्न तरह के कर लगाकर आईएसआईएस पैसा बनाता है. रिपोर्ट जारी करने वाली एजेंसी ने बताया कि ईराक और सीरिया से बरामद किए गए हथियारों से यह भी पता चलता है कि इनमें से अधिकतर हथियारों का निर्माण अमेरिका के मिसोरी प्रांत में स्थित हथियारों का निर्माण करने वाले एक प्लांट में हुआ है. आईएस जो कारतूस इस्तेमाल करता है, उनमें से ज्यादातर का निर्माण अमेरिका व यूरोपीय देशों में ही किया गया था और कुछ अन्य कारतूस रूस और चीन में भी बने पाए गए. इशारों में ही सही, लेकिन कई देश इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि आईएस को हथियार अमेरिका व यूरोपीय देश ही सप्लाई करते हैं. सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर उन देशों की क्या मंशा है, जो एक तरफ आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं तो एक तरफ आतंकी संगठनों को हथियार भी उपलब्ध करवाते हैं. पश्चिमी देशों की भले ही यह सोच हो कि वह जब चाहेंगे आईएस जैसे आतंकी संगठनों को खड़ा कर सकते हैं और जब चाहेंगे उसे उखाड़ फेकेंगे, लेकिन सत्य यह है कि इस तरह की सोच रखने वाले देश सिर्फ और सिर्फ मानवता के हत्यारे हैं, जिन्हें सिर्फ अपना घाव तो दिखता है, लेकिन जो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाना तो दूर, नमक छिड़कने से भी बाज नहीं आते.■

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

खतरनाक था हिल साइड स्ट्रेंजलर

केनेथ बीआनची एक ऐसा शख्स, जो हिल साइड स्ट्रेंजलर के नाम से कुख्यात था. केनेथ बीआनची एक ऐसा सीरियल किलर, जिसने अपने चचेरे भाई एंजेलो बूओनो के साथ मिलकर कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध को अंजाम दिया और कई लोगों को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया. सन् 1977 से लेकर सन् 1978 के दौर में केनेथ बीआनची ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर लॉस एंजिलिस में बलात्कार और हत्याओं जैसे अपराधों का तांडव मचाया.

सन् 22 मई, 1951 में न्यूयॉर्क के रोचेस्टर शहर में सीरियल किलर केनेथ बीआनची का जन्म हुआ. कहा जाता है कि केनथ की मां एक शराबी वेश्या थी और उसने केनथ को गोद लिया था और इसी वजह से बचपन से ही केनथ के मन में महिलाओं के प्रति नफरत का भाव उभरने लगा. केनेथ हमेशा से पुलिस आयोग में जाना चाहता था, लेकिन पुलिस की नौकरी नहीं मिलने पर उसने सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करना शुरू कर दिया. सन् 1975 में केनथ ने रोचेस्टर को छोड़ लॉस एंजिलिस चला गया और वहां अपने चचेरे भाई एंजेलो बूओनो के साथ रहने लगा. वक्त बीतता गया और बाद में केनेथ अपनी प्रेमिका केली बॉयड और अपने बच्चे के साथ पारिवारिक जीवन जीने लगा. केनेथ ने फर्जी डिग्री के साथ एक मनोविज्ञान अभ्यास की स्थापना की और अपनी प्रेमिका केली से झूठ बोला कि वह कैंसर जैसी लाइलाज बिमारी से मरने वाला है. कोई नहीं जानता था कि केनेथ के इस झूठ के पीछे क्या राज़ था. वक्त के साथ-साथ केनेथ के अंदर छिपी महिलाओं के प्रति नफरत एक बड़ी और बुरी मानसिकत का रूप लेने लगी. इसी भयानक मानसिकता के चलते केनथ ने अपने चचेरे भाई के संग मिलकर लॉस एंजिलिस में अपहरण, बलात्कार और 15 लोगों की हत्याओं जैसे अपराधों को अंजाम देने लगा. केनेथ पुलिस अधिकारी का पहनावा पहन कर वेश्याओं को अपना निशाना बनाता था और बाद में मध्यम वर्ग के घरों की लड़कियों और महिलाओं को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया. गलत काम करने के बाद उसके पीछे कोई सबूत न छूट जाये, इसी मंशा से केनथ शवों को ग्लेनडेल हाइलैंड पार्क क्षेत्र की पहाड़ी पर फेंक देता और धीरे-धीरे पूरे लॉस एंजिलिस में हिल साइड स्ट्रेंजलर के नाम से कुख्यात हो गया. चार महीनों के इस आतंक के दौरान केनेथ अपनी बुरी मानसिकता के चलते अपने शिकारों को घरेलू रसायन के इंजेक्शन लगा कर उन्हें दर्दनाक मौत देने लगा. अमेरिका की पुलिस ने बड़ी मशक्कत से केनेथ के इस आतंक का पर्दाफाश किया और वॉशिंगटन में केनेथ को उसकी प्रेमिका के घर से गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान केनथ का चचेरा भाई बूओनो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ गया. अमेरिका के इतिहास में आरोपी केनेथ और उसके चचेरे भाई बूओनो पर काफी लंबी कार्यवाही चली और अंत में न्याय प्रणाली ने केनेथ और बूओनो को उम्रकैद की सजा सुना दी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु समझौते पर मुहर

काफी लंबे समय से चल रहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच असैन्य परमाणु समझौता अब लागू हो चुका है. इस समझोते पर खुशी जाहिर करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों देशो के रिश्तों में इसे एक मील का पत्थर करार दिया है. तुर्की में हुये जी-20 शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टर्नबुल मैलकम से अपनी मुलाकात में मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौता एक मील का पत्थर तथा भरोसे और विश्वास का परिचायक है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से ट्वीट में दोनों नेताओं के मुलाकात की तस्वीर जारी करते हुये कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु समझौते के लागू होने की प्रक्रिया पूरी होने की घोषणा की है. इसके साथ ही यह समझौता औपचारिक रूप से लागू हो गया है. परमाणु समझौते पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुये कहा कि इस समझौते के प्रशासनिक व्यवस्था समेत सभी प्रक्रियाएं पूरी होना दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों को दिखलाता है.■

सीरिया-इराक में हो रही है आईएस की ट्रेनिंग

हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले करने वाले इस्लामिक स्टेट के आठ आतंकवादी उन हजारों युवाओं में से हैं, जिन्हें सीरिया और इराक में ट्रेनिंग मिली है. गिरफ्तार आतंकवादियों और इस्लामिक स्टेट के साथ सहानुभूति रखने वाले कुछ लोगों के भारत वापस आने पर हुई पूछताछ में पता चला है कि आतंकवादियों को अब आधुनिक हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है और रिक्रूट करने के साथ इन्हें बरगलाने में इंटरनेट भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. पूछताछ में गिरफ्तार आतंकवादी अरीब मजीद ने बताया कि हमला करने से पहले उन्हें तीन अलग-अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल से गुजरना पड़ता है. ट्रेनिंग के पहले राउंड में हथियारों से परिचय कराया जाता है और प्रत्येक नए रिक्रूट को शुरूआत से ही एके-47 दे दी जाती है. इसके बाद शरिया कानून और जिहादी प्रॉपगेंडा पर लेक्चर दिया जाता है. ट्रेनिंग आमतौर पर दो सप्ताह की होती है और इस दौरान उन्हें एक मस्जिद में रखा जाता है. पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि लेक्चर के बाद कई बार लड़ाकों की परीक्षा भी ली जाती है और ट्रेनिंग सेंटर्स में उन्हें बम बनाना भी सिखाया जाता है. तीसरे ट्रेनिंग कैम्प में फिजिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है. इन सब के साथ-साथ ट्रेनिंग में आईएस के जेहादियों को फर्टिलाइजर्स और कोटेंक्स से बारूदी सुरंगें बनाने के बारे में जानकारी दी जाती है. कई बार बुलेट की मदद से टारगेट की दूरी मापना सिखाने के लिये लाइव डिमॉस्ट्रेशन भी होते हैं.■

जनमत संग्रह ही कश्मीर का हल : नवाज शरीफ

पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीरी अलगाववादी नेता और दुख्तरान-ए-मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी को कहा है कि कश्मीर मसले का सिर्फ एकमात्र हल जनमत संग्रह है. रेडियो पाकिस्तान की रिर्पोट के अनुसार, नवाज शरीफ ने आसिया को उनके खत का जवाब देते हुये कश्मीर का जिक्र किया है. संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने पर आसिया ने नवाज शरीफ की तारीफ करते हुए उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी. नवाज ने इस चिट्ठी के जबाव में लिखा है, मैं आपकी भावनाओं और विचारों की कद्र करता हूं. अल्लाह पाकिस्तान और मुझे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की ताकत बख्शे. कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के स्टैंड पर आपका भरोसा मेरे लिए तसल्ली की बात है. कश्मीर की मुस्लिम आबादी का जिक्र करते हुये नवाज शरीफ ने कहा है कि बंटवारे की बुनियाद यही थी कि मुस्लिम बहुल आबादी वाले राज्य कश्मीर को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिये. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सारी दुनिया के कमीरियों के इस हक की बात मानी है. भारत ने विश्व के सामने खुद यह दावा किया था कि कश्मीर को अपने राजनीतिक मुस्तबिल का फैसला करने का रायशुमारी के जरिये अख्तियार दिया जाएगा. इस वादे से पीछे हटने का मतलब दुनिया से किए वादे से मुकरना होगा. ■

जीवन में आगे चलकर, अपनी योग्यता, मेहनत और महत्वकांक्षा के जरिए नेपोलियन फ्रांस की सेना में एक सामान्य सैनिक से एक अफसर, फिर सेनापति और अंत में फ्रांस का सम्राट बन गया. सम्राट बनने के बाद जब वह अपने पुश्तैनी गांव पहुंचा तो उसने लोगों से उस औरत का पता पूछा और उसके घर पर उससे मिलने गया. नेपोलियन ने उस औरत से पूछा मैम, क्या आप मुझे पहचानती हैं?

साई वंदना

कर्तापन का त्याग

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

अपनी आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में मनुष्य किस प्रकार शीघ्रता–पूर्वक अग्रसर हो सकता है ?

अध्यात्म के मार्ग में कोई भी व्यक्ति मात्र सुनकर या पढ़कर आगे नहीं बढ़ सकता. कोई भी ज्ञान यदि वह व्यवहार में नहीं आता, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है. ज्ञान को व्यवहार में लाना बहुत कठिन है. इसके लिए आस्था एवं शक्ति का होना अनिवार्य है. सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण एवं कृपा–याचना से इस मार्ग में भक्त का चलना संभव होता जाता है. इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि मैं योगी बनूंगा, सिद्ध बनूंगा, भक्त बनूंगा, कुंडलिनी जगाऊंगा, मुक्ति प्राप्त करूंगा. बिना इन शब्दों के अर्थ जाने हुए इनमें फंसना मूर्खता होगी. आवश्यक यह है कि हम केवल ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास रखें और बाबा से निरंतर प्रार्थना करें कि वे अपना स्वरूप हमें प्रकट करें. साथ ही इस तत्व को भी हम समझें कि वास्तव में हम कर्ता नहीं है. प्रत्येक कार्य को करने में अपने कर्तापन का त्याग करना आवश्यक है. यह कर्तापन हमारे अहंभाव के कारण आता है और धीरे–धीरे जाता है. इसमें समय लगता है.

पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा आचरण का महत्व

क्या धर्मग्रंथ पढ़ने से वास्तविक ज्ञान मिलता है ?

क्या हम जो धर्मग्रंथ आदि पढ़ते हैं, उसमें लिखी बातों पर अमल कर पाते हैं? अगर नहीं, तो वह मात्र बुद्धि–विलास है और जहां विलास है वहां ज्ञान कभी नहीं हो सकता है. अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है.

आध्यात्मिक क्षमता सद्गुरुओं द्वारा प्रदत्त

सद्गुरु मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का विकास करने में पूर्णतया समर्थ हैं, फिर उनके संपर्क में आने पर भी मनुष्य की चेतना के विकास की गति इतनी धीमी क्यों होती है?

सद्गुरु प्रकाशमान सूर्य की भांति हैं. जैसे सूर्य के प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अवरोध न हो और वह सीधा पड़े तो सब जल जाएगा. सद्गुरु मनुष्य की चेतना पर पड़े हुए असंख्य परदों को एक साथ नहीं हटाते, क्योंकि इस स्थिति को झेल पाना आसान नहीं है. श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर जब अपना विराट रूप दिखाया था, तो उस दिव्य दृष्टि के होने के बावजूद भी अर्जुन श्रीकृष्ण के विराट रूप को देखकर घबरा गए थे. इसीलिए सद्गुरु मनुष्य की चेतना पर पड़े हुए अनगिनत परदों को क्रमश: हटाते हुए उसे धीरे–धीरे आत्मानुभूति के योग्य बनाते हैं. इसमें समय लगता है. आध्यात्मिक खजाना भरपूर है, लेकिन उसे ग्रहण करने की पात्रता या क्षमता बिरलों में ही होती है. वास्तविकता तो यह है कि यह क्षमता भी सद्गुरु ही प्रदान करते हैं, लेकिन एकाएक नहीं. इसमें जन्म–जन्मान्तर भी लग जाते हैं.

लोग असली मार्ग की दिशा कब ढूंढ़ पात हैं?

कर्म–फल के अनुसार जब उचित समय आता है. जब मुसीबत आने पर वह अपने जीवन के बारे में विचार करना आरंभ करता है. करोड़ों प्रकार के विभिन्न प्राणी–जिनमें मानव सबसे उन्नत है, जीवन के अलग–अलग गलियारों में चलते रहते हैं– राजपथ पर पहुंचने के लिए. इसका अर्थ यह है कि विभिन्न लोग जीवन की संकीर्ण गलियों के भीतर दु:ख और कष्ट के बोझ को उठाते हुए उस आध्यात्मिक राजपथ को ढूंढते रहते हैं,

सद्गुरु प्रकाशमान सूर्य की भांति हैं. जैसे सूर्य के प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अवरोध न हो और वह सीधा पड़े तो सब जल जाएगा. सद्गुरु मनुष्य की चेतना पर पड़े हुए असंख्य परदों को एक साथ नहीं हटाते, क्योंकि इस स्थिति को झेल पाना आसान नहीं है. श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर जब अपना विराट रूप दिखाया था, तो उस दिव्य दृष्टि के होने के बावजूद भी अर्जुन श्रीकृष्ण के विराट रूप को देखकर घबरा गए थे.

जो कि प्रशस्त, समतल और दिव्य है. कुछ लोग कम समय में पहुंचते हैं. कुछ लोग गलियों की कठिनाईयों में उलझे रह जाते हैं. कुछ गलियों के ऊबड़–खाबड़ रास्ते में गिरते–पड़ते चलते हैं. कुछ आगे बढ़ने के लिए धक्का–मुक्की करते हैं. कुछ चल नहीं पाते और थक कर बीच में बैठ जाते हैं, कुछ किसी सराय में रुक जाते हैं. कुछ मायावी बाजार से आकर्षित होकर रह जाते हैं. समय के क्रम में जो जन्म–जन्मांतर से उस राजपथ के द्वार पर पहुंचते हैं, तो बिना द्वारपाल की अनुमति के अंदर घुस नहीं पाते. वे द्वारपाल ही सद्गुरु हैं. एक सद्गुरु हैं, जिसका दरवाज़ा खोलकर आध्यात्मिक राजपथ में प्रवेश देते हैं, वह फिर वापस नहीं लौटता. उसे फिर राजपथ पर चलना ही पड़ता है. इस राजपथ में भी बहुत समय लगता है, क्योंकि राजपथ के अन्त में मालिक या ईश्वर बैठा है. पहले वह उनको अस्पष्ट रूप में देख पाता है, फिर धीरे–धीरे उनका रूप स्पष्ट होने लगता है. आध्यात्मिक रास्ता और उसमें प्रगति करना सद्गुरु के बिना असंभव है. ■

feedback@chauthiduniya.com

धर्म भक्तों के दुख दूर करते हैं सालासर बालाजी

तरुण फोर

राजस्थान के चुरू जिले में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है. इस मंदिर को सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है.

बालाजी के एक भक्त थे मोहनदास. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने उन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया था. अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के आसोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए थे. इस मंदिर के संस्थापक श्री मोहनदासजी बचपन से श्री हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे. माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा एक किसान को जमीन जोतते समय मिली थी, जिसे सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है. बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी चमत्कारी है. उतने बालाजी भी चमत्कारी और भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं.

पूरे भारत में एक मात्र मंदिर सालासर में दाढ़ी मूछों वाले हनुमान यानी बालाजी स्थित हैं. इसके पीछे मान्यता यह है कि मोहनराम को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे. मोहनराम ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था. इसलिए हनुमान जी यहां दाढ़ी मूछों में स्थित हैं.

बालाजी के बारे में एक बड़ी रोचक बात यह है

कि इनके मंदिर का निर्माण करने वाले मुसलमान कारीगर थे. इनमें नूर मोहम्मद और दाऊ का नाम शामिल है.

बालाजी की धुणी को भी चमत्कारी माना जाता है. कहते हैं बाबा मोहनदास जी ने 300 साल पहले इस धुनी को जलाई थी, जो आज भी अखंडित प्रज्जवलित है.

सालालर बालाजी का प्राकट्य दिवस श्रावण शुक्ल नवमी को यहां बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. साथ ही पितृपक्ष में मोहनदासजी का श्राद्ध दिवस त्रयोदशी को मनाया जाता है. इन दोनों ही उत्सवों में भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं. हनुमान जयंती और शरद पूर्णिमा पर भी यहां भव्य पैमाने पर उत्सवों का आयोजन किया जाता है. ■

सम्राट ने चुकाया वृद्धा का कर्ज़

फ्रांस का महान सम्राट नेपोलियन जिसे हमेशा अपनी बहादुरी, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय के लिए याद किया जाता है. सामान्य लोगों, अपने सैनिकों के साथ भी बड़ी सहजता और सरलता से पेश आता था. नेपोलियन में कई उच्च मानवीय गुण थे, जिससे वह जनता में लोकप्रिय नायक बन गया था.

यह कहानी उसकी मानवीयता, दया और अपने पर किए एहसान को याद रखना और उसकी कीमत चुकाने के बारे में है.

नेपोलियन ने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी, कई बार उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, उसके स्कूल के बाहर ही एक औरत फल और खाने की चीजें बेचा करती थी.

कभी–कभी ऐसा भी होता कि नेपोलियन की जेब में एक भी पैसा नहीं होता था, ऐसे में वह उस औरत से खाने की चीजें मजबूरी में उधार ले लिया करता था और पैसे आने पर उसे ईमानदारी से लौटा देता था. वह औरत भी नेपोलियन पर विश्वास कर उसे खुशी से उधार दे देती थी.

जीवन में आगे चलकर, अपनी योग्यता, मेहनत और महत्वकांक्षा के जरिए नेपोलियन फ्रांस की सेना में एक सामान्य सैनिक से एक अफसर, फिर सेनापति और अंत में फ्रांस का सम्राट बन गया. सम्राट बनने के बाद जब वह अपने पुश्तैनी गांव पहुंचा तो उसने लोगों से उस औरत का पता पूछा और उसके घर पर उससे मिलने गया. नेपोलियन ने उस औरत से पूछा मैम, क्या आप मुझे पहचानती हैं? उस समय नेपोलियन ने फौजी जनरल की वर्दी पहन रखी थी, जिसे देखकर वह औरत थोड़ी सहम गई फिर उसने विस्मय से कहा नहीं, माफ़ कीजिएगा मैं आपको नहीं जानती? नेपोलियन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि आप मुझे भूल गईं हों, पर मैं वो छोटा लड़का आपको अभी तक नहीं भूला जिसे आप खुशी खुशी उधार दे दिया करतीं थी.

यह कहकर नेपोलियन ने उस बूढ़ी औरत को सिक्कों से भरी एक थैली उपहार में दी. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

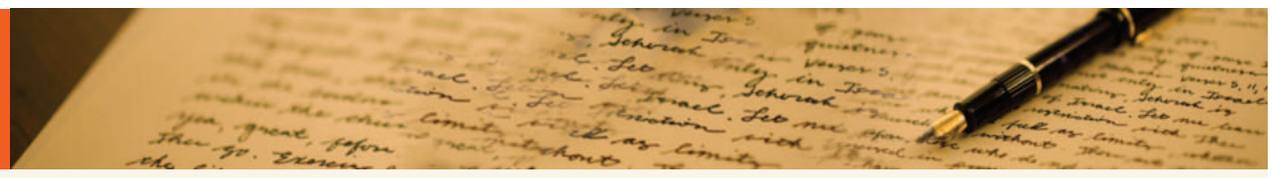

चुनाव परिणाम से संज्ञान लेंगे नेता

आलेख–यह चुनाव परिणाम एक बेहतर राजनीतिक वातावरण बनाएगा(16 नवंबर–22 नवंबर, 2015)पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. कमल मोरारका ने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार चुनाव परिणाम हमें कुछ सीख देता है. पहला, बिहार का मतदाता अलग तरह का मतदाता है. यह सही भी है, क्योंकि सारे सर्वे और एक्जिट पोल फेल हो गए. बिहार का मतदाता चुपचाप अपने मत का प्रयोग किया और नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री चुना. बिहार की जनता ने भाजपा की विकास की बातें, बड़े–बड़े आर्थिक पैकेज और योजनाओं की घोषणा को नकार दिया और उसने नीतीश द्वारा किए कार्यों पर भरोसा जताया. अब भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से कुछ सीख लेगी. इस चुनाव परिणाम के बाद आशा है कि नेता भी एक दूसरे के खिलाफ गंदे भाषाओं का प्रयोग करना बंद करेंगे.

–रविशंकर ओझा, बक्सर, बिहार.

जरूरत पड़ने पर ही हॉर्न बजाएं

जब तोप मुकाबिल हो–राजेश और उनके जैसे लोगों को सलाम(16 नवंबर–22 नवंबर, 2015) पढ़ा. काफी प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने एक आम आदमी की आवाज अपने संपादकीय के माध्यम से उठाई है और एक ऑटो चालक के दर्द को भी बयान किया है. लोग ऑटो में बैठते हैं और अपनी यात्रा समाप्त होने पर उतर जाते हैं. कौन कहां किसी के दर्द को समझता है. राजेश ने ध्वनि प्रदूषण की समस्या को लेकर अपनी चंता जाहिर की है. यह बिल्कुल सही है कि लोगों को मालूम है कि रेड लाइट है और जब ग्रीन लाइट होगी तभी कोई आगे बढ़ेगा, लेकिन लोग हॉर्न बजाते रहते हैं. जब एक ऑटो चलाने वाला ध्वनि प्रदूषण के बारे में इतना सोच सकता है, तो हम क्यों नहीं. सभी बाइक चलाने हों, कार चलाने हों या दूसरे ऑटो चालक सभी को जब जरूरत हो तभी हॉर्न बजाना चाहिए. हम सभी को राजेश से सबक लेने की जरूरत है.

–रघुवीर श्रीवास्तव, शाहदरा, दिल्ली.

सरकार की पोल खोलती रिपोर्ट

मैं चौथी दुनिया साप्ताहिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं. मैंने चौथी दुनिया अखबार के (02 नवंबर–08 नवंबर, 2015) अंक में प्रकाशित आलेख स्वच्छ भारत अभियान: सरकारी स्कूलों में सौ फ़ीसद शौचालय निर्माण, इस सरकारी दावे की हक़ीकत क्या है, पढ़ा. काफी अच्छा लगा. इस आलेख ने मोदी सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दावों की पोल खोल कर रख दिया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दावा है कि उसने देश भर के सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण का अपना लक्ष्य दो अक्टूबर, 2015 तक हासिल कर लिया है. मंत्रालय के मुताबिक, सौ फ़ीसद लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. इस दावे की जांच की, तो इसकी कलई खुलती नज़र आई. कई स्कूलों में तो शौचालय नहीं हैं, जहां बने हैं उनमें से अधिकांश में दरवाजे नहीं हैं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है और जहां दरवाजे हैं, उनमें ताला लटक रहा है. चौथी दुनिया अखबार के माध्यम से पता चला की देश में शौचालय का क्या हाल है. बातें तो बड़ी–बड़ी होती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर न ही कोई कार्य होता है और न कोई विकास. चौथी दुनिया अखबार द्वारा दिए आंकड़ो से यह साफ हो जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दावा झूठा है.

–अवनीश उपाध्याय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

आरक्षण का आधार आर्थिक हो

गुजरात में पटेल और उत्तर प्रदेश में जाटों और गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन को देखते हुए सरकार और संसद को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जातिगत आधारित आरक्षण नीति पर फिर से विचार करना चाहिए. उत्तर प्रदेश में लगभग 76 ओबीसी जातियां और 66 अनुसूचित जातियां हैं, लेकिन जिन जातियों की आबादी कम है, उन्हें तो आरक्षण का लाभ वैसे भी नहीं मिल रहा है. अत: आरक्षण नीति के बावजूद बहुत सी जातियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर पर पिछड़ापन बरकरार है. अब ऐसी व्यवस्था की जाए कि आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिले जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हों, तो अति पिछड़ी और महादलित जातियों को भी समाज की मुख्यधारा में लाया जा सकता है, जो आजादी के 68 वर्ष बाद भी समाज के निचले पायदान पर हैं.

–सत्य प्रकाश शिक्षक, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

राजनीतिक समीकरण

नीतीश के विकास को बिहार की जनता ने स्वीकार किया और पांचवी बार मुख्यमंत्री बने. नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में गैर भाजपा दलों के तमाम नेता शामिल हुए. इस शपथ ग्रहण समारोह से एक नया राजनीतिक समीकरण बनता दिख रहा है. नीतीश के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक के राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता शामिल हुए. इसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में मोदी सरकार के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष और नया राजनीतिक समीकरण नजर आएगा.

–किरन कुमारी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश.

असहिष्णुता की आड़ में सियासत

अनंत विजय

बिहार चुनाव के खत्म होते ही देश में बढ़ रहे असहिष्णुता को लेकर हर रोज हो रहा हंगामा लगभग खत्म सा हो गया है. ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार चुनाव में एनडीए और बीजेपी की हार के बाद देश के असहिष्णु होने को लेकर छाती कूटनेवालों के कलेजे को ठंडक पड़ गई हो. संभव है कि असहिष्णुता का मुद्दा केंद्र की मोदी सरकार को बिहार चुनाव के दौरान बैकफुट पर लाने के लिए उठाया गया हो. इस बात के पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिल सकते हैं लेकिन पर्याप्त संकेत अवश्य मौजूद हैं. बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद लगता है देश का माहौल अपेक्षाकृत सहिष्णु हो गया है और पुरस्कार लौटा रहे साहित्यकारों, फिल्मकारों आदि की आहत संवेदना पर मरहम लग गया हो. पुरस्कार वापसी की राजनीति पर इस स्तंभ में कई बार चर्चा हो चुकी है लेकिन इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में किस तरह से भारत की वैश्विक छवि को दरकाने की कोशिश की गई. आज जबकि भारत को विकास की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए विदेशी निवेश की सख्त आवश्यकता है. लंबे समय बाद देश में बहुमत वाली सरकार के आने के बाद विदेशी निवेशकों में आर्थिक सुधार को लेकर भरोसा बनना शुरू हुआ था लेकिन देश की राजनीति के चक्कर में विरोध पक्ष इतना आगे बढ़ गया कि उन्होंने हमारे देश को ही असहिष्णु घोषित करने का काम शुरू कर दिया. स्थितियां इस तरह की बनाई गईं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को मानवाधिकार का मुद्दा बना दिया गया, गैर सरकारी संगठनों के विदेशी चंदों की जांच और कुछ संगठनों पर पाबंदी को परोक्ष रूप से अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया गया. अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बताने वाले बहुधा यह भूल जाते हैं कि इतने तीखे विरोध की आजादी उनको है जिसमें वो पूरे देश की छवि को भी उन्मुक्त होकर दांव पर लगा सकते हैं. भारत के असहिष्णु होने की बात करनेवालों की अज्ञानता पर क्षोभ होता है. बगैर भारत को, उसकी संस्कृति को, उसके समाज को जाने–समझे उसके असहिष्णु होने की बात कहना और फिर उसको प्रचारित करने से पूरे देश की बदनामी होती है जिसके लिए किसी को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए. क्या कोई एक संगठन, एक व्यक्ति पूरे हिंदुत्व का ठेकेदार हो सकता है. कदापि नहीं. किसी एक संतनुमा नेता या नेत्री के बयान के आधार पर पूरे धर्म को कठघरे में खड़े करने से आरोप लगाने वाले समुदाय पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं. द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री और ऑन हिंदुइज्म जैसी किताब की लेखिका वेंडी डोनिगर ने भी अपनी किताब ऑन हिंदुइज्म में लिखा है–हिंदू धर्म की विशेषता उसकी विविधता है. हिंदू धर्म की एक और विशेषता है कि वो गैर हिंदुओं के आइडिया और परंपरा को भी अपने में आत्मसात कर लेती है. इस वजह से हिंदू धर्म इस्लाम, ईसाई धर्म आदि से बिल्किल अलग दिखता है. वो यह भी मानती है कि हिंदू धर्म की विविधता ही उसकी ताकत है और वो इस्लाम या क्रिश्चैनियटी की तरह एक खुदा, गॉड या एक भगवान के इर्द गिर्द नहीं घूमता है और न ही किसी एक किताब के आधार पर चलता है. हालांकि वेंडी डोनिगर इस बात पर चिंता जताती हैं कि हिंदू धर्म में कट्टरता के तत्व दिखाई देने लगे हैं लेकिन ये तत्व धार्मिक नहीं होकर राजनीतिक हैं. इस बात पर बहस हो सकती है लेकिन चंद लोगों के विवादित बयानों के आधार पर पूरे धर्म को या फिर पूरे देश को बदनाम करना बेहद आपत्तिजनक है.

देश में बढ़ते असहिष्णुता का प्रचार करने में कामयाबी पाने के बाद वही ताकतें अब विदेश में भी सक्रिय हो गई हैं और भारत की छवि पर बट्टा लगाने की कोशिश हो रही है. जब देश में पुरस्कार वापसी का आंदोलन चल रहा था तो अमेरिका और ब्रिटेन के अखबारों ने इस पर लेख लिखे थे. भारत को असहिष्णु बताने वाले इन अखबारों को अमेरिका में गुजरातियों और ब्रिटेन में सिखों पर नस्लीय हमले नजर नहीं आते हैं. दूसरे देश की चिंता करने के पहले इन अखबारों को अपने देश की कट्टरता को बेनकाब करना चाहिए. जब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर थे तो उनके वहां पहुंचने के दिन ही एक अखबार ने अनीश कपूर का एक लेख छापा. इस लेख का शीर्षक था– इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय अ हिंदू तालिबान. अनीश कपूर

के इस लेख में तमाम तरह की आपत्तिजनक बाते हैं जो ना सिर्फ भारत का अपमान है बल्कि यहां की सवा सौ करोड़ जनता का भी अपमान है. अनीश कपूर ने उत्साह में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लांघते और छिन्न भिन्न करते नजर आते हैं. अनीश कपूर ने अपने लेख की शुरुआत इस बात से की कि भारत में विविधता की संस्कृति गंभीर खतरे के दौर से गुजर रही है. कपूर इस बात को लेकर उत्तेजित नजर आते हैं कि मोदी सरकार उन अराजक हिंदुओं को सहन कर रही है जो बीफ खानेवालों को अनुशासित कर रहे हैं, जो जाति व्यवस्था के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के खिलाफ बोलनेवालों को कथित तौर पर सुधारने का काम कर रहे हैं. उत्तेजना में बहुधा लोग अतार्किक हो जाते हैं. यह अनीश कपूर की भड़ास है जो उनके लेख में उनके विचार के तौर पर सामने आई है. भड़ास इस वजह से क्योंकि उसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होता है. इस पूरे लेख में सिर्फ फतवेबाजी की गई है कहीं कोई दृष्टांत या तर्क नहीं है.

इस लेख का शीर्षक ही अनीश कपूर की भारत के बारे में अज्ञानता को प्रदर्शित करता है. अनीश को यह मालूम होना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि यहां कोई तालिबान शासन नहीं कर सकता है. दरअसल अनीश का यह लेख पूरे तौर पर भारत को बदनाम करने की मंशा से लिखा गया है. वो अपने लेख में लिखते हैं कि भारत को ब्रिटेन के लोग कश्मीर में हो रहे अत्याचार और हाल के दिल दहला देनेवाले रेप केस की वजह से जानते हैं. अनीश को कश्मीर में होनेवाला कथित अत्याचार दिखाई देता है लेकिन गुलाम कश्मीर में मानवाधिकार के उड़ रहे चीथड़े उनको दिखाई नहीं देते हैं. जिस ब्रिटेन का वो गुणगान करते नजर आ रहे हैं वहां सिखों पर पिछले दिनों हुए हमले का जिक्र नहीं करते हैं. कश्मीर के किस अत्याचार की बात कर रहे हैं अनीश? वहां लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार काम कर रही है. पता नहीं अनीश कपूर किस दुनिया में रहते हैं कि उनको भारत में हिंदू अत्याचार की लहर दिखाई दे रही है. अनीश ने अपने लेख में लिखा है कि भारत में हिंदू वर्जन ऑफ तालिबान अपना प्रभाव बढ़ा रहा है. अनीश को यह जानना आवश्यक है कि हिंदू और तालिबान दोनों दो ध्रुव हैं जो कभी नहीं मिल सकते. भारत की सवा सौ करोड़ जनता किसी भी प्रकार के तालिबान को पनपने नहीं देगी चाहे उसे राजाश्रय ही क्यों ना मिला हो? अनीश भारत के लोकतंत्र को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं. दरअसल उनके लेख की मंशा आखिर में आकर स्पष्ट होती है जहां वो ग्रीनपीस पर पाबंदी और तीस्ता शीतलवाड का मुद्दा उठाते हैं. तीस्ता किसी और वजह से नहीं बल्कि अपने ट्रस्ट के पैसों में हेराफेरी के आरोप में अदालतों के चक्कर लगा रही है. क्या सिर्फ इस बात को लेकर कि वो गुजरात दंगों के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही हैं उनको इस बात का हक मिल जाता है कि वो चंदे में गड़बड़ी के आरोपों से बच निकलें.

दरअसल अगर हम देखें तो यह एक बड़े अंतराष्ट्रीय डिजायन का हिस्सा नजर आता है. नरेन्द्र मोदी के दौरे के ठीक एक दिन पहले पेन इंटरनेशनल, जो कि साहित्य और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए काम करनेवाला संगठन है, के बैनर तले सलमान रश्दी जैसे करीब सौ लेखकों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र भेजा. इस पत्र में डेविड कैमरून से मांग की गई है कि वो भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कदम उठाएं. अपने पत्र में उन्होंने भारत में पिछले दो वर्षों में सार्वजनिक बुद्धिजीवियों पर हुए हमले को मुद्दा बनाया गया है. यह ठीक है कि हर संस्था को अपनी बात कहने का हक है लेकिन उतना ही हक उसका प्रतिवाद करने वाले को भी है. पेन इंटरनेशनल भी तब खामोश रही थी जब दाभोलकर की हत्या की गई थी, या जब कॉमरेड पनसारे को मार डाला गया था. विचार और धारा की लड़ाई में देश की छवि को बट्टा लगानेवालों को सोचना होगा क्योंकि इस लड़ाई से अंततः देश की जनता का नुकसान होगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

बेग़म एक हुकुम की उर्फ ब्लैक क्वीन

अनय शर्मा

गतांक से आगे...

जिस वक़्त दीवार के रोशनदान से धूप अन्दर आने की कोशिश में थी. किवाड़ के सुराख में छुपी हवा हांफ रही थी. चुंगी के नल पर बूंद–बूंद टपकते पानी के लिए औरतें लड़ रही थीं. जिस वक़्त रामसरन की बहू धीमी आवाज़ में रानी तुमसी तो बेहा हमने देखी नहीं, ओ राजा जो मैं होती ना बेहा तो तुमसे मेरी निभती नहीं गा रही थी. और जिस वक़्त चोरी–छुपे उर्मिला और अजीत नयी उम्र के सपनों में तार पिरो रहे थे. ठीक उसी वक़्त कुछ लोगों ने कारखाने से रामसरन को खींच कर एक पुरानी मारुती वैन में डाल दिया था.

शाम को जब अजीत धूल उड़ाता घर में घुसा तो रामसरन सामने बरामदे में लेटा हुआ था, शरीर पर जगह–जगह पट्टियां और पुल्टिस बंधीं थीं. अजीत ने देखा आस–पड़ोस की औरतें छोटे–छोटे घूंघट निकाले मां को घेरे बैठी थीं. वो अपने कमरे में जा रहा था कि पीछे से अम्मा की आवाज़ कानों में पड़ी,

इन अहीरों ने तो उत्पात मच रखा है, आये दिन जान पर सवार रहते हैं, और ये अजीत किसी की सुनता नहीं.

ठीक कह रहीं है आप ताई जी कोई भीड़ में से बोला.वैसे भी जवान बेटा और बिन–नकेल का बैल पीठ पर हाथ रखते ही सींग मारने को दौड़ता है.

बंद कमरे में अजीत ने सोचा अब पानी उतरने तक उसे कदम फूंक–फूंक कर रखने होंगे. पिता के कन्धों का भार अब उसके ऊपर ही था. मां की गृहस्थी चलाने के लिए अब उसे ही काम से लगना पड़ेगा.

उसकी ज़रा सी भूल का ये नतीजा था कि पिता के दोनों पांव जाते रहे, उसकी पढ़ाई छूटी और चूड़ी के एक कारखाने में नौकरी का आसरा रहा.एक–एक कर के छः महीने निकल गये. जब वो सुबह कारखाने जाता और शाम ढले धूल में लिपटा मोटरसाइकिल से उतरता तो मां का दिल भर आता था. चूड़ियों पर चढ़ने वाली हिल की हल्की पर्त चेहरे–हाथों पर चढ़ी रहती थी. बल्ब की हल्की रौशनी में उसका चेहरा ऐसे जगमगाता था जैसे किसी दुल्हन का सुनहरा आंचल हो. उस पर जब वो हर महीने अपनी तनख्वाह देता तो रामसरन की बहू की गर्दन तन जाती थी कि बेटा हो तो ऐसा. पर वो ये भूल जाती थी की इसी बेटे के कारण उसका घर परेशानियों की शरणस्थली बना. वो ये भी भूल जाती थी कि शांत समंदर में अनाड़ी मल्लाह की नाव हवा के एक हल्के झोंके से पलट सकती है. और वो यह भी न भांप सकी कि ये चुप्पी तूफानों से पहले की है.

आज खाना मत रखना मम्मी. अजीत ने बाथरूम से निकलते हुए आवाज़ लगाई.

क्यों ?

मैं आज आगरा जा रहा हूं मैच खेलने, कल शाम तक लौटूंगा.

और कारखाने?

दो दिन की छुट्टी पर हूं.

वो चुप रही सोचा लड़का पिछले सात–आठ महीने से खून जल रहा है अपना. अभी कोई उम्र है इसकी फैक्ट्री–कारखाने जाने की.

वो जब बन–संवर के घर से निकला तो रामसरन की बहू ने पीछे से चुपचाप उसकी बलैयां ले लीं.

****

अगले दिन तड़के ही पुलिस रामसरन के घर जा पहुंची.

लौंडा कहां है तेरा?

साब वो तो आगरे गया है मैच खेलने, शाम तक लौटने की बोल कर गया है.

कुछ हुआ क्या साब? रामसरन की बहू ने ओट से पूछा.

लड़की भगा ले गया तेरा लौंडा. सोलह साल की है. नाबालिग है. तगड़ा केस बने ही बने समझी.

रामसरन की बहू को ऐसा लगा जैसे पैरों की जान निकल जायेगी. गिरने से बचने के लिए उसने किवाड़ का पल्ला थाम लिया.

रोज़ मिलता था लड़की से मौका लगते ही ले उड़ा.

वो तो रोज़ कारखाने जाता था साब रामसरन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा.

साल सब झूठ, एक दिन नहीं गया फैक्ट्री. कितने ही यार–दोस्तों से पैसा उधार ले रखा है उसने पता है.

आजकल सरकार तुम्हारी है तो सालों पर ही निकल आयेंगे क्या? एक पुलिस वाला बोला, जल्दी बता कहां है लौंडा?

साब हम से तो आगरे की बोल के गया था.

जवाब पर किसी ने रामसरन का गिरेबान पकड़ कर तीन–चार थप्पड़ लगा दिये. उसके गले से एक घुटी सी चीख निकल कर रह गयी. उधर दरवाज़े की आड़ में खड़ी रामसरन की बहू कब की बेहोश होकर गिर पड़ी थी.

****

अगले तीन महीने तक पुलिस हर दूसरे दिन रामसरन के घर दबिश देती रही, फिर एकाएक आना बंद कर दिया. पता चला लड़की वापस लौट आई है तीन महीने बाद. कहां थी? किस के पास थी? कौन लौटा के लाया? या अपने आप आई? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे. सब अपने–अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे थे.

उर्मिला तो लौट आई पर अजीत नहीं लौटा. मां–बाप की आस टूटने लगी. महीनों दौड़ते–फिरते रहे पर नतीजा सिफ़र. फिर जब सरकार बदली तो रही–सही उम्मीद भी चुक गयी.

सूरज उगा और डूबा, फिर उगा और फिर डूबा, और यूं ही चार साल का वक़्त बीत गया.

रामसरन और उसकी बहू अब इस अंदेशे को सच मान चुके थे कि उनका लड़का जान से जाता रहा.

****

झालरों की जगमगाहट दूर ही से बता देती थी कि ये शादी के उत्सव की चकाचौंध है. पूरी गली के सिर पर पंडाल तना था. अप्रैल की चढ़ती गर्मी में शादी थी. उदास सी शाम हल्के–हल्के

हांफ रही थी और ऐसा लगता था जैसे आंधी आने के आसार हों.

किसी ने आवाज़ लगाई, अरे भई राजू जल्दी–जल्दी जाओ कल के लिए जनवासे का इंतजाम देखो. भई जितेन्दर कहां है अब? पता है किसी को.

अरे गोल कमरे में पत्ते खेल रहे हैं सब वही है.

अच्छा.

एक लड़की ने दरवाज़ा धकेला और कमरे में घुस गयी. उर्मिला सामने पलंग पर बैठी थी.

अरे सुधा! व्हाट ए सरप्राइज़, उर्मिला ने पलंग से कूदते हुए कहा. शादी कल है और तू आज आ रही है.

रिजर्वेशन ही बड़ी मुश्किल से मिला, वो भी अकेली का. सुधा ने कहा.

और जीजाजी?

कैसे आते, एक ही टिकट मिला कन्फर्म.

हाय!

जब–तक उसने हाथ–मुंह धोये तब–तक उर्मिला चाय ले आयी.

तुझे आज पूरे चार साल बाद देख रही हूं, सुधा ने कहा.

हाँ, उन दिनों बड़े रेस्ट्रिक्शन हो गए थे मुझ पर.

दोनों सहेलियां बहुत देर तक बातें करती रहीं, नीचे से तैरते हुए आवाजें ऊपर चली आ रहीं थीं.

वो मारा, ये लो बेटा अब तो गयी हुकुम की बेग़म तुम पर, 12 पॉइंट्स का दंड लगेगा, फ़ाईन लगेगा तुम पर.

क्या खेला जा रहा है भई?

ब्लैक क्वीन, इसमें हुकुम की बेग़म जिस पर जाती है उसकी हार हो जाती है.

चाय का प्याला ट्रे में रखते हुए सुधा ने पूछा. और वो लड़का?

उसका तो कांड जितेन्दर भाई ने वहीं कर दिया था बंगलौर में. उर्मिला ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो.

और पुलिस को क्या कहा तूने?

मैं मुकर गई, कह दिया मौसी के घर थी. मामला बिगड़ गया था बड़ा.

तू मुकर कैसे गयी उर्मिला?

जान से मार देते मुझे भी. देख आज भी शरीर पर निशान हैं मेरे, उर्मिला ने कोहनी की तरफ़ इशारा कर के कहा.

पर वो बेचारा तो जान से गया.

अब गया सो गया. अरे मुझे अपनी जान प्यारी थी. तू जानती नहीं क्या जितेन्दर भाई को.आंधी का सा मौसम हो रहा है, मैं एक–एक कप चाय और लाती हूं तू ज़रा खिड़की बंद कर ले.इतना कह कर उर्मिला कमरे के बाहर चली गयी.

सुधा उठी और खिड़की पर जा खड़ी हुई. हवा में तेजी आ गयी थी, अगले तीन–चार मिनट में आंधी का आना निश्चित था. वो जब तक खिड़की बंद करती तब तक हवा का एक तेज झोंका कमरे में घुस आया. उसने धूल–मिट्टी से बचने के लिए अपना मुंह फेर लिया.हवा के साथ कूड़ा–कर्कट भी फड़फड़ाता हुआ कमरे के अन्दर चला आया था. सुधा ने खिड़की बंद की तो देखा कि ताश का एक फटा पत्ता उड़ कर ड्रेसिंग टेबल के आईने से चिपक गया है. उसने जाकर पत्ता उठाया तो देखा की ये एक हुकुम की बेग़म थी. हठात उसके दिल से निकला तुम जिसके भी पास रहीं उर्मिला उस पर दंड लगाती रहीं, फ़ाइन लगाती रहीं. उर्मिला तुम भी एक हुकुम की बेग़म हो उर्फ़ ब्लैक क्वीन, उसने कहा.

क्या? पीछे खड़ी उर्मिला ने पूछा.

कुछ नहीं, बस यूं ही. *(समाप्त)*

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

दिल्ली से लगभग ढाई सौ किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखण्ड में स्थित मसूरी सैर–सपाटे के लिए लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक है. समुद्र तट से सात हजार फुट की ऊंचाई पर बसा मसूरी शहर कई मामलों में निराला है. सबसे खास बात यह है कि यहां पर किसी भी समय बारिश का मौसम बन जाता है. मसूरी के एक ओर से गंगा नजर आती है, तो दूसरी ओर से यमुना नदी. मसूरी शहर 1822 से बसना शुरू हुआ था और आज तक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

फैशन

लाहौर में पीएफडीसील ओरियल पेरिस ब्राइडल वीक 2015 के फैशन शो में रैंप पर दुल्हन के परिधानों का प्रदर्शन करतीं पाकिस्तानी मॉडल्स.

खाना पीना

स्वादिष्ट बटर चिकन जो मुंह में ला दे पानी

नॉर्थ इंडियन डिश में बटर चिकन काफी फेमस नॉन–वेज व्यंजन है. अगर आप चिकन लवर हैं, तो घर पर ही बनाइये मुंह में घुलने वाला बटर चिकन. बटर चिकन की इस रेसिपी में कोई ताम–झाम भी नहीं है. इसमें चिकन को मैरिनेट करने की भी जरूरत नहीं है. आइये, आपको बताते हैं घर बैठे–बैठे कैसे बनाते हैं बटर चिकन.

सामग्री

चिकन–500 ग्राम बोनलेस, प्याज–4, टमाटर–3, अदरक लहसुन पेस्ट–1 चम्मच, हल्दी पावडर–1 चम्मच, लाल मिर्च पावडर–1 चम्मच, धनिया पावडर–1 चम्मच, कसूरी मेथी–1 चम्मच, नमक–स्वादानुसार, टमैटो सॉस–1 चम्मच, बटर–2 चम्मच, हरा धनिया, गरम पानी–1 कप, क्रीम–2 चम्मच

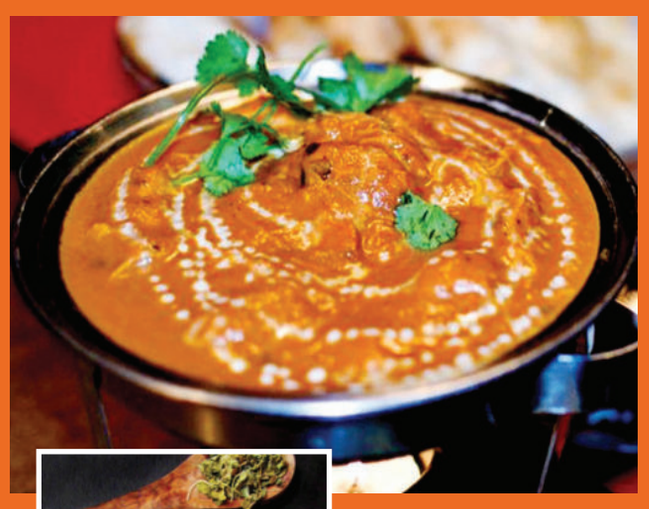

विधि–

1. सबसे पहले प्याज को बारीक पीस लें और टमाटर को भी बारीक पीस कर अलग रख दें. चिकन पीस को धो कर साफ करें और अलग रख दें. बटर को कुकर में गरम करें, उसमें पिसी प्याज डाल कर 5–7 मिनट तक पकाएं. इसके बाद इसमें अदरक–लहसुन का पेस्ट डालें और 3 मिनट तक पकाएं. फिर चिकन पीस को डालें और भूनें. अब इसमें टमाटर का रस डालें, हल्दी पावडर, लाल मिर्च पावडर, धनिया पावडर और नमक डाल कर 10 मिनट तक पकाएं. अब इसमें टमैटो सॉस और कसूरी मेथी डाल कर मिक्स करें. इसके बाद इसमें गरम पानी डालें और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा कर बंद कर दें. आंच धीमी रखें और चिकन को पकने दें. 3 सीटी आने के बाद कुकर को बंद कर दें और भाप निकलने दें. इसके बाद चिकन को चेक कर के देखें कि वह अच्छी प्रकार से पका या नहीं. एक बार चिकन पक जाने के बाद इसे प्लेट में निकालकर हरी धनिया और क्रीम से गार्निश करें और परोसें. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

करियर

ज्वेलरी डिजाइनिंग में बनाएं करियर

अगर आपकी रुचि डिजाइनिंग क्षेत्र में जाने की है, तो ज्वेलरी डिजाइनिंग आपके लिए एक बेहतर करियर विकल्प है. भारतीय आभूषण बाजार में बड़े–बड़े देशी और विदेशी ब्रांड्स जैसे तनिष्क, स्वरोवस्की, डी बीयर्स, डी डमास, टिफनीज, आईटीसी लाइफ स्टाइल, गीतांजलि ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड बहुत तेजी के साथ अपनी जगह बना रहे हैं. जहां नए ब्रांड अपने पांव जमाएंगे, वहां उनके कारोबारी सपनों को पूरा करने के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत तो पड़ेगी ही. आभूषणों में अलग–अलग रंगों और आकारों का चलन तेजी से ग्राहकों के बीच अपनी जगह बना रहा है. यह चलन किसी और की नहीं, बल्कि ज्वेलरी डिजाइनर्स की देन है. ज्वेलरी इंडस्ट्री भी देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनती जा रही है. इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, कि इस इंडस्ट्री की क्षमता 2015 तक 2.15 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. ऐसे में युवाओं के लिये ज्वेलरी डिजाइनिंग करियर के लिहाज से एक बेहतर विकल्प है. एनएसडीसी के अनुसार, 2022 तक इस क्षेत्र में करीब 80 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है.

वर्तमान में देखा जाए तो सोने की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए देश में कई इंस्टीट्यूट ने ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्सेज शुरू किए हैं. कुछ इंस्टीट्यूट में छात्रों को कंप्यूटर की सहायता से भी ज्वेलरी डिजाइनिंग की शिक्षा दी जाती है. इस कोर्स को करने के लिए कम से कम स्नातक होना आवश्यक है.

प्रमुख कोर्स

- डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिजाइन एंड जैमोलॉजी (2 वर्ष).
- डायमंड ग्रेडिंग कोर्स (2 माह).
- सर्टिफिकेट इन ज्वेलरी डिजाइन एंड जैमोलॉजी (1 साल).
- जैम आइडेंटिफिकेशन (3 माह).
- शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज इन जैमोलॉजी, पॉलिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग.

कहां से करें कोर्स:

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, जयपुर
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी, मुंबई
- सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई

नौकरी के अवसर

प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, ज्वेलरी हाउसेस, रिसर्च एंड ऑर्गनाइजेशन, ऑक्शन हाउसेस में नौकरी मिलने के चांसेस रहते हैं. अगर आप चाहें तो फ्रीलांस डिजाइन के जरिए अपने बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सैर–सपाटा

पहाड़ों की रानी मसूरी है अद्भुत

पतली घुमावदार सड़कें, हरे–भरे पेड़, जहां तक नजर दौड़ायें, वहां तक सिर्फ सफेद पहाड़, दूसरी ओर पहाड़ों की गोद में बने छोटे–छोटे घर, यानी देहरादून शहर में आकर कोई भी रोमांचित हो सकता है, क्योंकि यहां कि मदमस्त हवा किसी को भी अपना बना सकती हैं. हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी की. दिल्ली से लगभग ढाई सौ किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखण्ड में स्थित मसूरी सैर–सपाटे के लिये लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक है. समुद्रतट से सात हजार फुट की ऊंचाई पर बसा मसूरी शहर कई मामलों में निराला है. सबसे खास बात है कि यहां पर किसी भी समय बारिश का मौसम बन जाता है. मसूरी के एक ओर से गंगा नजर आती हैं तो दूसरी ओर से यमुना नदी. मसूरी शहर 1822 से बसना शुरू हुआ था और आज तक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां से दून वैली और मसूरी का नजारा देखना बेहद खूबसूरत लगता है. सुबह–शाम घूमने के लिए निकलने वालों के लिए कैमल बैक रोड पसंदीदा स्थान है. मसूरी आने वाले सैलानी यहां शाम के समय छिपता हुआ सूरज यानी सनसैट देखने के लिए जरूर आते हैं. यह खूबसूरत हिल स्टेशन यहां स्थित प्राचीन मंदिरों, पहाड़ियों, झरनों, घाटियों, और वन्यजीवों के लिए लोकप्रिय है.

ज्वाला देवी मंदिर और भद्रराज मंदिर, मसूरी और उसके आसपास स्थित कुछ नामचीन धार्मिक स्थलों में से एक हैं. यहां का ज्वाला देवी मंदिर, देवी दुर्गा को समर्पित है. मसूरी की एक पहाड़ी से हर दोपहर को तोप से गोला दागा जाता था, ताकि स्थानीय लोगों को समय बताया जा सके. उस समय लोग अपनी घड़ियों को उसी अनुसार सेट कर लिया करते थे. यहां की पहाड़ी पर पर्यटकों के बीच रोप–वे पर सैर करना काफी लोकप्रिय है. लाल टिब्बाह, मसूरी का सबसे ऊंचा प्वॉइंट है. इस पहाड़ी पर पर्यटकों की सुविधा के लिए रखे गए दूरबीन यानी टेलीस्कोप के माध्यम से पर्यटक नजदीक के इलाके बंदेरपुंछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ को देख सकते हैं. मसूरी में बहने वाले खूबसूरत झरनों में कैम्प्टी, झरीपानी, भट्टा और मोस्सी प्रमुख हैं.

किस मौसम में जाएं

मसूरी का मौसम हर महीने बेहद खुशनुमा रहता है. इसी वजह से हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं. यह हिल स्टेशन सभी मौसम में सुंदर लगता है. हालांकि, मसूरी घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितम्बर से नवंबर के बीच होता है.

कैसे जाएं

मसूरी आसानी से भारत के अन्य भागों से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है. इस गंतव्य का सबसे नजदीकी एयरबेस जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो देहरादून में बना हुआ है. इस एयरपोर्ट की मसूरी से दूरी 60 किलोमीटर है. देहरादून रेलवे स्टेशन मसूरी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है. ■

करियर की अच्छी शुरुआत के बाद साल 2009 में वह अपने करियर के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, साल 2010-11 की एशेज सीरीज के दौरान उनका करियर अंधकारमय नज़र आने लगा था. लेकिन इस दौरान टखने की चोट की वजह से उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा. वापसी के लिए वह एक बार फिर डेनिस लिली की शरण में पहुंचे, लिली के साथ ट्रेनिंग करना उनके लिए वरदान साबित हुआ. इस दौरान जॉनसन ने अपने रनप को थोड़ा छोटा किया, ऐसा करके वह और ज्यादा घातक हो गए थे.

क्रिकेट

रफ़्तार के शहंशाह

मिचेल जॉनसन का संन्यास

मिचेल जॉनसन कोई आम गेंदबाज नहीं थे उनके जैसे गेंदबाज सदी में एक बार पैदा होते हैं ऐसा डेनिस लिली ने एक बार कहा था. आक्रामक, बेखौफ, ख़तरनाक, अद्भुत, बेजोड़ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कॉमेंट्रेटर अक्सर आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन के लिए किया करते थे, लेकिन उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद किसी भी गेंदबाज की तारीफ में इन शब्दों का इस्तेमाल वे बहुत कम और सधे हुए अंदाज में ही कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले उनके जेहन में मिचेल की छवि उभरकर सामने आ जाएगी.

साल 2015 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए संन्यास का साल बनकर आया है, एक के बाद एक छह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इस साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. संन्यास लेने वाले छठवें खिलाड़ी तेज़ गेंदबाज मिचेल जॉनसन हैं. मिचेल से पहले माइकल क्लार्क, ब्रेड हैडिन, क्रिस रोजर्स, रेयान हैरिस और शेन वाटसन ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. मिचेल ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ पर्थ में खेले जा रहे शृंखला के दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन संन्यास की घोषणा की. उन्होंने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि, मुझे लगता है कि क्रिकेट को अलविदा कहने का यह सही समय है. मैं काफी भाग्यशाली रहा हूं कि मेरा करियर शानदार रहा और देश के लिए खेलते हुए मैंने प्रत्येक क्षण का मजा लिया. यह एक अद्भुत सफर था लेकिन इस सफर को कहीं तो रुकना ही था और वाका में ऐसा करना बेहद खास है. मैंने काफी सोच-विचार कर यह फैसला लिया है. मुझे नहीं लग रहा था कि इस मैच के बाद मैं उसी जोश के साथ प्रदर्शन कर पाऊंगा.

मिचेल की संन्यास की घोषणा के ठीक पहले वाका मैदान पर उनके खराब प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने टिप्पणी की थी कि मिचेल को अब संन्यास ले लेना चाहिए. पर्थ में खेले जा रहे टेस्ट मैच की पहली पारी में मिचेल ने 157 रन देकर केवल एक विकेट हासिल किया था. न्यूज़ीलैंड के केन विलियम्सन और रॉस टेलर ने उनकी गेंदों की जमकर धुनाई की. करियर की अंतिम और टेस्ट की दूसरी पारी में भी मिचेल महज दो विकेट हासिल कर सके. 157 रनों पर एक विकेट, पर्थ की तेजतर्रार पिच पर किसी भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के आजतक के सबसे खराब आंकड़े हैं. इन आंकड़ों को देखते हुए टेलर ने कहा था कि भले ही यह टेस्ट मिचेल के करियर का आखिरी टेस्ट न हो, लेकिन प्रशंसक जल्दी ही उनकी विदाई देखने वाले हैं. हालांकि मैच के शुरू होने से पहले जॉनसन ने कहा था, जब तक मैं जबतक अच्छा प्रदर्शन करता रहूंगा और टीम के लिए योगदान देता रहूंगा तब तक खेलता रहूंगा. लेकिन अब यह माना जा रहा है कि पर्थ टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने संन्यास का निर्णय ले लिया.

पिछले महीने फॉक्स स्पोर्ट्स के लिए लिखे एक कॉलम में मिचेल ने संन्यास के संकेत दिए थे. उस कॉलम में उन्होंने लिखा था कि इस साल एशेज में मिली हार के बाद से ही वह रिटायर्मेंट के बारे में सोच रहे हैं. उन्होंने यह भी लिखा था कि जब मैं पर्थ वापस आया और टीवी पर मेटाडोर कप देख रहा था तो मैंने पाया कि कई नए लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इससे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने करियर में कहां हूं? लेकिन संन्यास की घोषणा करते वक्त जॉनसन ने कहा कि मैंने बहुत सोच-समझ कर यह फैसला लिया है. इस मैच के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं बैगी ग्रीन (टीम ऑस्ट्रेलियाई की क्रिकेट कैप) पहनने के लिए उस लेवल की मेहनत करने के काबिल हूं. आज से दो साल पहले साल 2013-14 में घरेलू सरजमीं पर इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में 5-0 के अंतर से मिली जीत का सेहरा मिचेल के सिर सजा था. सीरीज में अपनी तूफानी गेंदबाज़ी के दम पर मिचेल ने 37 विकेट झटककर इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया था. इसके बाद उसी सीजन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जॉनसन ने 22 विकेट चटकाए थे. यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ दौर था. इसके बाद मिचेल के प्रदर्शन में वह आक्रामकता नहीं दिखाई दी. साल 2007 में टेस्ट करियर का आगाज करने वाले मिचेल को ग्लेन मैग्रा के संन्यास के बाद टीम में जगह मिली थी. महान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज डेनिस लिली ने 17 वर्ष की उम्र में मिचेल की प्रतिभा को पहचाना था और कहा था कि मिचेल जैसे गेंदबाज सदी में एक बार पैदा होते हैं.

मिचेल ने अंतरराष्ट्रीय करियर में 73 टेस्ट, 153 एक दिवसीय और 30 टी-20 मैच खेले. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 28.40 की औसत से 313 विकेट हासिल किए. टेस्ट विकेटों के मामले में वह शेन वार्न (708), ग्लेन मैक्ग्राथ (563) और डेनिस लिली (355) के बाद चौथे पायदान पर हैं. उन्होंने पर्थ टेस्ट में डग ब्रेसवेल का विकेट लेकर ब्रेट ली को पीछे छोड़ा था. उन्होंने 153 वनडे मैचों 25.26 की औसत से 239 और 30 टी-20 मैचों में 20.97 की औसत से 38 विकेट हासिल किए. सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में वह विश्व के गेंदबाजों की सूची में 25 वें पायदान पर हैं.

मिचेल की जिम्मेदारी को निभाने के लिए टीम में मिचेल स्टार्क पूरी तरह तैयार हैं, विश्वकप में मैन ऑफ द सीरीज बनने से लेकर अब तक स्टार्क ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वह हर कदम पर जॉनसन से बेहतर साबित हुए हैं, ऐसे में बढ़ती उम्र और गिरते फॉर्म के कारण वह अंदर ही अंदर संन्यास लेने का मन बना रहे थे. ऐसे में यदि उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाता तो उनके लिए टीम में वापसी कर पाना बेहद कठिन हो जाता. इसलिए जॉनसन ने सही समय पर सही फैसला करते हुए मैदान पर सक्रिय रहते हुए क्रिकेट को अलविदा कह दिया. अब अगली ऐशेज से पहले टीम को नए सिरे से तैयार करने का कप्तान स्टीव स्मिथ के पास पूरा मौका है ताकि वह अपनी तरकश में आए नए तीर को अनुभव की कसौटी पर कसकर और पैना कर सकें.

करियर की अच्छी शुरुआत के बाद साल 2009 में वह अपने करियर के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, साल 2010-11 की ऐशेज सीरीज के दौरान उनका करियर अंधकारमय नज़र आने लगा था. लेकिन इस दौरान टखने की चोट की वजह से उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा. वापसी के लिए वह एक बार फिर डेनिस लिली की शरण में पहुंचे, लिली के साथ ट्रेनिंग करना उनके लिए वरदान

> दो साल पहले साल 2013-14 में घरेलू सरजमीं पर इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में 5-0 के अंतर से मिली जीत का सेहरा मिचेल के सिर सजा था. सीरीज में अपनी तूफानी गेंदबाज़ी के दम पर मिचेल ने 37 विकेट झटककर इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया था. इसके बाद उसी सीजन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जॉनसन ने 22 विकेट चटकाए थे. यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ दौर था.

साबित हुआ. इस दौरान जॉनसन ने अपने रनप को थोड़ा छोटा किया, ऐसा करने वह पहले से ज्यादा घातक हो गए थे. उनकी टीम में वापसी ज्यादा धमाकेदार नहीं रही लेकिन वह धीरे-धीरे अपनी लय हासिल करने में सफल रहे. 2013 में भारत दौरे पर आई टीम में उन्हें जगह मिली लेकिन इसके बाद इंग्लैंड में खेली गई एशेज के लिए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया. इसके बाद जब उन्हें 2013-14 में घरेलू सरजमीं पर ऐशेज खेलने का मौका मिला तो जॉनसन ने लोगों को लिली-थॉमसन की जोड़ी की याद दिला दी. इस सीरीज में वह इतने आक्रामक थे कि कोई भी इंग्लिश गेंदबाज उनके सामने नहीं टिक पाया. उन्हें मैन ऑफ दि सीरीज चुना गया. उनकी कलाई की पोजिशन का उनकी गेंदबाजी में बड़ा योगदान रहा, यदि उनकी कलाई की दिशा सही है, दुनिया में उनसे बेहतर कुछ ही चुनिंदा गेंदबाज हुए हैं, लेकिन कलाई की पोजीशन सही नहीं है तो इनके जैसा असरहीन तेज़ गेंदबाज भी दूर-दूर तक नहीं दिखाई देता था. लेकिन वह अपनी गेंदों में जिस तरह स्लोअर्स और बाउंसर्स का मिश्रण करते थे वह बल्लेबाजों को अचंभे में डालने के लिए काफी था. इन्हीं सभी विधाओं की वजह से वह आज दुनिया के सफलतम गेंदबाजों में से एक हैं. भले ही उन्हें बायें हाथ का सर्वकालिक महान गेंदबाज नहीं कहा जाए, लेकिन उन्हें दुनिया के बायें हांथ के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में हमेशा शुमार किया जाएगा और उनकी बेखौफ गेंदबाजी के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.■

नवीन चौहान
navinonline2003@gmail.com

मिचेल जॉनसन का प्रदर्शन

एक टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 12-127 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका सेंचुरियन- 2014

टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ 8-61 बनाम दक्षिण अफ्रीका, पर्थ-2008

एकदिवसीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ 6-31 बनाम श्रीलंका, कैंडी-2011

साल 2009,2014 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए.

घरेलू क्रिकेट में होगी धोनी की वापसी!

> झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के सचिव राजेश वर्मा ने कहा कि धोनी ने राज्य की टीम से खेलने की इच्छा व्यक्त की है. वर्मा ने कहा, हमने धोनी से बात की और उन्होंने कहा कि वह विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से खेलने के लिए संभवत: उपलब्ध रहेंगे.

भारतीय वन-डे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आठ साल बाद घरेलू क्रिकेट में खेल सकते हैं. यदि अगले महीने पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं होती है, तो वह झारखंड की तरफ से विजय हजारे टॉफी में खेलते दिख सकते हैं. झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के सचिव राजेश वर्मा ने कहा कि धोनी ने राज्य की टीम से खेलने की इच्छा व्यक्त की है. वर्मा ने कहा, हमने धोनी से बात की और उन्होंने कहा कि वह विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से खेलने के लिए संभवत: उपलब्ध रहेंगे. हमने इस पर चर्चा नहीं की कि वह कितने मैचों में खेलेंगे या वह टीम की अगुवाई करेंगे. लेकिन यदि वह चाहते हैं तो वही टीम का नेतृत्व करेंगे. धोनी ने 2007 में भारतीय टीम के विश्व कप के पहले दौरे से बाहर होने के बाद आखिरी बार झारखंड की तरफ से पूर्व क्षेत्र चरण में सैयद मुश्ताक अली टी-20 चैंपियनशिप में कोलकाता में खेले थे. वर्मा ने कहा, उनकी उपस्थिति से निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा. धोनी को जब भी मौका मिलता है वह खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं. एक दिन पहले ही मैंने उन्हें मुख्य स्टेडियम में अकेले अभ्यास करते हुए देखा था. अभी हमारी सीनियर

टीम रणजी ट्रॉफी के लिए त्रिपुरा में है. धोनी अब टेस्ट खिलाड़ी नहीं है. उन्होंने अपना आखिरी वनडे 25 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. यदि पाकिस्तान सीरीज नहीं होती है तो भारत को सीमित ओवरों की अगली सीरीज जनवरी में ऑस्ट्रेलिया से खेलनी है. इस तरह से धोनी लगभग तीन महीने तक मैच अभ्यास नहीं कर पाएंगे. इसलिए वह 50 ओवरों के मैचों में खेलना चाहते हैं.■

एक खेल ऐसा भी...

थांग-ता

थांग-ता पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का एक खेल है, जो एक प्रकार का मार्शल आर्ट है जो कि मूल रूप से मैतेई लोगों द्वारा खेला जाता है. थांग का अर्थ होता है तलवार और ता का अर्थ होता है भाला. इन दोनों हथियारों की मदद से इस खेल को खेला जाता है. यह आत्मरक्षा या लड़ाई के मैदान पर उपयोग में आने वाली विधा है. इसे यहां स्कूलों में सिखाया जाता है. यह गुरू-शिष्य परंपरा से से आगे जाने वाला खेल है, जिसकी बारीकियां गुरू अपने शिष्य को सिखाता है. अंग्रेजी शासन के दौरान(1891-1947) तक इस खेल पर प्रतिबंध था. मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका उपयोग अंग्रेजों के साथ लोहा लेने में किया था. साल 1976 के बाद इसका प्रदर्शन मेलों और विदेशों में भी होने लगा.

यह खेल जानकारी के अभाव में अपने वजूद को खो रहा है, इस खेल का सांस्कृतिक के साथ-साथ आध्यात्मिक महत्व भी है. इसलिए नाटकों के जरिए इस खेल को बचाने का संदेश भी लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है. खेल की शुरूआत खुरुंबा से होती है जिसका अर्थ अपने प्रतिद्वंदी के साथ-साथ दर्शकों का झुककर अभिवादन करना होता है. खिलाड़ी पारंपरिक धोती पहनकर इस खेल को खेलते हैं. इस खेल को भारतीय ओलंपिक संघ ने भी मान्यता दी है.■

यूं ना भूला पाएंगे...

कैप्टन रूप सिंह

जाने-माने भारतीय हॉकी खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह हॉकी के जादूगर ध्यान चंद के छोटे भाई थे. उनका जन्म 28 सितंबर, 1906 को मध्यप्रदेश के जबलपुर में हुआ था. वह साल 1932 और 1936 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे. ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी का भाई होने के बावजूद उन्होंने हॉकी में अपनी अलग पहचान बनाई थी. वह आज भी भारत के सर्वकालिक महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने 1932 के ओलंपिक में जापान के खिलाफ 3 और अमेरिका के खिलाफ 10 गोल दागने का कारनामा किया था. कई बार भाई ध्यानचंद उन्हें अच्छे से खेलने के लिए आगाह करते थे. उन्हें लगता था उनके खेलने के तरीके से किसी को चोट न लग जाए. आज भी उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

के लिए जाना जाता है. रूप सिंह का परिवार ग्वालियर में रहता था वह सिंधिया रियासत की सेना में कार्यरत थे. ग्वालियर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उनके नाम पर है. यह स्टेडियम मूल रूप से हॉकी का था जिसे साल 1988 में क्रिकेट के मैदान में परिवर्तित कर दिया गया. 1936 में बर्लिन ओलंपिक धमाकेदार प्रदर्शन के बर्लिन में एक मार्ग का नाम रूप सिंह के नाम पर रख दिया गया था. साल 2012 में हुए लंदन ओलंपिक के दौरान उनके सम्मान में एक मेट्रो स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा गया था. इनके अलावा ध्यानचंद और लॉडली क्लॉडियस के नाम पर भी स्टेशनों का नामकरण किया गया था. 16 दिसंबर,1969 को 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

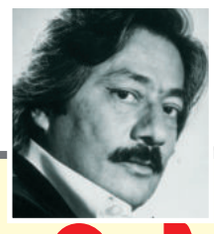

श्रद्धांजलि

सईद जाफ़री ने कहा दुनिया को अलविदा

छह दशक लंबे अपने अभिनय करियर में उन्होंने 150 से ज्यादा ब्रिटिश, हिंदी और अमेरिकी फिल्मों में काम किया था. वह अपने अभिनय के प्रति इतने संजीदा थे कि वह कभी भी सेट पर बिना प्रैक्टिस के नहीं पहुंचे. अपनी लगन और बेहतरीन अदाकारी के बल पर वह छोटे से छोटे रोल में भी जान डाल देते थे. कुछ ऐसा ही उन्होंने साल 1975 में रुडयार्ड किपलिंग के उपन्यास हू विल बी द किंग पर बनी फिल्म में गाइड बिली फिश की भूमिका अदा करके किया था.

अपनी बेहतरीन अदाकारी के बल पर बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मशहूर अभिनेता सईद जाफ़री का लंदन में 15 नवंबर को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. सईद का जन्म 08 जनवरी 1929 को पंजाब के मलेरकोटला एक पंजाबी मुस्लिम परिवार हुआ था. सईद हिंदी सिनेमा का एक बेहतरीन नगीना थे. वह अपने आप में अनूठे और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे. छह दशक लंबे अपने अभिनय करियर में उन्होंने 150 से ज्यादा ब्रिटिश, हिंदी और अमेरिकी फिल्मों में काम किया था. वह अपने अभिनय के प्रति इतने संजीदा थे कि वह कभी भी सेट पर बिना प्रैक्टिस के नहीं पहुंचे. अपनी लगन और बेहतरीन अदाकारी के बल पर वह छोटे से छोटे रोल में भी जान डाल देते थे. कुछ ऐसा ही उन्होंने साल 1975 में रुडयार्ड किपलिंग के उपन्यास हू विल बी द किंग पर बनी फिल्म में गाइड बिली फिश की भूमिका अदा करके किया था. इस छोटे से रोल से उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली थी. अस्सी और नब्बे के दशक में उन्हें हाई प्रोफाइल एशियाई अभिनेता माना जाता था.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सेंट जॉर्ज कॉलेज मैसूर से उच्च शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने कई सालों तक दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक कार्टूनिस्ट या लेखक के रूप में अपनी किस्मत आजमाने दिल्ली आ गए. उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एनाउंसर का ऑडिशन पास कर लिया और यहां काम करने लगे. इस दौरान उन्होंने फ्रैंक ठाकुरदास के साथ मिलकर युनिटी थियेटर की शुरुआत की, यहीं पर उनके फिल्मी करियर की नींव पड़ी. 50 के दशक में अपने थिएटर ग्रुप में काम के दौरान उन्हें

मधुर बहादुर नाम की अभिनेत्री से प्यार हो गया. हालांकि उन्होंने मधुर के परिवार से उनका हाथ मांगा लेकिन सईद की आर्थिक स्थिति देखकर उनके पिता ने इस रिश्ते से इंकार कर दिया. इसके बाद सईद थियेटर ड्रामा की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहां उन्हें अमेरिका में ड्रामा की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली. अगले ही साल वह न्यूयॉर्क चल गए. इस दौरान उन्होंने मधुर से शादी भी कर ली. इन दोनों की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी 1964 में दोनों ने तलाक ले लिया. तलाक़ के बाद वह इंग्लैंड आकर बस गए, इसके बाद भी वह हिंदी फिल्मों में काम करते रहे. साल 1986 में आई फिल्म माई ब्यूटीफुल लॉन्डरेट के लिए उन्हें बाफ्टा पुरस्कार में नामांकन भी मिला, यह उस वक्त किसी भी एशियाई कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात थी.

ऐसे तो सईद का हर एक किरदार अपने आप में बेहतरीन है लेकिन फिल्म शंतरंज के खिलाड़ी और एटनबरो की फिल्म गांधी में बल्लभ भाई पटेल की उन्होंने बेहतरीन भूमिका अदा की. उन्होंने हिना, मासूम, गांधी, चश्मे बद्दूर, राम तेरी गंगा मैली, दिल, दीवाना मस्ताना, किशन कन्हैया जैसी कई सफल हिंदी फिल्मों में काम किया. इसके साथ ही उन्होंने द मैन हू वुड बी किंग, ए पैसेज टू इंडिया, द फ़ार पवेलियंस जैसी अंग्रेजी फ़िल्मों में भी काम किया. पियर्स ब्रॉसन, शॉन कोनरी और माइकल केन जैसे जाने–माने सईद जाफरी के सह कलाकार रह चुके हैं. वहीं तंदूरी नाइट्स और ज्वेल इन द क्राउन जैसे टीवी शो के लिए भी सईद जाने जाते रहे हैं. सईद जाफ़री ने महात्मा गांधी के जीवन पर बनी रिचर्ड एडिनबरो की ऑस्कर विजेता फ़िल्म गांधी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई थी. जाफरी को साल 1978 में आई सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में मीर रोशन अली के किरदार के लिए फिल्मफेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था. सईद पहले भारतीय थे जिन्हें आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाज़ा गया था. साल 2010 में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. शतरंज के इस खिलाड़ी ने अभिनय के क्षेत्र में जो चालें चलीं वो लोगों को बरसों तक याद रहेंगी. सईद जाफरी जैसे कलाकारों के कारण ही आज भारतीय कलाकारों और भारतीय सिनेमा की पहचान विश्व के हर कोने में है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

भूमिका चावला की वापसी

भूमिका आखिरी बार हिन्दी फिल्म गांधी–माई फादर में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने कई कन्नड़, तेलुगू, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया.

भूमिका चावला याद हैं आपको? सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में लीड रोल अदा करने वाली भूमिका चावला. साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म तेरे नाम की सफलता के बाद भूमिका एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं. भूमिका आखिरी बार हिन्दी फिल्म गांधी–माई फादर में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने कई कन्नड़, तेलुगू, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया. लेकिन लंबे अरसे बाद उनकी झोली में कोई बड़ी हिन्दी फिल्म आई है. भूमिका को क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बन रही फिल्म एमएस धोनी–दि अनटोल्ड स्टोरी लिए साइन किया गया है. वह इस फिल्म में वह एक अहम किरदार में नजर आएंगी. इस खबर की पुष्टि स्वयं भूमिका चावला ने एक अंग्रेजी अखबार से हुई बातचीत के दौरान की है. उन्होंने कहा, हां मैं यह फिल्म कर रही हूं, लेकिन इस वक्त मैं अपने किरदार के बारें में कुछ नहीं बता सकती. मैं लंबे समय बाद हिन्दी फिल्म करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं. फिल्म एमएस धोनी– दि अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत सिंह राजपूत धोनी के किरदार में नजर आएंगे. यह फिल्म साल 2016 में रिलीज होगी. ■

एक्शन करेंगी सोनाक्षी

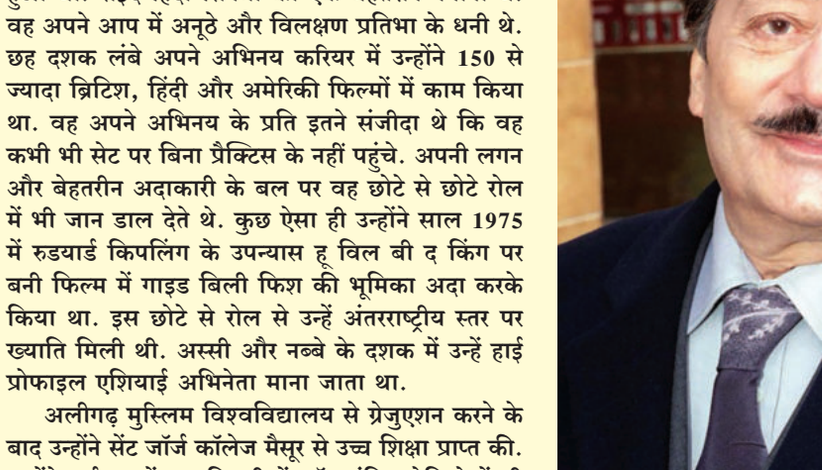

निर्देशक अभिनय देव का मानना है कि उनकी फिल्म फोर्स–2 में सोनाक्षी सिन्हा अपने एक्शन से हर किसी को अचंभित कर देंगी. अभिनय ने कहा, इस फिल्म में सोनाक्षी, जॉन अब्राहम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. उनके एक्शन सीन्स को देखकर लोग चौंक जाएंगे. हमने उनके साथ एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरूकर दी है. तकरीबन 50 प्रतिशत एक्शन सीक्वेंस फिल्माए जा चुके हैं. डेल्ही बेली के निर्देशक फिल्म फोर्स–2 में अब तक कुछ अनदेखे एक्शन दृश्यों को दिखाएंगे. उन्होंने कहा, फोर्स–2, में मैं ऐसा एक्शन सीन्स देने का प्रयास कर रहा हूं जो लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं. उम्मीद है कि मैं लोगों के सामने कुछ पेश कर सकूंगा. फिल्म की शानदार शूटिंग हो रही है, इस दौरान जॉन को चोट लग गई, ऐसे में हम लोगों ने कुछ समय के लिए शूटिंग रोक दी थी. फिल्म की 70 प्रतिशत शूटिंग हो गई है, केवल 30 प्रतिशत बाकी है. हमने फिल्म के प्रदर्शन की तारीख अभी तय नहीं की है. फिल्म में अभिनेता ताहिर राज भसीन, विद्युत जाम्मवाल के स्थान पर नजर आएंगे. विद्युत ने फिल्म फोर्स में नकारात्मक भूमिका अदा की थी.■

डेल्ही बेली के निर्देशक फिल्म फोर्स–2 में अब तक कुछ अनदेखे एक्शन दृश्यों को दिखाएंगे. उन्होंने कहा, फोर्स–2, में मैं ऐसा एक्शन सीन्स देने का प्रयास कर रहा हूं जो लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं.

प्रेम रतन धन पायो ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड

सौ करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली सलमान खान स्टारर यह 9वीं फिल्म है.

सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, फिल्म ने अपने ओपनिंग वीक में भारत में कुल 170 करोड़ रुपये की कमाई की है जबकि वर्ल्डवाइड कमाई का आंकड़ा 300 करोड़ के पार पहुंच गया है. सौ करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली सलमान खान स्टारर यह 9वीं फिल्म है. बंपर शुरूआत करने के बाद सलमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैंस को फिल्म की सफलता के लिए धन्यवाद दिया. सलमान ने भी प्रेम रतन धन पायो की कामयाबी पर खुशी जताते हुए कहा कि बॉक्स ऑफिस पर दूसरों के रिकॉर्ड तोड़ने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपने रिकॉर्ड तोड़ और अगर मैं यह सोचू कि मेरा बनाया रिकॉर्ड ना टूटे तो यह मेरे मतलबी होने जैसा हो जाएगा... रिकॉर्ड किसी का भी हो, उसे टूटना चाहिए. पारिवारिक भावनाओं और आपसी रिश्तों पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है, उनकी फिल्म मैंने प्यार किया से ही सलमान ने बतौर हीरो बॉलीवुड में कदम रखा था. सलमान खान और सोनम कपूर स्टारर इस फिल्म की कलेक्शन में आए दिन बढ़त देखने को मिल रही है. फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और 20 करोड़ रुपये फिल्म के प्रमोशन और विज्ञापन पर खर्च हुए हैं. भारत में यह फिल्म कुल 4,500 सिनेमाघरों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 1,100 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म में सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश, अनुपम खेर, स्वरा भास्कर और अरमान कोहली भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं. ■

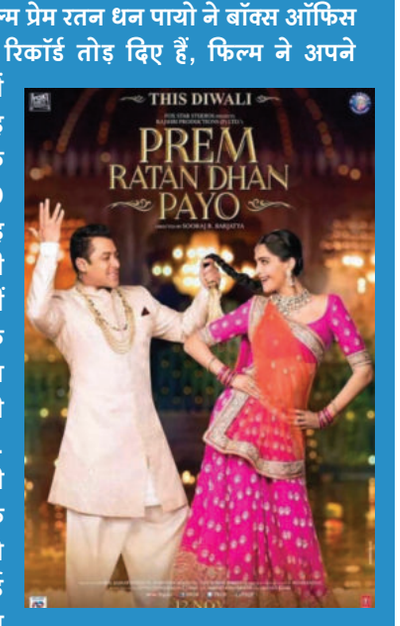

बिग बॉस के घर में कभी नहीं जाऊंगी नेहा धूपिया

कैमरों के इर्द–गिर्द रहना हमारे लिए आसान है, लेकिन हर समय आसपास कैमरे रहने से मुझे असहज महसूस होता है.

पूर्व मिस इंडिया और अभिनेत्री नेहा धूपिया को बिग–बॉस के घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने कहा, मैं बिग बॉस बहुत देखती हूं. मैं सलमान खान की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं. उन्हीं की वजह से मैं यह शो देखती हूं, लेकिन मैं बिग बॉस के घर में कभी नहीं जाऊंगी. नेहा ने यह भी कहा कि लोगों को लगता है कि हम हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, तो कैमरों के इर्द–गिर्द रहना हमारे लिए आसान है, लेकिन हर समय आसपास कैमरे रहने से मुझे असहज महसूस होता है. बिग–बॉस के होस्ट सलमान के बारे में नेहा ने कहा कि मुझे लगता है कि सलमान एक होस्ट के तौर पर कमाल के हैं. जिस तरह से वह प्रतिभागियों से बात करते हैं, वह उस स्थिति में बहुत अच्छे से समझाते हैं.■

मराठी फिल्मों में काम करना चाहते हैं इरफान

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवा चुके दिग्गज अभिनेता इरफान खान अब मराठी फिल्मों में भी काम करना चाहते हैं. उनका मानना है कि मराठी सिनेमा का प्रभाव बढ़ रहा है. इरफान ने दीपक कदम की फिल्म वाक्या के ट्रेलर लांच के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि मराठी फिल्मों ने इन दिनों अपना स्तर बढ़ा लिया है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने चैतन्य तम्हाने की फिल्म कोर्ट का जिक्र किया. इरफान कि अनुसार यह एक शानदार फिल्म है. पिछले साल आई फिल्म फैन्ड्री भी शानदार है. हर साल हैरान कर देने वाली नई प्रतिभाएं सामने आती हैं. यदि मुझे कोई अच्छा प्रस्ताव मिलता है तो मैं निश्चित रूप से मराठी फिल्म में काम करूंगा. फिल्म वाक्या के बारे में इरफान ने कहा कि वाक्या एक दिलचस्प फिल्म है.

फिल्म की कहानी भावनात्मक संकट पर आधारित है. भारतीय फिल्में अधिक से अधिक विषयोन्मुख हो रही हैं. 10 साल पहले चीजें अलग थीं. फिल्म वाक्या आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की जरूरत जैसे विषय पर आधारित है. फिल्म का निर्देशन दीपक कदम ने किया है उन्होंने ही फिल्म की पटकथा लिखी है.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार-झारखंड

30 नवंबर–06 दिसंबर, 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

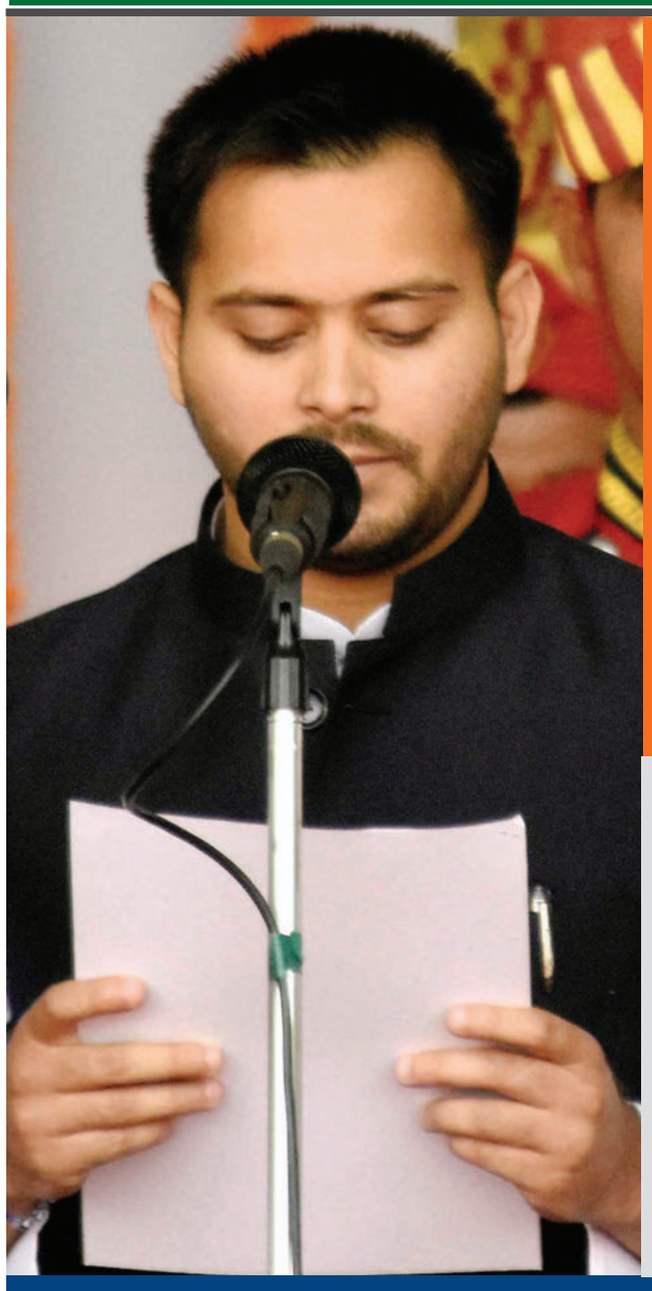

बेटा राज की अग्निपरीक्षा

बिहार में नई सरकार आ चुकी है. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों को राज्य के विकास में अहम भूमिका दी गई है. तेजस्वी और तेज प्रताप को सरकार के केंद्र में रखने के पीछे के कई निहितार्थ हैं जिनमें राजद की पूर्ववर्ती सरकार की छवि बदलना भी शामिल है. पढ़िए इस पर केंद्रित हमारी स्टोरी...

लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री बनाते हुए उन्हें सड़क, भवन और पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई तो बड़े बेटे तेजप्रताप को स्वास्थ्य, लघु जलसंसाधन व वन और पर्यावरण की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दी. कहा जा रहा है कि तेजस्वी और तेजप्रताप के कंधों पर अपने विभागों को बेहतर तरीके से चलाने की जिम्मेदारी है, जिससे वे उस दाग को धो सकें जो कभी लालू प्रसाद की सरकार पर लगा था.

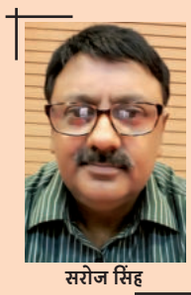

सरोज सिंह

बिहार में नई नीतीश सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया है. आम राय है कि सारे बड़े विभागों पर राजद के मंत्री काबिज हो गए हैं. खासकर तेजस्वी और तेजप्रताप को जिन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, उन पर पूरे बिहार की नजर है. ऐसा इसलिए भी है कि नीतीश कुमार ने विकास की गाड़ी को आगे ले जाने का जो खाका अपनी नई सरकार में खींचा है उसमें अहम भूमिका लालू प्रसाद के दोनों बेटों को निभानी है. साल भर बाद जब नीतीश कुमार अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे तब यह देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने जो भरोसा तेजस्वी और तेजप्रताप पर जताया था वह कितना सही था? दरअसल 2005 में जब नीतीश सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय जो तस्वीर दिखाई जाती थी वह यह थी कि बिहार में सड़क नहीं बल्कि केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं. भवनों का घोर अभाव है और स्कूल से लेकर अस्पताल तक जर्जर भवनों में चल रहे हैं. लालू राबड़ी सरकार पर यह भी तोहमत थी कि पढ़ाई–लिखाई चौपट हो गई है. लालू प्रसाद की इन नाकामियों को उस समय नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं ने जमकर चुनावी मुद्दा बनाया और जनता को यह भरोसा दिलाया कि उनकी नई सरकार विकास के ऐजेंडे को लागू करेगी.

नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में अपनी प्राथमिकता सूची में भवन, सड़क और अस्पताल को रखा और पहला टर्म खत्म होते होते लागों को यह लगने लगा कि नीतीश सरकार ने जो कहा वह होता हुआ दिख रहा है. लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से नीतीश अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी प्राथमिकताओं को उस तरह से अमलीजामा नहीं पहना पाए जैसा वह चाहते थे. अब समय का चक्र देखिये जिस सड़क, भवन और अस्पताल को लेकर लालू और राबड़ी के लंबे शासनकाल की आलोचना की जाती थी आज उसे ही दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने लालू के दोनों बेटों को थमा दी. लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री बनाते हुए उन्हें सड़क, भवन और पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई तो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप को स्वास्थ्य, लघु जलसंसाधन व वन और पर्यावरण की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने सौंपी है. इसलिए यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और तेजप्रताप के कंधों पर न केवल अपने विभागों को चलाने की जिम्मेदारी है बल्कि इस तरह चलाने की जिम्मेदारी है, जिससे वह उस दाग को धो सकें जो कभी लालू प्रसाद की सरकार पर लगा था. तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार का पहला एजेंडा ही विकास है इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह एहसास है. सड़क व भवन ऐसे विभाग हैं जिससे जनता का सीधा वास्ता होता है. मेरी पूरी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार ने जो काम हमें दिया है, उसे उनके सपनों के अनुरूप पूरा करेंगे. हम नए जरूर हैं पर काम करने का जज्बा हमारे अंदर कूट–कूट कर भरा है. बिहार की महान जनता ने हमलोगों पर जो भरोसा जताया है वह बेकार नहीं जाएगा.

तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार का पहला एजेंडा ही विकास है इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह एहसास है. सड़क व भवन ऐसे विभाग हैं जिससे जनता का सीधा वास्ता होता है. मेरी पूरी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार ने जो काम हमें दिया है, उसे उनके सपनों के अनुरूप पूरा करेंगे. हम नए जरूर हैं पर काम करने का जज्बा हमारे अंदर कूट–कूट कर भरा है. बिहार की महान जनता ने हमलोगों पर जो भरोसा जताया है वह बेकार नहीं जाएगा. दुनिया देखेगी कि सड़क और भवन के मामले में बिहार ने कितना अजूबा काम किया है.

दुनिया देखेगी कि सड़क और भवन के मामले में बिहार ने कितना अजूबा काम किया है. इसी तरह तेजप्रताप भी कहते हैं कि हमें हर चुनौती मंजूर है. हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है उन्हें निभाने के लिए जीतोड़ मेहनत करेंगे. लोगों ने हमलोगों को काम करने का जनादेश दिया है, इसलिए केवल मैं ही नहीं पूरी सरकार दिन रात काम करेगी और जनता के सपनों को पूरा करेगी. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तेजप्रताप और तेजस्वी यादव इस बात की पूरी कोशश करेंगे कि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि राजद को विकास से कोई मतलब नहीं है. या फिर कोई यह कहे कि राजद विकास के रास्ते का कांटा है. बल्कि इन दोनों भाइयों की कोशिश यह होगी कि राजद के प्रति इस अवधारणा को अपने कामों से बदल दिया जाए. साल भर के बाद जो रिपोर्ट कार्ड आए उसमें राजद के मंत्रियों का कामकाज सबसे बेहतर हो. एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और विकास का माहौल बने ताकि आगे कोई यह न कह सके कि राजद के रहते विकास संभव नहीं है. लालू प्रसाद भी यही चाहते हैं कि उनके बेटों की इमेज काम करने वाले मंत्री की बने. लालू के बेटे की छवि से अलग हटकर काम करने वाले युवा मंत्री की छवि के साथ बिहार की राजनीति में स्थापित होने का एक मंच लालू प्रसाद ने अपने बेटों के सामने सजा दिया है. जानकार बताते हैं कि लालू प्रसाद अपने दोनों बेटों के कामकाज पर गहन नजर रखेंगे और समय–समय पर उन्हें सही मागदर्शन भी देंगे. लालू प्रसाद की दिली इच्छा है कि उनके दोनों बेटों की पहचान जनता के हमदर्द और विकास करने वाले मंत्री के तौर पर बने. खासकर सड़क और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी अपने बेटों को दिलाने के पीछे लालू प्रसाद की यही भावना काम कर रही थी कि आम जनता का ज्यादा से ज्यादा भला उनके बेटे कर पाएं. किसी जमाने में जाने या अनजाने उन पर विकास न करने का जो दाग लगा था, उसे उनके दोनों बेटे अपने जबरदस्त काम से धो डालें. लालू जानते हैं कि उनके आलोचक तेजस्वी और तेजप्रताप के एक–एक फैसलों पर तीखी नजर रखेंगे और उस पल का इंतजार करेंगे की लालू के बेटे कहीं कोई गलती करें.

दरअसल लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को मंत्री बनाकर और उन्हें महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ा दांव लगाया है. लालू प्रसाद यह कभी नहीं चाहेंगे कि यह बाजी वह हार जाएं क्योंकि राजद का पूरा दारोमदार तेजस्वी और तेजप्रताप के बेहतर कामकाज पर टिका है. अगर ये दोनों भाई अपने अपने विभागों में बेहतर काम कर गए तो निश्चित तौर पर राजद की काम न करने की छवि पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी और एक नए राजद की तस्वीर बनेगी जिसके नेता केवल और केवल विकास और जनहित को प्राथमिकता देते हैं.

– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

एक नज़र

'खुले में शौच मुक्त' पंचायत बना गोगरी

सूबे बिहार का आठवां 'खुले में शौच मुक्त' ग्राम पंचायत गोगरी समुदाय के समुदाय द्वारा घोषित किया गया. नमामि गंगे परियोजना के तहत सूबे बिहार में गंगा किनारे बसे ग्राम पंचायतों को खुले शौच मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है. खगड़िया जिले के 21 ग्राम पंचायतों को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है. प्रयोग के तौर पर गोगरी प्रखंड के रामपुर ग्राम पंचायत में सीएलटीएस विद्या कम्युनिटी लेग टोटल सेनीटेशन समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता अभियान विधि का सफल प्रयोग किया था. गोगरी ग्राम पंचायत में जिला जल स्वच्छता समिति खगड़िया के द्वारा दो माह पूर्व इस अभियान की शुरुआत की है. समुदाय द्वारा जब खुले में शौच मुक्ति का स्तर प्राप्त कर लिया तब ग्राम पंचायत गोगरी के मुखिया वकील यादव के द्वारा समारोह आयोजित किया गया. जिसमें जिला पदाधिकारी साकेत कुमार, आरक्षी अधीक्षक अनील कुमार सिंह नमामी गंगे परियोजना के निर्देशक सउल्ला जावेद, युनिसेफ बिहार के निर्देशक परवीन मोरे, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति के राज्य समन्वयक संजय सिन्हा, जल एवं स्वच्छता समिति के विश्वनाथ झा, कार्यपालक अभियंता रामाकांत सिंह, निगरानी समिति के दीपक इपाध्याय, डीपीआरओ कमल सिंह, मुकेश कुमार, पुष्पांजलि देवी, प्रमोद पाठक के अलावा इस अवसर पर जिले के सभी पदाधिकारी, समाजसेवी, गण्यमान्य लोग सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे.

महागठबंधन को जीत की बधाई

विगत विधानसभा चुनाव मे बिहार प्रदेश में महागठबंधन की शानदार जीत के लिए खगड़िया जिला के आम नागरिकों, बुद्धिजीवियों ने स्वागत किया तथा उन्होंने कहा कि यह समाजिक न्याय की जीत है. जिले के चारों विधानसभा से महागठबंधन के इम्मीदवारों की जीत हुई है. विकास पुरुष नीतीश कुमार पुन: मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करेगें. बैठक कर स्थानीय नेताओं व आम जनता द्वारा महागठबंधन के नेताओं को नेता लालू प्रसाद यादव एवं नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा गया कि वे अब अच्छे ठंग से बिहार को चलाएं एवं विकास की रफ्तार को तेज करें. ताकि बिहार की अन्य राज्यों से विकास की रफ्तार में आगे बढ़े. *– गीता कुमार*

मीसा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग

बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 64 यादव जाति के विधायक हैं. इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री यादव जाति के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉ. मीसा भारती को बनाना चाहिए. यह बातें सत्यनारायण यादव मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट कैंपस मदारपुर महेशखूंट में यादव महासभा के जिला अध्यक्ष डा. अखिलेश कुमार विद्यार्थी ने कही. उन्होंने यह भी कहा कि मीसा भारती को सीएम बनाया जाता तो यादव जाति का सम्मान और बढ़ेगा. वहीं महिलाओं को सुरक्षा व सम्मान भी अधिक मिलेगा. यदुवंशियो ने राजद को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाया. उनकी उम्मीद तभी पूरी होगी. जब मीसा भारती मुख्यमंत्री बनाया जायेगा. इस मौके पर जिला सचिव अमर कुमार यादव ने कहा कि 30 प्रतिशत विधायक यादव जाति के हैं. इसलिए मुख्यमंत्री पद पर पहला हक उनका बनता है.■ *– गीता कुमार*

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

बिना शराब के भी ...
हो सकता है लिवर खराब
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
Dr. V.C. Thakur
URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL-D Cap
Omeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

मांझी, पासवान और कुशवाहा हुए फेल

मगध में एनडीए के घटक दल रालोसपा, हम और लोजपा अपनी मजबूत स्थिति का दावा कर रहे थे. कारण भी था. पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी का जन्म-कर्म क्षेत्र मगध ही रहा, वहीं रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार का संसदीय क्षेत्र भी मगध में ही है. लोजपा का जातीय वोट बैंक पासवान जाति भी मगध के कई विधानसभा क्षेत्रों मे निर्णायक भूमिका में है, किंतु दावों के विपरीत इन जातियों का वोट एनडीए में मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर नहीं हो पाया.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

मांझी, कुशवाहा और पासवान जाति के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने की एनडीए की कोशिश मगध में नाकामयाब हो गया. जातीय वोट बैंक का लाभ नहीं मिल पाने से एनडीए को 14 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा. यदि दावों के अनुसार इन जातियों का वोट एनडीए को मिल जाता, तो दृश्य बदला हुआ नजर आता, किंतु ऐसा हो नहीं पाया. जाति पर अपनी 'हुकूमत' का दावा करने वाले एनडीए के तीन घटक दलों के सर्वेसर्वा यथा जीतनराम मांझी, उपेन्द्र कुशवाहा एवं राम विलास पासवान को मगध में मुंह की खानी पड़ी.

> जहां कुशवाहा जाति का वोट महागठबंधन से खड़े अभय कुशवाहा (टिकारी) एवं कृष्णनंदन वर्मा (घोसी) को मिला, तभी इनकी जीत भी हुई. यही हाल लोजपा सुप्रीमो के दावों का भी रहा. लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान लाख दावा करें कि मेरी जाति के वोट पर मेरा कब्जा है, लेकिन मगध में इनका दावा फेल हो गया. बोधगया सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए से भाजपा के श्यामदेव पासवान एवं महागठबंधन से राजद के कुमार सर्वजीत चुनाव मैदान में थे. दोनों की समान बिरादरी थी, लेकिन यहां पासवान जाति का वोट एनडीए को पूरी तरह से नहीं मिल पाया और बाजी महागठबंधन ने मारी.

मगध में एनडीए के घटक दल रालोसपा, हम और लोजपा अपनी मजबूत स्थिति का दावा कर रहे थे. कारण भी था. पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी का जन्म-कर्म क्षेत्र मगध ही रहा, वहीं रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार का संसदीय क्षेत्र भी मगध में ही है. लोजपा का जातीय वोट बैंक पासवान जाति भी मगध के कई विधानसभा क्षेत्रों मे निर्णायक भूमिका में है, किंतु दावों के विपरीत इन जातियों का वोट एनडीए में मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर नहीं हो पाया.

भले ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज से जीत गये, लेकिन अन्य विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जाति का वोट एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से ट्रांसफर करा पाने में असफल हुए. यदि ऐसा होता तो मांझी खुद मखदुमपुर से नहीं हारते! रालोसपा के उपेन्द्र कुशवाहा भी मगध में अपनी जाति के वोट बैंक को एनडीए के पक्ष में टर्न-अप नहीं करा पाये. उदाहरणस्वरूप, टिकारी एवं घोसी विधानसभा क्षेत्र को लिया जा सकता है. जहां कुशवाहा जाति का वोट महागठबंधन से खड़े अभय कुशवाहा (टिकारी) एवं कृष्णनंदन वर्मा (घोसी) को मिला, तभी इनकी जीत भी हुई. यही हाल लोजपा सुप्रीमो के दावों का भी रहा. लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान लाख दावा करें कि मेरी जाति के वोट पर मेरा कब्जा है, लेकिन मगध में इनका दावा फेल हो गया.

बोधगया सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए से भाजपा के श्यामदेव पासवान एवं महागठबंधन से राजद के कुमार सर्वजीत चुनाव मैदान में थे. दोनों की समान बिरादरी थी, लेकिन यहां पासवान जाति का वोट एनडीए को पूरी तरह से नहीं मिल पाया और बाजी महागठबंधन ने मारी. एनडीए के घटक दलों के इन नेताओं का अपनी जातीय वोट बैंक पर पकड़ रहता, और एनडीए के पक्ष में वोट ट्रांसफर कराने में सफल हो जाते, तो मगध के कम से कम 14 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों, जहां से महागठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, वहां का परिणाम कुछ दूसरा होता. ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, रजौली, नवादा, गोविन्दपुर, घोषी, मखदुमपुर, अरवल कुर्था, बोधगया, टिकारी, अतरी, बाराचट्टी, वजीरगंज, ओबरा और कुटुम्बा. विधानसभा चुनाव में जीतनराम मांझी, उपेन्द्र कुशवाहा और रामविलास पासवान अपनी अधिकतर चुनावी सभा भी वैसे ही स्थानों पर ही की, जहां इनका जातीय वोट बैंक कुछ मजबूत स्थिति में था. परिणाम ने तीनों नेताओं की बोलती बंद कर दी. मगध में इन नेताओं के फेल होने का अब जो भी कारण निकाला जाये, लेकिन इतना तय हो गया कि कोई भी नेता स्वजाति वोट बैक पर पूरी तरह अपना दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतदाता ही तो है, न जाने कौन सी बात मतदाता को लग जाये और अपने मत से नेताओं के दावे को पलट दें. मगध में कुछ ऐसा ही हुआ! मगध के मतदाताओं ने एनडीए के घटक दलों के तीनों नेताओं को नकार दिया, जिनसे एनडीए को उम्मीद थी.■

पृष्ठ 17 का शेष

बेटा राज की अग्निपरीक्षा

राजद की यह छवि तेजप्रताप और तेजस्वी यादव को ही अब बनानी है. राजद के सामने 2019 का लोकसभा का चुनाव है. तेजप्रताप और तेजस्वी यादव के दिमाग में उसका भी खाका है. लालू प्रसाद ऐलान कर चुके हैं कि अब वह दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे. अब लालू के दिल्ली के रास्ते को सुगम बनाने का काम उनके दोनों बेटों को ही करना है. बिहार में जितनी सड़कें बनेंगी लालू प्रसाद के लिए दिल्ली का रास्ता उतना ही आसान होगा. बिहार की जनता का स्वास्थ्य जितना दुरुस्त होगा उतना ही दिल्ली की लड़ाई के लिए राजद का स्वास्थ्य मजबूत होगा.

लालू प्रसाद तभी दोगुनी ताकत से दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला कर पाएंगे. इसलिए तेजस्वी यादव और तेजप्रताप के सामने एक अवसर है अपने आप को साबित करने का. लालू प्रसाद ने तो पटना से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में अपने आप को साबित कर दिया. अब बारी इनके बेटों की है. अच्छी बात यह है कि उनके दोनों बेटे भी इस समय उत्साह से लबालब हैं और कुछ कर गुजरने के लिए अपने आप को दिन रात झोंकने के लिए तैयार है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस कठिन काम को वह किस तरह से कितना कर पाते हैं. अगर कर गए तो बिहार में उनकी एक अलग पहचान स्थापित होगी और अगर न कर पाए तो फिर राजद के साथ ही साथ लालू प्रसाद के सपनों को भी करारा झटका लगेगा. तेजस्वी और तेजप्रताप कहते हैं कि बिहार की महान जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है हम कामयाव होंगे, ऐसा हमारा भरोसा है.■

feedback@chauthiduniya.com

कहा जाता है कि यहां के मरचा धान का चूड़ा, बासमती का चावल, आनंदी धान का भूजा जिसने भी एक बार चख लिया, जीवन भर उसका स्वाद याद रहता है. इसे संयोग कहे अथवा कुछ और कि यहां उगने वाली धान की किस्मों की खूबी शनै-शनै इसकी सुगंध देश में कौन कहे विदेश तक पहुंच चुकी है. कहा जाता है कि यहां की बेटियों का ब्याह जब भी बाहर होता है तो उनके साथ मायके वाले चावल या उससे बना सामान जरूर देते है. ताकि यहां के प्रसिद्ध धान से निकले चावल का स्वाद लोग ले सकें. कहा जाता है कि यहां से उपजे बासमती चावल, मरचा का चिउड़ा, आनंदी धान का भूजा का स्वाद अगर एक बार किसी ने ले लिया तो जीवन पर्यन्त लोग नहीं भूलते है. यहां तक की अगर यहां की बेटी देश अथवा विदेश के किसी कोने में जाकर बस जाती है. उसके घरवाले फरमाईश कर चावल या चावल से बने सामान को मंगवाना नहीं भूलते हैं.

परंपरागत धान पर भारी संकर धान

संजय कुमार सिंह
feedback@chauthiduniya.com

धान के कटोरे के रूप में ख्याति प्राप्त है पश्चिम चंपारण का दोन क्षेत्र कभी अपने हजारों परंपरागत धान की किस्मों की बदौलत काफी खुशहाल रहा यह क्षेत्र आज अपने दामन में उगने वाली इन किस्मों के अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में लगा है. अपने इसी धान की किस्मों पर नाज करने वाले यहां के किसान खेती की बढ़ती लागत, बेहतर संवर्धन-संरक्षण की कमी के अभाव में बदहाली के कगार पर हैं. बेहतर व सही बाजार के अभाव ने किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा है. हालात यह है कि गर किसानों को बेहतर उपज होती भी है तो उनको इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती है. बाजार की बेहतर व्यवस्था नहीं होने तथा उचित उपज मूल्य नहीं मिलने से अब धान की इन परंपरागत किस्मों के अस्तित्व को ही समाप्त करना शुरू कर दिया है. कोढ़ पर खाज की तरह धान की संकर किस्मों ने पूरी कर दी है. बेहतर उपज देने वाली इन धान की संकर नस्ल की किस्मों से होने वाली प्रतिस्पर्धा ने परंपरागत धान की खेती करने वाली किसानों के मनोबल को तोड़ कर रख दिया है. क्योंकि परंपरागत किस्में स्वाद समेत अन्य सभी तुलनाओं में बेहतर होने के बावजूद केवल उपज में पिछड़ जाती हैं. जिसके कारण इसकी खेती फायदेमंद नहीं रह गयी है. अगर जल्दी ही इसके संवर्धन व संरक्षण के लिये सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर प्रयास नहीं किया गया तो इन परंपरागत किस्मों का वजूद ही इतिहास की बात हो जायेगी.

विलुप्त होने की कगार पर पहुंची परंपरागत किस्में

दोन क्षेत्र में पहले स्थानीय किस्मों में आनंदी, मरचा, मधुमालत, बासमती, सनखरिका जैसी धान की तकरीबन सैकड़ों किस्मों की खेती होती थी. लेकिन आज इन किस्मों की खेती में भारी कमी आयी है. जिसके कारण कभी दिलों पर राज करने वाली परम्परागत किस्में विलुप्ति के कगार पर पहुंच गयी हैं. हिमालय पहाड़ की सबसे निचली पर्वत श्रृंखला सोमेश्वर रेंज की तलहटी में बसे दोन क्षेत्र को धान का मायका या धान का कटोरा कहा जाता है. बरसात में पहाड़ों से आने वाली उपजाऊ मिट्टी से बने इन मैदानी इलाकों में सदियों से यहां रहने वाले थारू समुदाय के लोग धान की खेती करते रहे हैं. इसे मिट्टी की तासीर समझें या पहाड़ व जंगल की सड़ी पत्तियों के बह कर आने के कारण बिना किसी रासायनिक उर्वरक के ही इन मैदानी खेतों में सोना के रूप में कई परंपरागत किस्में अपनी खूबियों के साथ सदियों से उपजती रही हैं. कालांतर से इन ऑरगेनिक किस्मों पर किसी प्रकार का अनुसंधान व विकास नहीं होने का प्रभाव ऐसा पड़ा कि कम उपज वाली इन किस्मों की खेती बेहतर मार्केटिंग के अभाव में अलाभकारी होती चली गई. दोहरी मार तो तब पड़ी जब अधिक उपज वाली संकरी किस्मों का बाजार अधिक उपज के दम पर बढ़ने लगा. जिसके बाद बढ़ती लागत व घटते मुनाफे के कारण चाह के बावजूद किसान संकर किस्मों की खेती की तरफ उन्मुख होते चले जा रहे हैं. जिसके कारण परंपरागत किस्मों के वजूद पर संकट खड़ा होता चला गया. आलम यह है कि आज तो यहां उपजने वाली कई किस्मों का वजूद ही समाप्त हो गया है. बाकी बची परंपरागत किस्मों पर भी विलोपन का खतरा मंडराने लगा है. अगर जल्दी ही इसके संरक्षण व बेहतरी के लिये पहल नहीं की गयी तो दोन क्षेत्र में उपजने वाली परंपरागत धान की सैकड़ों विविधता वाली किस्में समाप्त हो जायेंगी.

संरक्षण को लेकर नहीं शुरू हो सकी है सार्थक पहल

दोन क्षेत्र में उपजने वाली इन विलुप्त होती प्रजाति के धान के संरक्षण व संवर्धन के लिये अभी तक कोई ठोस व कारगर पहल शुरू नहीं हो पायी है. यहां उपजने वाली परंपरागत किस्मों की उपज क्षमता काफी कम है. साथ में इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कम रहती है. जबकि संकर नस्ल में बेहतर उपज व रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी होती है. हालांकि स्वाद व गुणवत्ता में संकर किस्में परंपरागत किस्मों से बेहतर नहीं होती हैं. लेकिन बेहतर बाजार व्यवस्था के अभाव के कारण बिचौलिये इन परंपरागत किस्म का बेहतर मूल्य किसानों को नहीं देते हैं. हालात यह है कि बढ़िया परिवहन व्यवस्था के अभाव, सरकारी खरीद की लालफीताशाही के कारण बिचौलियों के दर पर अपनी उपज बेचना पड़ता है. इसके संरक्षण व संवर्धन के लिये बिहार के एक मात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से भी संभवतः सार्थक सफल पहल नहीं हो पाया है. अगर इन शोध व विकास पर ध्यान दिया जाता तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता व उपज बढ़ सकती थी. जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल पाता. हालात इतने

बदतर हैं कि गैर सरकारी स्तर पर भी यहां के बीज को बचाने के उपाय नाकापी साबित हो रहे है. आशा की कीरण बस एक ही नजर आती है कि छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन स्थानीय कुछ किसान संरक्षण की महत्ता को समझ मामूली क्षेत्रफल में इन बीजों को हर साल लगा रहे हैं. जिसके कारण बची धान की किस्मों का वजूद अभी तक बचा है. लेकिन जल्दी ही सरकारी स्तर पर कोई बड़ी पहल नहीं हुई तो यह सिलसिला लंबा नहीं चल पायेगा.

यहां की धान की कई किस्में है प्रसिद्ध

कहा जाता है कि यहां के मरचा धान के चूड़ा, बासमती का चावल, आनंदी धान का भूजा जिसने भी एक बार चख लिया, जीवन भर उसका स्वाद याद रहता है. इसे संयोग कहे अथवा कुछ और कि यहां उगने वाली धान की किस्मों की खूबी शनै-शनै इसकी सुगंध देश में कौन कहे विदेश तक पहुंच चुकी है. कहा जाता है कि यहां की बेटियों का ब्याह जब भी बाहर होता है तो उनके साथ मायके वाले चावल या उससे बना सामान जरूर देते है. ताकि यहां के प्रसिद्ध धान से निकले चावल का स्वाद लोग ले सकें. कहा जाता है कि यहां से उपजे बासमती चावल, मरचा का चिउड़ा, आनंदी धान का भूजा का स्वाद अगर एक बार किसी ने ले लिया तो जीवन पर्यन्त लोग नहीं भूलते है. यहां तक की अगर यहां की बेटी देश अथवा विदेश के किसी कोने में जाकर बस जाती है. उसके घरवाले फरमाईश कर चावल या चावल से बने सामान को मंगवाना नहीं भूलते हैं.

बेहतर बाजार के अभाव ने तोड़ी किसानों की कमर

देहरादूनी बासमती समेत देश में उपजायी जाने वाली कई धान की किस्मों को सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों की बदौलत आज बेहतर बाजार मिला हुआ है. साथ ही देश के कई कृषि विश्वविद्यालयों ने वहां की किस्मों पर शोध कर से बेहतर बनाने में मदद की है. जिसका सीधा लाभ वहां के किसानों को मिला है. लेकिन दोन में उपजने वाली परंपरागत किस्में उपेक्षित रह गयी. यहां उपजने वाली धान की किस्मों पर आज तक किसी प्रकार का शोध नहीं हो पाया. ताकि इनका संवर्धन व विकास हो सके. साथ ही इन किस्मों की बेहतर मार्केटिंग के लिये सरकारी समेत गैर सरकारी किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया. जिसके कारण बेहतर बाजार के अभाव ने किसानों की कमर तोड़ दी. ऐसे हालात में यहां के धान उत्पादक फसल आने के बाद इसे औने-पौने दाम पर बेचने को विवश होते रहते हैं. जिसके कारण उन्हें उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है.

खूबियों से सरोबार है यहां का धान

दोन क्षेत्र में उपजने वाली कई सारी किस्में ऐसी खूबियों से लैश हैं जो अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती है. बताया जाता है कि दोन में उपजने वाली बासमती इतना महीन व साईज में इतना छोटा होता है कि वह नाखून में समा जाता है. लेकिन पकाने के बाद इसका साईज चावल के समान्य दाने से बड़ा हो जाता है. साथ ही इससे निकलने वाली खूश्बू काफी अधिक होती है. स्थानीय लोगों की माने तो वर्षों तक यहां के बासमती चावल को रखने के बाद भी उसकी खुश्बू खत्म नहीं होती. यहां के मरचा धान से बने चिउड़ा के दीवाने स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी हैं. इस क्षेत्र में घर आने वाले मेहमान को यह चिउड़ा जरूर परोसा जाता है. बताया जाता है कि इससे बनने वाला चूड़ा काफी लजीज होता है. साथ ही इससे भी एक प्रकार की भीनी-भीनी खुश्बू निकलती है. इस क्षेत्र में उपजे आनंदी धान से निकले चावल का भूंजा काफी लजीज होता है. जिसे लोग काफी पसंद करते है.

मिट्टी की तासीर के कारण उगती है बेहतर फसल

इसे दोन क्षेत्र की जमीन की तासीर कहे या यहां उपजने वाली धान की किस्मों की खूबी अथवा प्रकृति का वरदान समझें कि यहां के अलावा बाहर कहीं भी इन किस्मों को उगाया जाता है तो उगने वाले धान के दाने मोटे होने लगते हैं. साथ ही उनसे निकलने वाली खूश्बू में कमी आने लगती है. चाहे वह बीज दोन क्षेत्र से लिया गया हो. स्थानीय लोग इस खूबी का श्रेय सोमेश्वर से बरसात के दिन में पानी के साथ आने वाली कीचड़ युक्त मिट्टी जिसे गाद कहते हैं, उसको देते हैं.

किसानों की खुशहाली के लिये करने होंगे बेहतर उपाय

किसानों के खुशहाली भरे दिन को फिर से वापस लाने के लिये जरूरत है तो इन किस्मों के संवर्धन व संरक्षण की. ताकि इनका वजूद बचाया जा सके. इसके लिये बेहतर बाजार सुविधा उपलब्ध करा कर किसानों को उचित मूल्य दिलाया जा सकता है. बाजारवाद के इस दौर में इसके लिये बेहतर मार्केटिंग रणनीति अपना कर भी इसे बाजार के पटल पर स्थापित कर इस धरोहर को बचाये जाने की आवश्यकता है. साथ ही इन किस्मों पर अनुसंधान कर भी इसको बेहतर बनाने का सफल प्रयास की भी जरूरत है. ताकि किसानों को इसका लाभकारी मूल्य मिल सके और किसान इसकी खेती से विमुख नहीं हो. अभी तो हालात यह है कि दोन क्षेत्र को जिला व प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिये एक अदद सड़क मयस्सर नहीं है. जिसके कारण किसान अपनी उपज को बाहर नहीं भेज पाते हैं. जिसका लाभ बिचौलिये उठाते हैं.यहां से निकले चावल का मूल्य जिला मुख्यालय तक आते-आते दोगुणा से उपर हो जाता है. वह भी मिलावट के साथ.■

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बतायें।
भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन
उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये
3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।
प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव
उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव,
सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आयुर्वेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।
प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा
साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।
चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505
Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com
डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गा:9343834519

पूर्वी चम्पारण में नोटा का जमकर प्रयोग

नरकटिया में नोटा को मिला 5.45 फीसद मत

विधानसभावार नोटा के प्रयोग और अन्य पार्टियों की स्थिति की समीक्षा की जाए तो गोविन्दगंज विधानसभा क्षेत्र से आठ प्रत्याशी खड़े थे. उनमें दो निर्दलीय के अलावा कांग्रेस, बसपा, लोजपा, शिवसेना, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और आरक्षण विरोधी पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे. इनमें केवल लोजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को ही नोटा से ज्यादा मत मिले. यहां नोटा बटन को 3441 लोगों ने दबाकर प्रत्याशियों को नकार दिया. इसी तरह रक्सौल विधान सभा क्षेत्र से कुल 10 प्रत्याशी थे. उनमें भाजपा, बसपा, राजद, सपा, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी और गरीब जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ दो निर्दलीय खड़े थे. यहां भी जमकर नोटा का इस्तेमाल हुआ.

राकेश कुमार

बिहार विधान सभा चुनाव में नोटा यानी 'इनमें से कोई नहीं' का पूर्वी चम्पारण के मतदाताओं ने जमकर प्रयोग किया. पूर्वी चम्पारण की बारह विधान सभा सीटों के मतदान में कुल 41,969 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया. कई विस क्षेत्रों में तो नोटा ने कई क्षेत्रीय पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया. कई विधान सभा क्षेत्रों में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, पप्पू यादव के जनतांत्रिक मोर्चा, जीतनराम मांझी की हम सेकुलर, साधु यादव की गरीब विकास पार्टी सहित वामपंथी पार्टियों को नोटा ने मात दे दी. गोविन्दगंज और हरसिद्धि में नोटा तीसरे स्थान पर रहा जबकि अन्य जगहों पर नोटा को चौथा और पांचवां स्थान प्राप्त हुआ.

वहीं पूरे सूबे के 243 विधान सभा क्षेत्रों में नोटा पर 9,47,185 वोट पड़े, जो कुल मतदान का 2.5 फिसदी है. जबकि कुल 6.68 करोड़ मतदाताओं ने अर्थात सूबे के 56.80 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया. ज्ञात हो कि 2013 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद नोटा के विकल्प को चुनाव में जोड़ा गया. पहली बार लोक सभा चुनाव में नोटा का प्रयोग हुआ. विगत लोक सभा चुनाव में 60 लाख मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था. बिहार विधान सभा चुनाव में पहली बार 2015 में नोटा का प्रयोग किया गया. लोकतंत्र में आस्था रखने वाले ऐसे मतदाता जो चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार को योग्य नहीं मानते थे. वे मतदान के प्रति उदासीन हो जाते थे और वोट प्रतिशत कम रहता था. ऐसे मतदाताओं के विचार को मत में परिवर्तित करने के लिए नोटा का विकल्प दिया गया है. बिहार विधान सभा में मतदाताओं ने नोटा का जमकर प्रयोग किया. नोटा की जानकारी जन–जन तक पहुचाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जमकर प्रचार प्रसार किया गया. इन सभी प्रयासों के बावजूद कई जगहों पर मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार किया. यह भी चिन्ता का विषय है कि योग्य उम्मीदवार के चुनाव मैदान में नहीं होने पर किसी को मत नहीं देकर नोटा के विकल्प के बाद भी क्यों चुनाव वहिष्कार करने की जरूरत पडी. हॉलाकि चुनाव वहिष्कार को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है. कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के महारानी भोपत पंचायत के ग्रामीणों ने बूथ संख्या 75 और 77 पर चुनाव का बहिष्कार किया. इसके पीछे के कारणों को देखा जाय तो स्पष्ट है कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों के व्यवहार से क्षुब्ध और विभागीय उदासीनता से परेशान ग्रामीणों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही विश्वास उठता जा रहा है. ग्रामीण वर्षों से बिजली की मांग कर रहे थे. इस बाबत ग्रामीण बिजली विभाग, डीएम सहित चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलन्द कर चुके थे. लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया. चतुर्थ चरण में 30 अक्टूबर को महारानी बैरिया के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार कर दिया तो शासन प्रशासन की नींद टूटी. वरीय पदाधिकारी पहुंचे. मान मनव्वल हुआ पर ग्रामीण नहीं माने. इस बाबत ग्रामीणों का कहना है कि विधायक, सांसद सरकार से बतौर वेतन या मानदेय मोटी रकम लेते हैं. जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कार्य को पूरा नहीं करता तो इसके लिए दण्ड का प्रावधान होता है. विभागीय कार्यवाही के बाद उसकी नौकरी भी जा सकती है. जबकि ये नेता केवल वायदे करके लोगों को भ्रमजाल में फंसाकर वोट लेकर चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद सभी वायदे भूल जाते हैं. ग्रामीण न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल करने जा रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधि अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं करते हैं तो उनपर भी कार्रवाई हो और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पदच्युत किया जाये. जब तक ऐसा प्रावधान नहीं लाया जाता तबतक जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे. एक बार झूठे वायदों पर चुनाव जीतकर पांच वर्षों तक अपने को कुर्सी पर सुरक्षित समझ बैठे रहते हैं और मतदाता के अधिकार में कुछ नहीं होता. ऐसे विचार मतदाताओं के मन में घर कर जाने के कारण ही उन्होंने नोटा का भी प्रयोग नहीं किया.

बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार 2015 में नोटा का प्रयोग किया गया. लोकतंत्र में आस्था रखने वाले ऐसे मतदाता जो चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार को योग्य नहीं मानते थे, वे मतदान के प्रति उदासीन हो जाते थे और वोट प्रतिशत कम रहता था. ऐसे मतदाताओं के विचार को मत में परिवर्तित करने के लिए नोटा का विकल्प दिया गया है. बिहार विधानसभा में मतदाताओं ने नोटा का जम कर प्रयोग किया. नोटा की जानकारी जन–जन तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जमकर प्रचार–प्रसार किया गया. इन सभी प्रयासों के बावजूद कई जगहों पर मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार किया. यह भी चिन्ता का विषय है कि योग्य उम्मीदवार के चुनाव मैदान में न होने पर नोटा का विकल्प मौजूद होने के बावजूद भी चुनाव बहिष्कार की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी?

विधानसभावार नोटा के प्रयोग और अन्य पार्टियों की स्थिति की समीक्षा करें. गोविन्दगंज विधान सभा क्षेत्र से आठ प्रत्याशी खड़े थे. इनमें दो निर्दलीय के अलावा कांग्रेस, बसपा, लोजपा, शिवसेना, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और आरक्षण विरोधी पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे. इनमें केवल लोजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को ही नोटा से ज्यादा मत मिले. यहां नोटा बटन को 3441 लोगों ने दबाकर प्रत्याशियों को नकार दिया. इसी तरह रक्सौल विधान सभा क्षेत्र से कुल 10 प्रत्याशी थे. इनमें भाजपा, बसपा, राजद, सपा, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी और गरीब जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ दो निर्दलीय खड़े थे. यहां नोटा के पक्ष में 3310 मत मिले जो बसपा, सपा, भालोराप और गजप सेकुलर से भी ज्यादा था. केवल भाजपा, राजद और एक निर्दलीय प्रत्याशी को ही नोटा से ज्यादा मत मिला. सुगौली विधान सभा की स्थिति भी ऐसी ही रही. सुगौली में 2521 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया. यहां भी दस प्रत्याशियों का मत नोटा से कम था. सुगौली में राजद, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी सहित आठ निर्दलीय प्रत्याशी खड़े थे. केसरिया विधान सभा में नोटा पांचवें स्थान पर रहा. भाजपा, राजद, सीपीआई और निर्दलीय नीता शर्मा को छोड़ सभी प्रत्याशियों से ज्यादा मत नोटा को मिला. यहां नोटा का प्रयोग 2479 लोगों ने किया. हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्र में नोटा को 3131 मत मिले. यहां नोटा तीसरे स्थान पर रहा. नोटा ने सीपीआई, बीएसपी, साकोपा, नेशनल पैंथर पार्टी, गरीब जनता दल सहित निर्दलीय प्रत्याशियों को पछाड़ा. कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र में नोटा को 4260 मत मिले. यहां खड़े दस उम्मीदवारों में से नोटा ने छह उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया. पीपरा में 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. यहां नोटा को सबसे कम 1454 मत मिले. वहीं मधुबन विधान सभा क्षेत्र से चुनाव में खड़े बारह उम्मीदवारों में से नोटा 4666 मत लेकर आठ को पछाड़ दिया, यहां मात्र चार प्रत्याशी नोटा से ज्यादा मत प्राप्त कर सके. मोतिहारी में नोटा को 2589 मत मिले. यहां नोटा ने सीपीआई, सीपीएम, जन अधिकार पार्टी, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी सहित नौ को पछाड़ा. चिरैया विधान सभा में बारह प्रत्याशी खड़े थे. नोटा को यहां कुल 2418 मत मिले. यहां नोटा जन अधिकार पार्टी, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी, गरीब विकास पार्टी प्रत्याशी सहित आठ उम्मीदवारों से आगे रहा. जिले में नोटा को सबसे ज्यादा मत नरकटिया विधान सभा क्षेत्र में प्राप्त हुआ. यहां 8934 मतदाताओं ने नोटा को अपना मत दिया. नरकटिया में राजद, रालोसपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी को छोड़ सभी उम्मीदवारों से नोटा को ज्यादा मत मिला. नरकटिया में कुल मतदान 1,62,495 हुआ जिसका 5.45 प्रतिशत मत नोटा को मिला.

महारानी भोपत पंचायत के ग्रामीणों द्वारा पीएलआई दाखिल करने की तैयारी के मुद्दे के बाद राजनीतिक गलियारों में भी इसपर विचार विमर्श होने लगा है कि जनप्रितिनिधियों पर ऐसा अंकुश लगाया जाना आवश्यक है या नहीं.■

feedback@chauthiduniya.com

अब भी ग्रामोफोन है पूर्व पार्षद के परिवार का चहेता

सीतामढ़ी भले ही वर्तमान परिवेश में आधुनिक उपकरणों की चाह ने लोगों की जीवनशैली की दिशा बदल दी है, परंतु इस सच्चाई से कोई पलट नहीं सकता कि पुराने जमाने के उपकरण अब भी लोगों के लिए अमूल्य धरोहर बने हुए हैं. सीतामढ़ी का एक परिवार आज भी आधुनिकता के दौर से खुद को किनारे कर सैकड़ों साल पुराने यंत्रों को ही अपने मनोरंजन का साधन के रूप में उपयोग कर रहा है. यह अलग बात है कि अब इन यंत्रों का पार्टस–पुर्जा भी मिलना मुहाल हो गया है. परिवार के मुखिया डॉ आनंद प्रकाश वर्मा का कहना है कि अगर जिले में एक म्युजियम का निर्माण हो जाये तो इन ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज कर रखा जा सकता है...

जिले में अब तक एक म्युजियम की स्थापना नहीं करायी जा सकी है. अगर सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर म्युजियम का निर्माण करा दिया जाये तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ी के लिए सहेज कर रखा जा सकता है. उनका मानना है कि जिले में कई और भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऐसी वस्तुएं होंगी जो म्युजियम के लिए आकर्षण बन सकती हैं.

वाल्मीकि कुमार

आधुनिकता के दौर में जहां एक ओर सभी देशी से लेकर विदेशी सामानों से अपने घर को भरने में लगे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग है. जिनकी पसंद आज भी सैकड़ों साल पुरानी दुर्लभ वस्तुएं हैं. इस तथ्य का जीवंत उदाहरण सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित गीता भवन के समीप पूर्व विधान पार्षद स्व. सावलिया बिहारी लाल वर्मा का आवास है. तकरीबन 85 साल पूर्व स्व. सावलिया ने मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन खरीद कर अपने घर में लाया था. वर्ष 1930 से उक्त यंत्र उनके परिवार के लिए एक दुर्लभ धरोहर के रूप में मौजूद है. आश्चर्य यह कि आज भी अगर कोई चाहे तो उक्त यंत्र का आनंद किसी भी पल उठा सकता है. पुराने जमाने के फिल्मी गीतों का आनंद अब भी उनके पुत्र डॉ आनंद प्रकाश वर्मा सपरिवार ले रहे हैं. बदले जमाना का तकाजा है कि अब उक्त यंत्र का बड़ा सा लगने वाला सीडी सरीखा कैसेट भी बाजार में नहीं मिलता. कारण कि विज्ञान के नये आविष्कारों ने इसे अतीत की कहानी बना दिया है. डॉ आनंद प्रकाश बताते हैं कि अपने पिता के जमाने का कई सामान अब भी उनके घर में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद हैं. जिसमें पुराना टाइपराईटर, दीवार घड़ी, संदेश पत्र, टेलीफोन, सूक्ष्म दिखने वाला ताले जैसे कई सामान शामिल हैं. कहते हैं कि महज हाथ से चाभी देकर एक मात्र मौजूद कैसेट से निकलने वाला गाने की धुन – गम दिये मुस्तकीम, कितना नाजुक है दिल. ये न जाना, हाय – हाय ये कैसा जमाना' सुन कर अपने पिता की अर्जित धरोहर को जीवंत बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं. कहते है कि अब तो इस यंत्र का कोई पार्ट–पुर्जा भी तलाशने पर नहीं मिलता है. ग्रामोफोन की विशेषता का जिक्र करते हुए कहते है कि इसमें कोई खर्च ही नहीं है. न बैट्री का चक्कर है और न ही बिजली से मतलब. केवल हाथ से चाभी मात्र भर कर गाना का आनंद लिया जाता है. डॉ वर्मा की पत्नी ममता वर्मा, पुत्र जयंत कृष्ण, पुत्री वर्षा आनंद व मेघा आनंद का कहना है कि अपने दादा जी की अमानत को बवाये रखने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे. इनका कहना है कि देश में कभी चहेते रहे इस यंत्र को विलुप्त होने से बचाने की दिशा में सरकारी स्तर पर पहल की जानी चाहिए. इनका कहना है कि जिला में अब तक एक म्युजियम की स्थापना नहीं करायी जा सकी है.

अगर सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर म्युजियम का निर्माण करा दिया जाये तो ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ी के लिए सहेज कर रखा जा सकता है. इनका मानना है कि जिले में कई और भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऐसी वस्तुएं होंगी जो म्युजियम के लिए आकर्षण बन सकता है. जिले में हिंदी साहित्य के विकास को लेकर प्रयासरत गीतकार गीतेश ने जिले के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व प्रशासनिक महकमा से सीतामढी में एक म्युजियम की स्थापना कराने की मांग की है.■

ग्रामोफोन पर गाना सुनते डॉ आनंद व उनकी पत्नी

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
30 नवंबर-06 दिसंबर, 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

हाईकोर्ट की विचित्र गाथा, फ़ैसले के ऊपर भी सीनाजोरी

घोटालों की चिंता नहीं अवमानना की फिक्र!

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला उजागर करने वाले व्हिसिल ब्लोअर को हिफाजत और संरक्षण देने के बजाय उसे ही घेरे में लेने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को किस तरह तोड़ा-मरोड़ा जाता है उसका नायाब उदाहरण सामने आया है. यह प्रसंग दुखद और आश्चर्यजनक इसलिए भी है, क्योंकि इस सत्कर्म में खुद न्यायाधीश संलग्न हैं. पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला हाईकोर्ट के फैसले को ताक पर रख कर चलाया जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला दे रखा है कि पांच हजार करोड़ के घोटाले की जांच के बाद ही अवमानना मामले पर सुनवाई की जाएगी. लेकिन हजारों करोड़ के विकराल घोटाले की जांच की तरफ न्यायालय कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है. न्यायिक ईमानदारी और पारदर्शिता का यह बेजोड़ नमूना है. व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका में शिकायत की गई थी कि पांच हजार करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में जजों द्वारा हीलाहवाली और लापरवाही बरतने का आरोप लगा कर नंदलाल जायसवाल ने दो किताबें लिखी हैं. अवमानना याचिका जल विद्युत निगम के एक कर्मचारी की ओर से दाखिल की गई थी. यह याचिका घोषित तौर पर तो व्यक्तिगत थी, लेकिन इसके पीछे घोटाले में लिप्त आला अधिकारियों और उनके संरक्षक सरकारी कानूनविदों का हाथ था. यह बात आगे कथाक्रम में खुलती जाएगी. याचिका दाखिल होने के कुछ वर्ष बाद निगम खुल कर सामने आ गया और व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा (689/08.09.2010) भी दर्ज करा दिया. जायसवाल की गिरफ्तारी भी हो गई. पहले दाखिल हुई अवमानना याचिका और बाद में दर्ज हुए आपराधिक मुकदमे के सूत्र मिले हुए हैं. आपराधिक मुकदमे में उस व्यक्ति का बयान अहम बताया गया था, जिसने व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी. विचित्र किंतु सत्य यह है कि उस आपराधिक मुकदमे को हाईकोर्ट ने बेबुनियाद, तथ्यहीन और पूर्वाग्रह से ग्रस्त बता कर खारिज कर दिया है, इसके बावजूद दूसरी बेंच अवमानना याचिका पर सुनवाई जारी रखी है.

बहरहाल, यह सुनवाई जारी नहीं रहती, तो पांच हजार करोड़ से कहीं अधिक के घोटाले की गुत्थियों के सूत्र कैसे खुलते! इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पांच हजार करोड़ के घोटाले की जांच में हीलाहवाली करने वाले जजों के खिलाफ जांच करने से तो कन्नी काट रहे हैं, लेकिन अदालत की अवमानना उन्हें याद रहती है. जबकि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हैं. जजों पर संलिप्तता के आरोप हैं. हाईकोर्ट को उसके सबूत दिए जा रहे हैं, फिर भी उसकी जांच न कर अवमानना की सुनवाई जारी रखना आश्चर्यजनक है. अब्दुल मतीन, योगेंद्र कुमार संगल, केके मिश्र और उमानाथ सिंह जैसे वरिष्ठ जजों ने ऊर्जा घोटाले में जजों की संलिप्तता मामले को सुनने से ही इंकार कर दिया था. जज सत्येंद्र सिंह चौहान और विष्णु चंद्र गुप्त की बेंच ने थोड़ा साहस से काम लिया. जजों की संलिप्तता वाली नंदलाल जायसवाल की दोनों किताबों को बेंच ने बाकायदा रिकॉर्ड पर लाते हुए अवमानना याचिका की फाइल के साथ संलग्न (एनेक्स) कर दिया और 12 जुलाई 2013 का अपना फैसला रिजर्व कर लिया.

अवमानना का मामला अभी (28 अगस्त 2015 से) हाईकोर्ट के जज अजय लाम्बा और अशोक पाल सिंह की बेंच में चल रहा है. विडंबना यह है कि एक व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ चल रहे मामले में दूसरे पक्ष से पैरवी के लिए सरकारी वकीलों की फौज खड़ी होती रही है. जबकि इस मामले में सरकार पक्षकार नहीं है. आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद सरकारी वकीलों का आना तो बंद हो गया, लेकिन याचिकाकर्ता मायाराम वर्मा के आग्रह पर अदालत ने 11 हजार रुपये की फीस पर रत्नेश चंद्रा को वकील मनोनीत कर दिया. सरकारी खर्च पर रत्नेश चंद्रा ने याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर काम शुरू भी कर दिया. व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल अपने केस की बहस खुद करते हैं, उनके लिए अदालत की ओर से कोई कानूनी सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन याचिकाकर्ता को सुविधा देने की अदालत को बहुत चिंता थी. आप अदालत के उस मनोनयन आदेश को देखेंगे, तो आपको हैरत होगी जिसमें जज अजय लाम्बा और अशोक पाल सिंह लिखते हैं कि याचिकाकर्ता खर्च वहन करने में असमर्थ है, इसलिए 11 हजार रुपये की फीस पर रत्नेश चंद्रा को वकील मनोनीत किया जाता है. जज को वकील रत्नेश चंद्रा का मोबाइल नंबर भी याद रहता है. आदेश में वकील का मोबाइल नंबर (9415008400) उल्लेख करते हुए जजद्वय लिखते हैं कि रत्नेश चंद्रा को इस बारे में सूचित कर दिया जाए. याचिकाकर्ता के वकील के रूप में मनोनीत होते ही अदालत ने रत्नेश चंद्र को न्याय-मित्र (एमीकस क्यूरी) भी नियुक्त कर दिया और आनन-फानन में व्हिसिल ब्लोअर नंदललाल जायसवाल के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का आदेश देकर वारंट भी जारी कर दिया. ऐसी न्यायिक अंधेरगर्दी पर हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की प्रतिबद्धता जताने का प्रहसन करते रहते हैं.

बात अभी खत्म नहीं हुई है. न्यायिक विडंबना का एक और पहलू देखते चलिए. जज अजय लाम्बा के नेतृत्व वाले डबल बेंच के दूसरे जज अशोक पाल सिंह ने ही व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को आधारहीन, तथ्यहीन और बदले की भावना से ग्रस्त बता कर खारिज कर दिया है. अशोक पाल सिंह का यह फैसला 16 नवम्बर (2015) को जारी हुआ है. लिहाजा, अवमानना याचिका मामले में याचिकाकर्ता के लिए रत्नेश चंद्रा को सरकारी खर्चे पर वकील रखे जाने के आदेश पर अशोक पाल सिंह का हस्ताक्षर वरिष्ठ स्तर के दबाव की ओर स्पष्ट इशारा करता है.

ऊर्जा सेक्टर के घोटाले उजागर करने वाले व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ चलाया जा रहा अवमानना का मामला गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जज अब्दुल मतीन और योगेंद्र कुमार संगल ने आठ सितम्बर 2010 को यह फैसला दिया था कि पांच हजार करोड़ के ऊर्जा घोटाले की जांच संबंधी याचिका (संख्या- 5825-एमबी-2010) पर जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक अवमानना मामले की सुनवाई नहीं होगी. बेंच ने अदालत को यह साफ-साफ निर्देश दिया था कि लंबित याचिका पर फैसला आने के बाद ही अवमानना मामले को सूचीबद्ध किया जाए. लेकिन अदालत ने अदालत के ही आदेश को ठेंगा दिखा दिया है.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

Court No. - 25

Case :- CONTEMPT No. - 284 of 2008

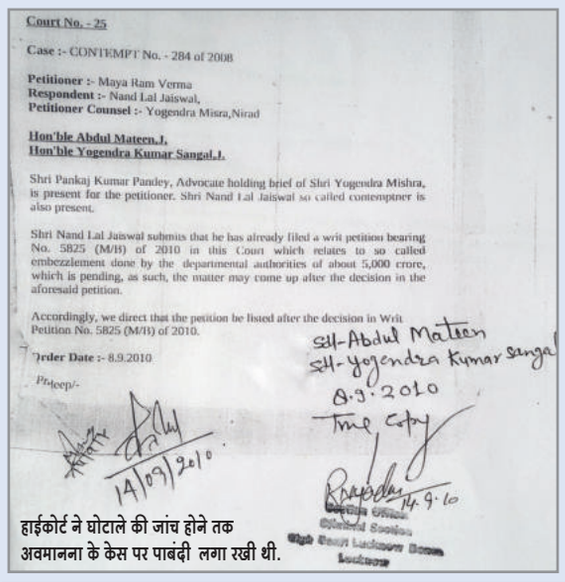

Petitioner :- Maya Ram Verma
Respondent :- Nand Lal Jaiswal,
Petitioner Counsel :- Yogendra Misra,Nirad

Hon'ble Abdul Mateen,J.
Hon'ble Yogendra Kumar Sangal,J.

Shri Pankaj Kumar Pandey, Advocate holding brief of Shri Yogendra Mishra, is present for the petitioner. Shri Nand Lal Jaiswal so called contemptner is also present.

Shri Nand Lal Jaiswal submits that he has already filed a writ petition bearing No. 5825 (M/B) of 2010 in this Court which relates to so called embezzlement done by the departmental authorities of about 5,000 crore, which is pending, as such, the matter may come up after the decision in the aforesaid petition.

Accordingly, we direct that the petition be listed after the decision in Writ Petition No. 5825 (M/B) of 2010.

Order Date :- 8.9.2010

Pradeep/-

Sd/- Abdul Mateen
Sd/- Yogendra Kumar Sangal
8.9.2010
True Copy
14/09/2010
14.9.10

हाईकोर्ट ने घोटाले की जांच होने तक अवमानना के केस पर पाबंदी लगा रखी थी.

Court No. - 7

Case :- CONTEMPT No. - 284 of 2008

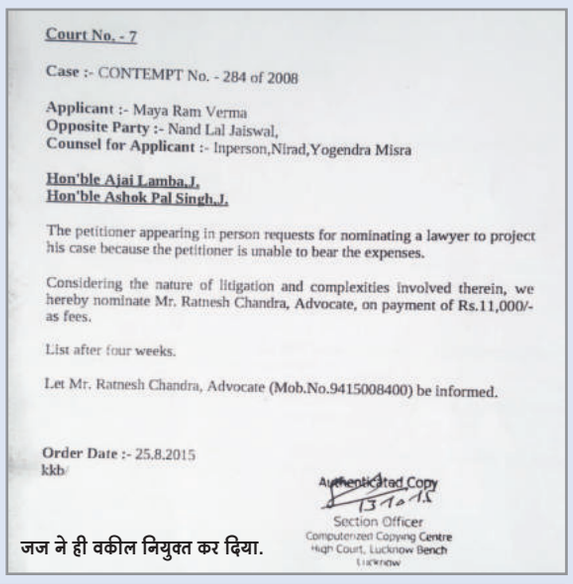

Applicant :- Maya Ram Verma
Opposite Party :- Nand Lal Jaiswal,
Counsel for Applicant :- Inperson,Nirad,Yogendra Misra

Hon'ble Ajai Lamba,J.
Hon'ble Ashok Pal Singh,J.

The petitioner appearing in person requests for nominating a lawyer to project his case because the petitioner is unable to bear the expenses.

Considering the nature of litigation and complexities involved therein, we hereby nominate Mr. Ratnesh Chandra, Advocate, on payment of Rs.11,000/- as fees.

List after four weeks.

Let Mr. Ratnesh Chandra, Advocate (Mob.No.9415008400) be informed.

Order Date :- 25.8.2015
kkb

Authenticated Copy
Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court, Lucknow Bench
Lucknow

जज ने ही वकील नियुक्त कर दिया.

घोटाले के आगे नतमस्तक लोकतंत्र

उत्तर प्रदेश का ऊर्जा घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है, जिसमें न केवल नेता और नौकरशाह बल्कि जज और सीबीआई के अधिकारी भी लिप्त पाए जाएंगे. यह आश्चर्यजनक है कि अरबों के ऊर्जा घोटाले की सीबीआई जांच का औपचारिक आदेश हो जाने के बाद भी उसे अदालत में दबाए रखा गया और उपकृत सीबीआई ने ही जांच करने से मना कर दिया. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में हुए हजारों करोड़ के घोटाले में सीजेएम अदालत के निर्देश पर 23 जनवरी 2008 को ही हजरतगंज थाने में प्रदेश के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय, आठ आईएएस अफसरों आरबी भास्कर, वीरेश कुमार, अशोक खुराना, राजकमल गुप्ता, जीबी पटनायक, कुंअर फतेह बहादुर सिंह, महेश गुप्ता और आलोक टंडन व उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के 19 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर (संख्याः 72/2008) दर्ज की गई थी. इनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 193, 409, 420, 465, 471, 471-ए, 120-बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. राजनीतिक दबाव और पुलिस की ढिलाई पर 20 जनवरी 2009 को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई. अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह त्वरित कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की. इस बीच 19 विवेचना अधिकारी (आईओ) बदल भी दिए गए. तत्कालीन बसपा सरकार के ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय ने सारी फाइल अपने पास मंगवा ली और उसे 2012 (बसपा सरकार के कार्यकाल) तक अपने पास दबाए रखा. पूर्ववर्ती सपा सरकार और फिर बसपा सरकार दोनों के कार्यकाल के घोटाले इस वजह से दबे रह गए. बसपा सरकार के समय तीस हज़ार करोड़ का बिजली घोटाला हुआ था. बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और निजी कंपनियों के साथ बिजली खरीद करार कर इस घोटाले को अंजाम दिया था. इस घोटाले के कई सबूत और दस्तावेजी प्रमाण लोकायुक्त एनके महरोत्रा को भी सौंपे गए थे. लोकायुक्त ने शिकायत को संज्ञान में भी लिया था, लेकिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने पांच निजी पावर ट्रेडिंग कंपनियों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया था. इस समझौते में पावर कॉरपोरेशन ने इन कंपनियों से महंगे दर से 5 हज़ार करोड़ यूनिट बिजली खरीदने का समझौता किया था. समझौते की शर्त यह थी कि पावर कॉरपोरेशन को उस दौरान सस्ती बिजली मिलने पर भी इसे अन्य कहीं से खरीदने का अधिकार नहीं होगा, चाहे वह केंद्रीय ग्रिड की एनटीपीसी और दूसरी कंपनियों से मिलने वाली सस्ती बिजली ही क्यों न हो. राज्य सरकार ने जिस तरह से बिजली खरीदी, उससे सरकारी खजाने को भीषण नुकसान पहुंचा. बसपा सरकार से पहले सपा के शासनकाल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 1600 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था. उस मामले में भी केवल जांच ही चलती रही, नतीजा शून्य ही रहा. मायावती के कार्यकाल के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कई सार्वजनिक बयानों में कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में मायावती सरकार 25 हजार करोड़ रुपये का घाटा छोड़कर गई है, लेकिन इस घाटे की वजह जानने की अखिलेश सरकार ने कभी कोशिश नहीं की. अकेले जेपी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए ही प्रदेश सरकार को 30 हजार करोड़ रुपये की चपत लगाई जा चुकी है. इसके लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष राजेश अवस्थी को निष्कासित भी होना पड़ा, लेकिन घोटाले को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम में भी 750 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, लेकिन इस घोटाले में लिप्त तत्कालीन सीएमडी आईएएस आलोक टंडन समेत अन्य अधिकारियों व अभियंताओं का कुछ नहीं बिगड़ा. सपा के मौजूदा शासनकाल में बिजली बिलों में फर्जीवाड़ा कर हजार करोड़ का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया. यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकृत बिलिंग कंपनी की मिलीभगत के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया.

व्हिसिल ब्लोअर की सुरक्षा या मजाक!

सुप्रीम कोर्ट भी व्हिसिल ब्लोअर की सुरक्षा को लेकर तमाम चिंता जताता रहता है, लेकिन जमीनी यथार्थ इसके विपरीत और भयावह है. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा घोटालों को उजागर करने वाले नंदलाल जायसवाल ने बड़ी कीमतें चुकाई हैं. जायसवाल विद्युत विभाग के ही कर्मचारी थे. ऊर्जा सेक्टर में फैले भ्रष्टाचार उजागर करने पर उनका जबरदस्त उत्पीड़न हुआ. उनके खिलाफ आपराधिक षडयंत्र तक हुए. फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए. कातिलाना हमला कराया गया. गिरफ्तार कर जेल में ठूंसा गया और नौकरी से निकाल बाहर कर दिया गया. अदालत ने भी पाया कि जायसवाल पर फर्जी मुकदमे लादे गए. अदालत के हस्तक्षेप पर वर्षों बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हुई. ऊर्जा सेक्टर में अरबों रुपये के घोटाले उजागर करने वाले व्हिसिल ब्लोअर को संरक्षण और सुरक्षा देने के बजाय उनका मुंह बंद करने की साजिशें अब भी जारी हैं. अभी 16 नवंबर को हाईकोर्ट ने जायसवाल के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मुकदमे को तथ्यहीन बताकर खारिज किया है. नंदलाल जायसवाल पर ऐसे आधा दर्जन फर्जी मुकदमे और दर्ज हैं. ■

व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

सड़कें और लोगों की उम्मीदें चकनाचूर

जनता गड्ढे में डालेगी वोट

सन्तोष देव गिरि

सड़कें किसी जिले अथवा नगर के विकास का आइना होती हैं, लेकिन जब यही आइना चकनाचूर हो जाए तो क्या कहेगें? पूर्वांचल की सड़कों की दशा भी इसी तरह चकनाचूर हो चुकी हैं. 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री के रूप में जब अखिलेश यादव ने शपथ ली थी, तो सूबे की जनता को व्यवस्था में सुधार के आसार नजर आने लगे थे. अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठित सरकार के मंत्रियों ने भी प्रदेश की बदहाली के लिए पूर्णरूपेण पूर्व की बसपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था तथा इस बदहाली से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया था. प्रमुख मुद्दा था सूबे की बेपटरी हो चुकी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का. हम बात कर रहे हैं खास तौर पर पूर्वांचल की सड़कों की जो कई राज्यों की सीमा को भी जोड़ती हैं. मसलन, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी और इलाहाबाद की सड़कें, जिनकी हालत देख लें तो कहना मुश्किल हो जाए गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढा. पूर्वांचल की सड़कों से आजिज लोग कहते हैं कि पांच साल में जब सड़कें गड्ढा बन गईं, तो हमारा वोट भी अब गड्ढे में ही जाएगा.

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव सड़कों की दशा देखने के बाद एक नहीं कई बार उसे ठीक करने की चेतावनी देते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ. एक बार तो शिवपाल ने यहां तक कह दिया था कि यदि गड्ढे मिले तो सम्बन्धित अधिकारी भी दोषी होंगे. मंत्री का इशारा मलाई काट रहे महकमे के अधिकारियों और ठेकेदारों की ओर था जो सड़क निर्माण में गुणवत्ता को ताक पर रख कर काम करते आए हैं. ऐसे अधिकारियों के प्रति मंत्री का लहजा काफी सख्त दिखने के बावजूद जमीन पर वह सख्ती नहीं दिखी.

सड़कें हर आम-ओ-खास से जुड़ी हैं, इसके बावजूद सड़कों की सेहत में सुधार नहीं हो रहा है. सड़कों को पैचलेस करने के नाम पर बिटुमिन की चोरी हो रही है. पूर्व में कई जिलों में मिलावटी बिटुमिन भी पाई गई. इसे खुद लोक निर्माण मंत्री ने भी स्वीकार किया और इसके लिए विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी. एक तरफ सड़क बनती है तो दूसरी तरफ उखड़ जाती है. गिट्टी में तारकोल का बेहतर मेल न होना सड़क निर्माण की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहा है. खासकर पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में सत्ताधारी दल के उन मंत्री, विधायकों के जिले की सड़कों की हालत भी खराब है जिनकी क्षेत्र में तूती बोलती है. मसलन, जौनपुर के मल्हनी विधायक और कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव. इसी जिले के मछलीशहर से विधायक एवं मंत्री जगदीश सोनकर, मिर्जापुर शहर के विधायक एवं राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया, सोनभद्र में राबर्टसगंज से सपा विधायक अभिनाश कुशवाहा, घोरावल से सपा विधायक रमेश चौबे, गाजीपुर के जमानियां से विधायक एवं मंत्री ओमप्रकाश सिंह, आजमगढ़ जहां से मुख्यमंत्री के पिता तथा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, सब जगह सड़कें बदहाल हैं. इन हस्तियों के जिले की सड़कों की हाल देखें तो रोना आता है. अगर ग्रामीण सड़कों की बात करें, तो वे बात करने लायक भी नहीं है. जब नगर की सड़कों की दशा दयनीय हो तो ग्रामीण सड़कों के हाल के बारे में कुछ पूछना ही नहीं. वाराणसी जिले से ही विधायक चुने गए और सरकार में लोक निर्माण एवं सिंचाई राज्यमंत्री बने सुरेन्द्र सिंह पटेल के जिले की सड़कों की हालत खस्ता है. ग्रामीण इलाकों की सड़कें तो बेहाल हैं ही नगर और जिले को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों की भी दशा बेहद चिंतनीय है. शायद ही कोई सड़क या मार्ग हो जिसे खोदा न गया हो. हल्की बरसात होने पर शहर की जिंदगी ठहर जाती है. बरसात के पानी से भर कर सड़क तालाब दिखती है, जिसमें चलकर आना-जाना लोगों की मजबूरी है. पिछले माह वाराणसी आए नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां भी न केवल नगर की सड़कों की हालत देख कर भौचक्के रह गए बल्कि उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ भी लगाई. कहना गलत नहीं होगा कि देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी नित्य काशी पधारते हैं, वह भी यहां की सड़कों की दशा को देख चकित रह जाते हैं. आश्चर्य की बात यह है कि यहां के सांसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं फिर भी यहां सड़कों की बदहाली दूर नहीं हो पा रही है. पूछे जाने पर अधिकारी टका सा जवाब देते हैं कि सड़कों के सुधार का कार्य तेजी के साथ चल रहा है. बात करें वाराणसी को जोड़ने वाली चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर या गाजीपुर की जनपद सीमा की तो सभी की कमोबेश एक जैसी ही दशा है. यातायात के दिनों-दिन बढ़ते दबाव के कारण सड़कें बिगड़ती ही जा रही हैं. सबसे बुरी दशा तो चार प्रांतों को जोड़ने वाले सोनभद्र जिले की सड़कों की है. जिसके मरम्मत के नाम पर प्रति वर्ष करोड़ों की रकम खर्च तो जरूर हो जा रही है, पर सड़क है कि सुधर ही नहीं रही. इतना जरूर देखने में आता है कि इस काम में लगे अधिकारियों और ठेकेदारों की दशा जरूर सुधरती चली जा रही है. आलम यह है कि सोनांचल सोनभद्र की लाइफ लाईन कहे जाने वाले वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग की पहचान हादसों वाली खूनी सड़क के रूप में हो गई है. इस सड़क पर होने वाले हादसों में हर वर्ष लगभग पांच सौ मौतों की संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे किलर रोड कह कर चिंता जताई थी. अब जब इस मार्ग को फोर लेन में करने की कवायद शुरू की जा चुकी है, तो सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या इससे इन हादसों को रोका जा सकता है? क्योंकि इस मार्ग पर जिस बेतहाशा तरीके से बड़े ओवर लोडेड वाहनों का जाल फैला हुआ है उसे देख तो यह नहीं लगता कि हादसों को रोका जा सकता है. सोनभद्र के ही मारकुंडी की पहाड़ी से लेकर अन्य भागों की सड़कें सड़क दिखती ही नहीं हैं. सूबे के राजस्व में सबसे ज्यादा आय देने वाले सोनभद्र की सड़कों की दशा सबसे ज्यादा दयनीय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. हालत यह है कि यहां पैदल चलने लायक भी सड़क नहीं है, सड़कों पर चकती वगैरह लगाकर काम चलाया जा रहा है. ■

मंत्री-संतरी का तो काम है कहना

उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई राज्यमंत्री सुरेन्द्र सिंह पटेल कहते हैं कि पूर्वांचल की सड़कों की दशा सुधरेगी, सरकार प्रदेश की सड़कों के प्रति गंभीर है. मंत्री आगे भी कहते हैं कि सड़क नगर की हो या गांव की, सभी मायने रखती हैं, इसलिए सभी को चमकाने के साथ उनके निर्माण में गुणवत्ता क्या होनी चाहिए इसका भी खास ध्यान दिया जा रहा है. इसमें लापरवाही और कोताही पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी को दंडित करने के साथ-साथ उससे ही इसकी भरपाई भी कराई जाएगी, ताकि सड़क निर्माण में कोई खिलवाड़ न करने पाए. मंत्री वाराणसी नगर की सड़कों की खराब दशा के लिए नगर निगम को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि इसके लिए नगर निगम को हिदायत दे दी गई है. मंत्री की हिदायत और उनका आश्वासन कहीं सड़क पर नहीं दिख रहा.

ज़िला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें नहीं हो पाईं फोर-लेन

प्रदेश सरकार ने सड़कों की बदहाली दूर करने के साथ-साथ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों को फोर-लेन करने की योजना बनाई थी. इसकी घोषणा भी की गई और कुछ जिलों में इसके लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चला. लोगों को लगा कि अब तो सड़कों की सूरत बदल ही जाएगी, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी. इस घोषणा के कई महीने बीत चुके हैं. काम कहीं शुरू भी नहीं हो पाया. फोर-लेन की बात तो दूर रही, जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों को गड्ढा-मुक्त तक नहीं किया जा सका.

feedback@chauthiduniya.com

घोटालों की चिंता नहीं, अवमानना की फिक्र!

पृष्ठ 17 का शेष

जज लगे रहे लीपापोती में

लखनऊ के पूर्व जिला जज केके शर्मा अकेले नहीं हैं जिन्होंने ऊर्जा घोटाले की लीपापोती में संदेहास्पद भूमिका अदा की हो. श्री शर्मा के खिलाफ तो जांच भी हो रही है, अन्य जजों के खिलाफ तो कुछ भी नहीं हुआ. विदेशी कंपनी के साथ मिलीभगत कर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पांच हजार करोड़ रुपये का घोटाला किए जाने के मामले में सीबीआई से जांच कराने की सरकारी अधिसूचना जारी हो जाने के बाद भी इन जजों ने सीबीआई से जांच नहीं होने दी. इस षडयंत्र में सीबीआई के अधिकारी भी शरीक रहे. विचित्र यह है कि पावर कॉरपोरेशन की विजिलेंस शाखा ने घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और स्टेट विजिलेंस ने भी कहा था कि पूरा प्रकरण गंभीर जांच की अपेक्षा करता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के तत्कालीन जज स्वनामधन्य जगदीश भल्ला और कमल किशोर ने विजिलेंस की सिफारिश को तकनीकी पड़ताल के लिए उन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दिया जो अरबों के घोटाले में लिप्त थे. हाईकोर्ट के तत्कालीन जज एसएचए रजा और आरडी शुक्ला की बेंच ने सीबीआई जांच के अपने ही पूर्व के फैसले के ऑपरेटिव पोर्शन को बदल डाला. जज डीके त्रिवेदी और नसीमुद्दीन की बेंच ने कानूनी पेचोखम में उलझा कर मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया. जज वीरेंद्र शरण व आरडी शुक्ला की बेंच ने एसएचए रजा वाली बेंच के विरोधाभासी फैसले को ही पकड़े रखा और जज रितुराज अवस्थी और अनिल कुमार शिकायतकर्ता का पक्ष सुने बगैर तारीख पर तारीख देते रहे. इन सारे जजों की संदेहास्पद भूमिका के बारे में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज रहे इम्तियाज मुर्तजा और विनय कुमार माथुर ने तो हद ही कर दी. उन्होंने याचिकाकर्ता नंदलाल जायसवाल को अंधेरे में रख कर उनकी जनहित याचिका खारिज कर दी. जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और जज श्रीनारायण शुक्ला की बेंच ने याचिकाकर्ता को शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दे रखा था. शपथ पत्र दाखिल करने के बाद नंदलाल जायसवाल सुनवाई की तारीख का इंतजार ही करते रह गए और उधर उनकी याचिका खारिज कर दी गई. जज इम्तियाज मुर्तजा और विनय माथुर के बेजा फैसले की शिकायत पर वह जनहित याचिका फिर से री-स्टोर की गई. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा उस जनहित याचिका को वापस कानूनी प्रक्रिया में लाने का निर्णय उन जजों और मौजूदा न्यायिक व्यवस्था पर करारे तमाचे की तरह साबित हुआ.

सुप्रीम कोर्ट के जज की सुप्रीम हरकत

तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा 30.01.2003 को मामले की सीबीआई से जांच कराने का बाकायदा शासनादेश जारी किया गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाईके सब्बरवाल एवं बीएन अग्रवाल की बेंच ने 13.07.2003 को केंद्र, सीबीआई और यूपी पावर कॉरपोरेशन को अंतिम मौका देते हुए प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया. लेकिन प्रति-शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया. केंद्र सरकार, सीबीआई और यूपी पावर कॉरपोरेशन की इस खुली नाफरमानी पर सख्त संज्ञान लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने मामले को ही खारिज कर दिया. वहीं ईमानदार सब्बरवाल बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे.

सीबीआई ने कैसे दिखाया ठेंगा

पांच हजार करोड़ के ऊर्जा घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की अधिसूचना जारी होने के बावजूद सीबीआई ने जांच करने से मना कर दिया. यह हैरतअंगेज हुकुमउदूली सीबीआई ने की और केंद्र व राज्य सरकार चुप बैठी रह गई. घोटाले की रकम इतनी बड़ी थी कि उसने राज्य व केंद्र सरकार में बैठे सियासतदानों, नौकरशाहों और सीबीआई के अधिकारियों तक को अपने प्रभावक्षेत्र में ले लिया. तभी सीबीआई ने सरकार की अधिसूचना तक को ताक पर रखते हुए कह दिया कि यह मामला जांच के उपयुक्त नहीं है. सीबीआई ने जांच से मना करते हुए इसे पुराना मामला बताया, फिर कहा कि घोटाले से संबन्धित जानकारियां नहीं दी जा रही हैं, फिर कहा कि सीबीआई के पास जांच की तकनीकी क्षमता नहीं है, फिर यह भी कहा कि इस घोटाले का कोई अंतरराष्ट्रीय प्रसार नहीं है. सीबीआई के ये सारे तर्क सफेद झूठ थे. पांच हजार करोड़ का ऊर्जा घोटाला दरअसल विदेशी कंपनी के साथ यूपी पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया था, लिहाजा इस घोटाले का अंतरराष्ट्रीय प्रसार है. घोटाले से सम्बद्ध जानकारियां और दस्तावेज सीबीआई को मुहैया कराए गए थे.

भारी-भरकम बिजली घोटाले

1. पावर कॉरपोरेशन में पांच हजार करोड़ का घोटाला. मायावती सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, पर जांच शुरू ही नहीं हुई. मौजूदा राज्य सरकार भी जांच के लिए प्रयासरत नहीं है.

2. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 1600 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ. इस मामले में पिछले छह साल से जांच ही चल रही है, पर नतीजा शून्य है.

3. विद्युत नियामक आयोग की शह पर जेपी समूह समेत निजी बिजली-घरानों को लाभ पहुंचाया गया. इससे करीब 30 हजार करोड़ रुपये की क्षति हुई. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश अवस्थी हटा दिए गए, पर घोटाले की जांच अभी फाइलों में ही बंद है.

4. जल विद्युत निगम में 750 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ. तत्कालीन एमडी आलोक टंडन समेत कई अभियंताओं के इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है. इस मामले में जांच जारी है. नतीजा कब आएगा, किसी को कुछ नहीं पता. ■

feedback@chauthiduniya.com

बाराबंकी से दिल्ली तक जाएगी "भारत-पाकिस्तान महासंघ बनाओ" संकल्प रथयात्रा

खंडित आज़ादी की पीड़ा से उबरने का बीड़ा

पाटेश्वरी प्रसाद

विखंडित आजादी की पीड़ा कम करने की कोशिश में भारत-पाकिस्तान और बांग्लादेश महासंघ स्थापित करने का अभियान उत्तर प्रदेश में जोर पकड़ रहा है. समाजवादियों के अभियान का लक्ष्य आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम मतदाताओं में अंतरंगता का खास माहौल बनाना भी है. डॉ. राम मनोहर लोहिया का भारत-पाकिस्तान महासंघ बनाने का यह सपना मौजूदा समय के लिए और भी प्रासंगिक बन गया है. उत्तर प्रदेश के कुछ खांटी समाजवादी इस अभियान को लेकर लगातार सक्रिय हैं और महासंघ की अवधारणा के पांच दशक पूरा होने पर बाराबंकी से दिल्ली तक भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश महासंघ बनाओ संकल्प रथ यात्रा निकाले जाने की तैयारी कर रहे हैं. दिसंबर महीने में यह यात्रा निकलेगी जो उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के गांधी भवन से चलकर नई दिल्ली के राजघाट तक जाएगी. इस यात्रा का नेतृत्व प्रसिद्ध समाजवादी नेता राजनाथ शर्मा कर रहे हैं. डॉ. लोहिया, मधुलिमये, जॉर्ज फर्नांडीस, राज नारायण, मुलायम सिंह यादव सरीखे समाजवादी नेताओं के साथ राजनाथ शर्मा समाजवादी आंदोलन में सक्रिय तौर पर हिस्सा लेते रहे हैं और आज भी समाजवादी मशाल से अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं.

इस सन्दर्भ में समाजवादी चिंतक राजनाथ शर्मा बताते हैं कि खंडित आजादी से दुखी डॉ. लोहिया उस आजादी के बाद ही इस प्रयास में लग गए थे कि भारत-पाकिस्तान महासंघ की स्थापना हो. कांग्रेस और पाकिस्तान के शासकों ने विषम स्थितियां बनाईं और दो राष्ट्र फिर कभी एक नहीं हो सके. महासंघ स्थापना के प्रयास की शुरुआत भारत विभाजन के तत्काल बाद और पाकिस्तान से हुए प्रथम युद्ध के पहले समाजवादी पुरोधा डॉ. राम मनोहर लोहिया ने जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, पीताम्बर दास के साथ मिल कर 12 अप्रैल 1964 को भारत-पाकिस्तान महासंघ की संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर की थी. हालांकि पाकिस्तान के प्रति डॉ. लोहिया का साफ विचार था कि पाकिस्तान के साथ संघ बने या फिर जंग लड़कर पाकिस्तान को पुनः भारत के साथ जोड़े जाने का प्रयास किया जाना चाहिए.

डॉ. लोहिया के इसी निर्देशन पर राजनाथ शर्मा ने दिसंबर 1965 में भारत पाकिस्तान एक करो (महासंघ बनाओ) अभियान के तहत दो दिवसीय सम्मेलन जनपद बाराबंकी में आयोजित किया था. सम्मेलन मे स्वयं डॉ. लोहिया और मधुलिमये को आना था. किसी कारणवश वे नहीं आ सके और पूर्व जस्टिस आनन्द नारायण मुल्ला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. इससे पूर्व राजनाथ शर्मा ने पं.दीनदयाल उपाध्याय से मिलकर भारत-पाक महासंघ की संभावना पर चर्चा की और उन्होंने सम्मेलन में शामिल होने की आशा भी व्यक्त की. मगर इसी वर्ष प्रयाग में कुंभ के दौरान विश्व हिन्दू समागम होने के चलते पं. दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम में नहीं आ सके. उस दो दिवसीय सम्मेलन का समापन लोकबंधु राज नारायण ने किया था.

प्रकरण यूं ही चलता रहा. सन 1975 में सम्पूर्ण क्रांति के आन्दोलन के द्वितीय चरण में जब राजनाथ शर्मा विधानसभा लखनऊ के समक्ष से गिरफ्तार किए गए और उन्हें इलाहाबाद के नैनी केंद्रीय कारागार में बंदी बनाया गया, तब उनके साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी बंदी थे. करीब 15-20 दिनों की जेल के दौरान राजनाथ और अटल जी के बीच महासंघ को लेकर विस्तृत वार्ता हुई. अटल जी इस महासंघ के निर्माण से सहमत थे. उन्होंने कहा कि डॉ. राममनोहर लोहिया ने इस महासंघ के लिए जो कोशिशें कीं उन्हें व्यवहारिक धरातल पर उतारने में समकालीन राजनीति, नेता और सत्ता आड़े आती है. देश का विभाजन ही एक अक्षम्य भूल है और इसके उत्तरदायी माफ नहीं किए जा सकते हैं. बाद की कोशिशें हुईं तो जरूर, पर इसमें भी सत्ता और स्वार्थ आड़े आती रही. भारत-पाक-बांग्लादेश महासंघ की परिकल्पना से ही स्वार्थी, क्षेत्रीय और जातीय राजनीति करने वाले सिहर जाते हैं और इस विषय को अप्रासंगिक कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं.

राजनाथ शर्मा का कहना है कि महासंघ के निर्माण से आपसी भेदभाव तो खत्म होगा ही साथ ही तीनों राष्ट्रों के सार्वजनिक जीवन, व्यापार, रोजगार और आर्थिक स्थिति में जो आशातीत बदलाव होंगे वह विश्व के लिए उदाहरण होगा. उन्होंने बताया कि गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट के तहत इस स्वप्न को साकार करने की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जोड़ा गया और कई आयोजन बाराबंकी, लखनऊ, नई दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर आयोजित किए गए. इस कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार रामबहादुर राय ने महासंघ के मुद्दे पर जनसत्ता में संपादकीय भी लिखा. वहीं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, मस्तराम कपूर, जयशंकर गुप्ता, इफ्तिखार गिलानी, कुर्बान अली, पाकिस्तान के समाचार पत्र नवा-ए-वक्त के संपादक फरीद अहमद किदवई जैसे बुद्धजीवियों ने भी महासंघ के प्रति अपना समर्थन जताया. महासंघ के मुद्दे पर आयोजित हुए सम्मेलनों में पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि रे, पूर्व रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडीस, पूर्व राज्यपाल बी. सत्य नारायण रेड्डी, रघु ठाकुर, एचएन शर्मा, पाकिस्तान दूतावास के राजनीतिक सलाहकार सैय्यद मोहम्मद रफीक अहमद, मजदूर नेता नूर अहमद, नरेन्द्र गुरु, कैप्टन अब्बास अली, सैयद सगीर अहमद, डॉ. हलीम, मौलाना कल्बे सादिक, सौलत अली, एसएस नेहरा, बहार यू बर्की सहित भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के तमाम बुद्धिजीवियों का नैतिक समर्थन और सक्रिय सहयोग रहा है. बावजूद इसके यह परिकल्पना निजी राजनीतिक स्वार्थों और धार्मिक, जातीय सोच के बीच पिस कर रह गई है.

राजनाथ शर्मा मानते हैं कि डॉ. लोहिया के देहांत के बाद महासंघ पर बड़े नेताओं का ध्यान कम हुआ और लोग उदासीन होते गए. राज नारायण से वैचारिक मतभेद के कारण जॉर्ज फर्नांडीस व मधुलिमये का साथ मिला. अटल बिहारी वाजपेयी के संग अखंड भारत और महासंघ की अवधारण पर चर्चा से फिर सक्रियता बढ़ी, लेकिन वह सक्रियता सरकार आते-आते धीमी पड़ गई. उप प्रधानमंत्री रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने महासंघ के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लंदन यात्रा के दौरान बीबीसी को दिए साक्षात्कार में महासंघ की प्रासंगिकता की बात कही. दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉ. महेशचन्द्र शर्मा अखंड भारत पर सन् 1987 से परिसंवाद आयोजित करते आ रहे हैं, जिसमें देश के जाने माने राजनीतिकों को शामिल कर महासंघ और अखंड भारत की प्रासंगिकता पर परिचर्चा होती है.

इस दिशा में सबसे अधिक सक्रियता सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने दिखाई. उन्होंने महासंघ और चीन के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते हुए अपनी बात को प्रमुखता से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखा. ऐसी दशा में राजनाथ शर्मा का मानना है कि बंटवारा तो वस्तुतः थके हारे नेताओं के कारण हुआ. बंटवारे की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही इससे किसी समस्या का कोई हल निकलने वाला था. ऐसा भी नहीं है कि जिन्ना बंटवारे के अकेले दोषी हैं. तात्कालिक स्थितियां और राजनीतिक स्वार्थों ने अखंड भारत को विभाजित कर दिया. इस विभाजन की भरपाई महासंघ के निर्माण से ही संभव है और इसके लिए तहे दिल से कोशिश की जानी चाहिए.

राजनाथ शर्मा यह उम्मीद करते हैं कि महासंघ के निर्माण पर ठोस पहल की बेहद आवश्यकता है. भारत-पाकिस्तान महासंघ बने इस मुहिम के 50 वर्ष पूरे होने पर दिसंबर महीने में निकाली जाने वाली संकल्प रथयात्रा के सन्दर्भ में गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिनों भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का महासंघ बनाओ अभियान के संयोजक राजनाथ शर्मा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल में वयोवृद्ध समाजवादी चिंतक सैय्यद सगीर अहमद, समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विशेष आमंत्रित सदस्य धनंजय शर्मा, सपा नेता मृत्युंजय शर्मा और युवा समाजवादी लेखक दीपक मिश्रा शामिल थे. शिवपाल सिंह यादव ने रथ यात्रा निकालने की योजना और महासंघ पर 50 वर्षों से अनवरत किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव सहित पूरा समाजवादी परिवार इस अभियान में साथ है. उन्होंने कहा कि महासंघ का मिशन जहां देश की सहिष्णुता और अखंडता को मजबूत करेगा वहीं भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा पर खर्च होने वाली राशि से तीनों देशों का आर्थिक ढांचा मजबूत बनेगा. शिवपाल बोले कि डॉ.लोहिया के महासंघ के सपने को पूरा करने में हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

हिन्द-पाक महासंघ पर जारी पहला साझा बयान

सन 1964 में पाकिस्तान में हिन्दुओं पर व्यापक रूप से आक्रमण किए जाने पर डॉ. राममनोहर लोहिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चर्चा की तथा दोनों ने 12 अप्रैल 1964 को हिन्द-पाक महासंघ के निर्माण के लिए वक्तव्य जारी किया. वह साझा वक्तव्य था, जहां तक हिन्दुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, ध्रुव विचार है कि नागरिकों के समान उनके जान माल की रक्षा हर हालत में होनी चाहिए. कोई घटना और तर्क ऐसा नहीं, जिसके सामने इस सत्य को झुकना जरूरी हो. जो राज्य अपने नागरिकों और नागरिक अपने पड़ोसियों को जीने का अधिकार न दिला सके, वह जंगली है. हमारा यह मत है कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान की पृथकता कृत्रिम है. दोनों सरकारों के साथ बिगड़ने का एक बड़ा कारण उनकी टूटी दृष्टि और टूटी-फूटी बातचीत है. हम चाहते हैं कि दोनों सरकारें टुकड़े-टुकड़े में बातचीत न करके सम्पूर्ण बातचीत खुले मन से करें. इससे समस्याओं का निराकरण हो सकेगा और पारस्परिक सद्भावना पैदा होकर हिन्द-पाक महासंघ किसी न किसी रूप में बनने का क्रम शुरू हो सकेगा.

जब महासंघ को मिला पाकिस्तान का समर्थन

जुलाई 2001 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की आगरा वार्ता के मौके पर दिल्ली में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का महासंघ बनाओ सम्मेलन गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ. जिसमें सबसे बड़ी सफलता तब प्राप्त हुई जब उस सम्मेलन में पाकिस्तानी दूतावास के राजनीतिक सलाहकार सैय्यद मोहम्मद रफीक अहमद ने महासंघ को जायज बताते हुए समर्थन किया और सम्मेलन में शामिल हुए. सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आज जरूरत दिलों को जोड़ने की है. पाकिस्तान की आवाम में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान से मैत्री संबंध बनाना चाहता है. इस सम्मेलन में बांग्लादेश के दूतावास से किसी व्यक्ति के न आने के बाद जब महासंघ की व्यवहारिकता की बात उन तक पता चली, तो उन्होंने दूरभाष द्वारा न आने का खेद व्यक्त किया और भविष्य में इस प्रकार के आयोजनों में सहभागिता की सहमति दी.

भारत-पाकिस्तान महासंघ का मूल प्रस्ताव

समाजवादी दल का राष्ट्रीय सम्मेलन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों से यह मांग करता है कि वे दोनों देशों के महासंघ के निर्माण पर गंभीरता से सोचें. देश के बंटवारे और कारणों के अलावा, एक तरफ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, दूसरी तरफ हिन्दू और मुसलमान की छोटी और स्वार्थी बुद्धि थी कि वे अपने घर को बनाकर परम स्वतंत्र और बेटोक सुख से रहें. घर अलग होने से अपनी स्वतंत्रता और सुख में कमी हुई. इस अनुभव के बाद संभावना बढ़ी है कि लोग दोनों की निरंकुश इच्छाओं को दबाकर संयम के साथ किसी हद तक मिलकर रहना चाहें. उदाहरण के लिए, महासंघ के संविधान में फिलहाल एक प्रावधान रह सकता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से एक पाकिस्तान का हो. महासंघ की पृष्ठभूमि में श्रीनगर घाटी अथवा संयुक्त बंगाल जैसे प्रश्न सुलझाना संभव हो सकता है. सम्मेलन की राय है कि महासंघ का सबसे जरूरी अधिकार एक नागरिक का हो. रण और विदेश नीतियां तथा यातायात, महासंघ के सर्वमान्य अधिकार हैं. (हिंदुस्तान-पाकिस्तान महासंघ पर 31 दिसंबर 1962 को समाजवादी दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में जारी प्रस्ताव)

हरीश को पटखनी देकर मुख्य सचिव पद पर शत्रुघ्न सिंह की तैनाती

-राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री हरीश रावत को मोदी सरकार ने पटकनी देकर शत्रुघ्न सिंह को मुख्य सचिव बनाया है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने उत्तराखंड के 13वें मुख्य सचिव के रूप में पद संभाला है. हरीश रावत अपने पसंदीदा अधिकारी पर इस कदर फिदा थे कि उसके रिटायर्ड होने के बाद भी उसे सेवा में बनाए रखना चाहते थे और हरीश की इसी मंशा ने राकेश शर्मा को पद पर बनाए रखा था. अपने कार्यों की वजह से चर्चा में रहने वाले शर्मा को पीएमओ ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और शत्रुघ्न सिंह की तैनाती को हरी झंडी दे दी. हरीश सरकार अपनी करनी से भई गति सांप छछूंदर जैसी कहावत चरितार्थ कर रही है. चर्चा है कि अपने अहम के लिए हरीश रावत ने राकेश शर्मा को नया पद सृजित कर प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के पद पर तैनाती सौंपी है. शर्मा को पद दिए जाने को उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने दाल मे कुछ काला होने की बात कहकर इसे चर्चा का विषय बना दिया है. 1983 बैच के आईएएस शत्रुघ्न सिंह ने पद संभालने के बाद कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शी प्रशासन और अवस्थापना सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिताओं में शामिल हैं. जन सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं. यहां के लोग प्रकृति के बीच रहते हैं और सरल स्वभाव के हैं. प्रशासन तंत्र को वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना है. खासतौर से उत्तराखंड में पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं. प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नियम के तहत करना है. यदि सब कुछ ठीक चला तो शत्रुघ्न सिंह का कार्यकाल दिसंबर 2016 तक रहेगा. पहली बार सृजित किए गए मुख्य प्रधान सचिव के पद पर प्रभावशाली व रिटायर्ड नौकरशाह राकेश शर्मा को तैनात किया गया. वह मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव होंगे. उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी को मुख्यमंत्री सचिवालय से सपोर्ट की जरूरत होती है और मैं उनकी पूरी मदद करूंगा. वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में जिस तरह फेरबदल किया गया उससे साफ है कि नौकरशाही की कमान मुख्यमंत्री सचिवालय के हाथों में रहेगी. केंद्र के अड़ंगे के चलते भले ही प्रदेश सरकार निवर्तमान मुख्य सचिव राकेश शर्मा को सेवा विस्तार देने में कामयाब न हो सकी हो, लेकिन नौकरशाही पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने सचिवालय में मुख्य प्रधान सचिव पद सृजित कर दिया. नए मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्य प्रधान सचिव पद के सृजन होने के बाद से ही नौकरशाही के बीच पावर सेंटर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. जिस तरह से शासन में बैठे अधिकारियों के कामकाज में बदलाव हुए उससे मुख्यमंत्री सचिवालय मजबूत दिखाई देने लगा है. नौकरशाही की कमान भले ही मुख्य सचिव के हाथों में हो, लेकिन काम के लिहाज से मुख्य प्रधान सचिव ने अपनी टीम में ऐसे अधिकारियों को शामिल कर लिया जिनके महकमे महत्वपूर्ण हैं. भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का कहना है कि राज्य में राकेश शर्मा हरीश रावत के लिए भले ही लाभप्रद सिद्ध हों, लेकिन जनता पर भार ही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का मानना है कि मुख्यमंत्री एक म्यान में दो तलवार रखने की कोशिश कर रहे हैं. विपक्ष के नेता अजय भट्ट सबसे सधी टिप्पणी की और कहा कि मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार है. एक और एक ग्यारह भी होता है. खींचतान की अवस्था में हानि की संभावना अधिक रहती है.

नवनियुक्त मुख्य प्रधान सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि शत्रुघ्न सिंह अनुभवी अधिकारी हैं और वह अच्छा शासन चलाएंगे. मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राकेश से उपजे मोह के प्रति भाजपा के अधिकांश नेताओं को दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है और अधिकतर नेताओं का मानना है कि हरीश रावत ने अपना हित साधने के लिए चर्चित अधिकारी के प्रति मोह और ईमानदार अधिकारी के प्रति अविश्वास प्रकट किया है. ■

आख़िरकार सरकार को घोषित करना पड़ा उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त

खेत सूखा, किसान भूखा, शासन रूखा

दीनबंधु क़बीर

उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र सूखे का शिकार बना है, लेकिन सरकारी तौर पर सूखा घोषित करने में प्रदेश सरकार ने अप्रत्याशित देरी की. बर्बादी के कगार पर खड़े करोड़ों किसानों को राहत की घोषणा के लिए ही लंबा इंतजार करना पड़ा. कोताहियां दोनों तरफ से हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ढीली पड़ी रही और केंद्र आंखें बंद किए रहा. केंद्र सरकार को पता है कि वह सूखे की अधिसूचना जारी कर प्रभावित राज्यों को दो सप्ताह के भीतर जानकारी भेजने का आदेश दे सकती है और जानकारी आते ही राहत कार्य शुरू हो सकता है.

उत्तर प्रदेश भीषण सूखे की चपेट में है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काफी विलंब के बाद प्रदेश के 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. किसानों को अंदेशा है कि जिस तरह पिछली प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत दी गई, वैसा ही इस बार भी हुआ तो किसानों के सामने आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. सरकार ने प्रदेश के उन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है जहां 60 प्रतिशत से कम बारिश हुई. 50 जिलों में सिर्फ बलरामपुर ऐसा जिला है, जहां 60 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई. इसके बावजूद यहां की 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हो गई, इस वजह से बलरामपुर जिले को भी सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. सूखाग्रस्त घोषित जिलों में 31 मार्च 2016 तक किसी भी तरह के राजस्व की वसूली नहीं की जाएगी. इन जिलों के किसानों से कर्ज भी नहीं वसूला जाएगा और जो किसान अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी. उत्तर प्रदेश में लगातार चौथी बार ऐसा हुआ है जब बारिश, ओलावृष्टि या सुखाड़ के चलते किसानों को फसल की बर्बादी देखनी पड़ी और भारी नुकसान उठाना पड़ा.

विडंबना यह है कि केंद्रीय मौसम विभाग ने महीने भर पहले ही आधे देश को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया था, लेकिन कर्नाटक को छोड़कर दूसरे सभी राज्यों ने इस प्राकृतिक आपदा को मान्यता देने में अनावश्यक देरी लगाई. पिछले महीने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओड़ीशा ने भी सूखे का ऐलान कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और तेलंगाना की सरकारें सोई रहीं. नियमानुसार जब तक राज्य सरकार किसी इलाके को सूखाग्रस्त घोषित नहीं करती और केंद्र नुकसान का जायजा नहीं ले लेता, तब तक वहां राहत कार्य शुरू नहीं हो सकते. इस देरी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल अप्रैल में खराब फसल के मुआवजे की रकम 50 प्रतिशत बढ़ा दी थी.

उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र सूखे का शिकार बना है, लेकिन सरकारी तौर पर सूखा घोषित करने में प्रदेश सरकार ने अप्रत्याशित देरी की. बर्बादी के कगार पर खड़े करोड़ों किसानों को राहत की घोषणा के लिए ही लंबा इंतजार करना पड़ा. कोताहियां दोनों तरफ से हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ढीली पड़ी रही और केंद्र आंखें बंद किए रहा. केंद्र सरकार को पता है कि वह सूखे की अधिसूचना जारी कर प्रभावित राज्यों को दो सप्ताह के भीतर जानकारी भेजने का आदेश दे सकती है और जानकारी आते ही राहत कार्य शुरू हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. सरकार उस इलाके को सूखाग्रस्त मानती है, जहां वर्षा सामान्य से 20 प्रतिशत कम होती है. जिन इलाकों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 50 प्रतिशत या इससे अधिक कमजोर हो, उन्हें भीषण सूखाग्रस्त कहा जाता है. इस परिभाषा की कसौटी पर कसें, तो देश के 614 में से 302 जिले सूखे या भीषण सूखे का संकट झेल रहे हैं. फिलहाल कुल 18 राज्यों के 66 करोड़ लोगों के सिर पर संकट मंडरा रहा है. चिंता की बात यह है कि सूखे की मार उन इलाकों में पड़ी है, जहां जमीन बहुत उपजाऊ है. वहां राहत पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है कि किसान समय रहते अगली फसल की तैयारी कर सकें.

देश में इस बार सबसे ज्यादा सूखा उत्तर प्रदेश में पड़ा है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के 31 जिलों में 50 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है. पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी, सूखे की मार चारों ओर है. अक्टूबर में आमतौर पर धान की फसल कटने को तैयार रहती है, लेकिन पानी की कमी से फसल का बुरा हाल हुआ, खेत सूख गए. उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली भी नहीं आती कि किसान ट्यूबवेल या अन्य साधनों से सिंचाई कर पाएं. सिंचाई के लिए किसान महंगे डीजल का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं. आप ग्रामीण इलाकों का जायजा लें तो पाएंगे कि न तो नहर में पानी है और न ही पिछले साल की खराब हुई फसल का सरकार ने कोई मुआवजा दिया है. जबकि सरकार दावा करती है कि राज्य की नहरों का पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया जा रहा है. सरकार ने यह भी दावा किया था कि किसानों की फसल न सूखे, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं. लेकिन सरकार के दावे और नहरों में पानी दोनों ही सूखा रहा. यूपी के जिन किसानों ने धान की खेती की थी, अक्टूबर में फसल कटने को तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश नहीं होने और नहरों में पानी नहीं होने से फसलें सूख गईं. बिजली के इंतजार में नलकूप भी सूखे पड़े रहे.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूखाग्रस्त घोषित जनपदों के जिलाधिकारियों को सूखे से निपटने के लिए बनाई गई कार्य योजना के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा राजस्व, सिंचाई, पंचायतीराज, ऊर्जा, ग्राम्य विकास, कृषि, खाद्य एवं रसद, समाज कल्याण, संस्थागत वित्त, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, पशुधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, जल निगम, मत्स्य एवं उद्यान विभागों को भी सूखाग्रस्त जनपदों में सूखे से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए राहत कार्य करने और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को विशेष रूप से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है. मौसम विभाग के वर्षा के आंकड़ों का विस्तृत परीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि पूरे प्रदेश में जून से लेकर 30 सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण 53.50 प्रतिशत वर्षा हुई. 33 जनपदों में 40 से 60 प्रतिशत तथा 16 जनपदों में 40 प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई. समिति द्वारा भारत सरकार के सूखे के सम्बन्ध में जारी गाइड-लाइन में उल्लिखित इस तथ्य पर भी विशेष रूप से विचार किया गया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की सम्पूर्ण अवधि में सामान्य के सापेक्ष 75 प्रतिशत से कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यूपी के सूखाग्रस्त घोषित ज़िले

उत्तर प्रदेश के इन 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है: संत रविदासनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, बांदा, प्रतापगढ़, चंदौली, इटावा, बस्ती, बागपत, जौनपुर, फैजाबाद, गोंडा, कन्नौज, बाराबंकी, संतकबीरनगर, झांसी, जालौन (उरई), गोरखपुर, हाथरस, एटा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मऊ, उन्नाव, रामपुर, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, लखनऊ, देवरिया, मैनपुरी, महराजगंज, आगरा, औरैया, पीलीभीत, अमेठी, महोबा, रायबरेली, कुशीनगर, कानपुर देहात, कौशांबी, फतेहपुर, अंबेडकरनगर और बलरामपुर.

महीने भर पहले योगेंद्र ने कहा था, सुखाड़ घोषित हो

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिल कर योगेंद्र यादव ने पिछले महीने ही प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की थी. उन्होंने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था. पत्र में कहा गया था कि राज्य में सूखे की स्थिति के बारे में कई सटीक सूचनाएं सत्ता तक नहीं पहुंच पातीं. सूखे का हाल यह है कि इस राष्ट्रीय आपदा का केंद्र बिन्दु उत्तर प्रदेश ही है. इस बार उत्तर प्रदेश में औसत से 45 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. वर्षा की कमी से देश में सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में से 17 उत्तर प्रदेश से हैं. प्रदेश के कई इलाकों में लगातार दूसरे या तीसरे वर्ष सूखा पड़ रहा है. एक बहुत बड़े इलाके में खरीफ की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है. ज्यादातर इलाकों में किसान रबी की फसल बोने की स्थिति में भी नहीं हैं. पीने के पानी का संकट है. लोग पशुओं को बेच रहे हैं या यूं ही लावारिस छोड़ दे रहे हैं. प्रदेश में आपदा की इस घड़ी में सरकारी तंत्र सूखे के शिकार किसान और मजदूरों को मदद पहुंचाने में असमर्थ रहा है. प्रदेश सरकार ने किसानों से मालगुजारी न वसूलने का फैसला लिया, लेकिन यह कदम महज प्रतीकात्मक साबित हुआ. प्राकृतिक आपदा के मारे किसानों को मुआवजा तो दूर पिछली फसलों का मुआवजा भी नहीं मिल पाया. खेती में मनरेगा का इस्तेमाल भी नहीं के बराबर है. जिन लोगों को सस्ते अनाज की सबसे ज्यादा ज़रूरत है, उनमें से अधिकांश लोग उस राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं. कुल मिलाकर प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है. जानवरों के लिए तो यह सूखा अकाल में बदलता ही जा रहा है, अगर सरकार की ओर से जल्द ही कुछ प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह भी आशंका है कि बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में सबसे गरीब वर्ग के लिए अकाल की स्थिति बन सकती है. पत्र में यह मांग की गई थी कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए सरकार को पूरे प्रदेश में सूखे की तुरंत घोषणा करनी चाहिए, ताकि सूखा राहत का काम शुरू हो सके. कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने काफी पहले घोषणा कर दी, जबकि वहां सूखे की स्थिति इतनी भयावह नहीं थी. प्रदेश सरकार ने पिछले साल ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए मुआवज़े की घोषणा की थी, लेकिन यह मुआवज़ा कुछ ही गांवों तक पहुंच पाया. इसमें भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आईं. फसलों के नुकसान और मुआवजे की राशि तय करने की उत्तर प्रदेश में अपनाई गई प्रक्रिया भी व्याधिग्रस्त पाई गई. फसलों के नुकसान का जायजा पारदर्शी तरीके से होना चाहिए था और इसके लिए किसकी फसल को कितना नुकसान हुआ, यह सूची ग्रामसभा के सामने पेश की जानी चाहिए थी. रबी फसल के दौरान अतिवृष्टि और अब खरीफ फसल के दौरान सूखे के कारण किसानों ने इन फसलों के लिए जो कर्ज लिया था, वह डूब चुका है. किसान पुराने बकाया कर्ज की अदायगी में भी असमर्थ है. कर्ज के बोझ में दबा किसान आत्महत्या को विवश न हो इसलिए यह जरूरी है कि किसानों के तमाम खेती संबंधी और व्यक्तिगत ऋणों का पुनर्निर्धारण हो. योगेंद्र यादव ने यह मांग की थी कि जिन इलाकों में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, वहां पिछली दोनों फसलों का ऋण माफ कर दिया जाए. किसानों के बकाया कर्ज का ब्याज माफ़ कर दिया जाए. बकाया कर्ज की किश्तों की अदायगी मुल्तवी कर दी जाए. किसानों को सरल, सुगम और समयानुसार बैंक कर्ज उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वह साहूकारों के चंगुल में फंसकर प्रतिमाह 5 से 10 प्रतिशत ब्याज देने को मजबूर न हो. इसके अलावा मनरेगा के तहत राज्य के हर सूखाग्रस्त जिले में हर गांव में काम उपलब्ध करवाया जाए, चाहे उसकी औपचारिक मांग हुई हो या नहीं. मनरेगा के काम को भूमि और पानी संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि भविष्य में सूखे का सामना करने की क्षमता विकसित हो सके. काम के पंद्रह दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाए, इसमें किसी भी तरह की देर होने पर दोषी व्यक्ति को सजा दी जाए. सूखे के चलते गांवों में गरीबों के खान-पान पर असर पड़ रहा है. सूखे से खाद्यान्न की कमी और अकाल जैसे हालात न उत्पन्न हों, इसके लिए जरूरी है कि राशन व्यवस्था के जरिए जरूरतमंद लोगों तक सस्ता खाद्यान्न पहुंचाया जाए. लेकिन राज्य की सार्वजनिक आपूर्ति व्यवस्था यह करने में पूरी तरह से असमर्थ है. लाल कार्ड, पीले और सफेद कार्ड वितरित करने की व्यवस्था में कोई न्यायसंगत आधार दिखाई नहीं देता. हर गांव में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को पीला कार्ड दिया गया है, जिसके कारण वे सस्ते खाद्यान्न से वंचित हैं. चूंकि सरकार के लिए तुरंत इन कार्डों का पुनर्वर्गीकरण संभव नहीं है, इसलिए सूखाग्रस्त इलाको में सभी परिवारों को सूखे की अवधि के दौरान 60 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए. इस दौरान उनसे इस खाद्यान्न का वही दाम लिया जाए, जो कि लाल कार्ड धारकों से लिया जाता है. जिन परिवारों के पास कोई भी कार्ड नहीं है, उन्हें भी सूखे के दौरान यही सुविधा एक अस्थायी प्रमाण पत्र के माध्यम से दी जाए. हाल ही में तेलंगाना सरकार ने एक शासनादेश के जरिए आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को दिए जाने वाली मुआवजे की एक सुसंगत व्यवस्था बनाई है. योगेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि प्रदेश सरकार भी ऐसा ही एक आदेश जारी कर व्यवस्था में सुधार कर सकती है. नई व्यवस्था के तहत आत्महत्या के शिकार परिवारों की पहचान में तकनीकी औपचारिकताओं को खत्म किया जाना चाहिए. जमीन जोतने वाले भूमिहीन परिवारों को भी इस मुआवजे का लाभ मिलना चाहिए. मुआवजे में परिवार के बकाया कर्ज को माफ़ करने, तात्कालिक राहत राशि, विधवा के लिए रोजगार और बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए.

इस समय पूरे प्रदेश में मवेशियों के लिए भारी आपदा की स्थिति है. गेहूं की पिछली फसल अतिवृष्टि से खराब हो गई, जिसके कारण चारा भी बर्बाद हो गया था. अब खरीफ की फसल सूख जाने की वजह से ज़हरीली हो रही है. सूखा जहरीला चारा खाकर जानवरों के मरने की खबर आ रही है. जो परिवार बाहर से महंगा चारा खरीदकर अपने जानवरों को नहीं खिला सकते, वह इस विपदा की स्थिति में मजबूर होकर जानवरों को औने-पौने दाम पर बेच रहे हैं, या फिर उन्हें गांव के बाहर छोड़ दे रहे हैं. चारों ओर अफरा-तफरी मची है. सरकार को बिना देर किए महाराष्ट्र की तर्ज़ पर चारा छावनी बनानी चाहिए. इन चारा छावनियों में सैकड़ों मवेशियों को एक साथ रखकर सरकार की ओर से चारा और पानी उपलब्ध किया जाना चाहिए. इस काम में स्वयंसेवी संगठनों, गौशालाओं और अन्य पशुपालक संगठनों को शामिल किया जा सकता है. सूखाग्रस्त इलाकों में तालाब और पानी के अन्य स्रोत सूख गए हैं. इसलिए इंसान और मवेशी, दोनों पानी के लिए नलकूपों पर निर्भर हैं. लेकिन प्रायः हर गांव में कई नलकूप छोटी-मोटी मरम्मत के अभाव में काम नहीं कर रहे हैं. इससे गांववासियों, खास तौर पर औरतों को, बेहद कष्ट उठाना पड़ रहा है. योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार एक मिशन की तरह पूरे प्रदेश में नलकूपों की मरम्मत का काम सम्पन्न कराए और बोरवेल या ट्यूबवेल चला कर सिंचाई करने के लिए बिजली मुहैया कराए. ■